राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 7 अंक 240

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, बुधवार, 7 फरवरी, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर के साथ निर्यातक भी बनेगा भारत >> 10

जागरण विशेष

कारीगरों की आर्थिकी सुधार रहा घड़ा क्लस्टर

मोगा: पारंपरिक विधि से मिट्टी के बर्तन बनाने वालों की तकनीक और बाजार तक पहुंच बनाकर घड़ा क्लस्टर उनके जीवन की आर्थिकी बदल रहा है। ● पेज-7

संपादकीय

राजनीतिक अनिश्चितता से घिरा पाकिस्तान: पाकिस्तानी सेना ने वे सभी दांव चले हैं, जिनसे लोकप्रिय होने के बाद भी इमरान खान की पार्टी सत्ता की दौड़ से बाहर हो जाए।

विवेक काटजू का आकलन।

अयोध्या के बाद आगे क्या: काशी और मथुरा के मामले हल होने चाहिए, लेकिन इसी के साथ देश को मंदिर-मस्जिद के विवादों से बाहर भी निकलना चाहिए। **राजीव सचान** का आलेख। ● पेज-8

विमर्श

परीक्षाओं को कदाचार मुक्त करने का प्रयास: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 का मकसद देश में सभी तरह की सरकारी परीक्षाओं में किसी भी किस्म की गड़बड़ी पर लगाम लगाना है। अभिषेक कुमार सिंह का विश्लेषण।

भाजपा के मातृशक्ति वंदन से दुविधा में कांग्रेस: धामी सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए उठाए जा रहे कदम कांग्रेस के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। विकास धूलिया की उत्तराखंड डायरी। ● पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

सेहत भरे जीवन का

सेहत का सार पारंपरिक उपचार

त्वचा को नुकसान तो नहीं!

● पेज-13

पेपर लीक कानून के दायरे से बाहर रहेंगे विद्यार्थी और अभ्यर्थी पेज>>3

एससी-एसटी कोटे में कोटे पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ मंथन पेज>>6

मथुरा में केशव देव मंदिर तोड़ बनाई ईदगाह, एएसआइ का जवाब बनेगा साक्ष्य

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामला

जागरण टीम, आगरा

- आगरा मंडल के पुरातत्व विभाग ने वादी को आरटीआइ में दिया जवाब
- वादी ने सर्वोच्च न्यायालय में भी आरटीआइ के जवाब की प्रति लगाई

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में आगरा मंडल के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की एक स्वीकारोक्ति न्यायालय में हिंदू पक्ष के लिए मजबूत साक्ष्य बनेगी। दरअसल, एक आरटीआइ के जवाब में एएसआइ ने जानकारी दी कि औरंगजेब ने मथुरा में केशव देव मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद ईदगाह का निर्माण किया। 29 जनवरी को यह जवाब सुप्रीम कोर्ट में 'ईदगाह का कोर्ट सर्वे' मामले में चल रही सुनवाई में वादी बनने के लिए दायर किए वाद में लगाया गया है। इससे पहले, इसी जवाब को मथुरा न्यायालय में दायर एक वाद में साक्ष्य के तौर पर पिछले साल लगाया जा चुका है।

अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने एक वर्ष पूर्व मथुरा सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया था। उन्होंने दावा किया था कि शाही मस्जिद ईदगाह ही श्रीकृष्ण जन्मस्थान का मूल गर्भगृह है,इसे हिंदुओं को लौटाया जाए। दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने आरटीआइ पर एएसआइ से मिले जवाब को लगाया। इसमें बताया गया कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद ईदगाह का निर्माण किया था। नवंबर 1920 में विभाग ने प्रकाशित अपने गजट में भी इसका उल्लेख किया है। अजय सिंह ने यह आरटीआइ मथुरा न्यायालय में वाद दायर करने से पहले पिछले साल लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रंजना अग्निहोत्री आदि के वाद पर 14 दिसंबर, 2023 को शाही मस्जिद ईदगाह का कोर्ट कमीशन सर्वे कराने का आदेश दिया।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह। जागरण आर्काइव

हमें ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। इसलिए इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है। कोर्ट में यदि विपक्षी कोई तथ्य दाखिल करेंगे तो हम उसका जवाब प्रस्तुत करेंगे। -तनवीर अहमद, सचिव, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी

जामा मस्जिद-केशव देव विग्रह प्रकरण में अब 12 को सुनवाई

जासं, आगरा : जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव के विग्रह दबे होने के मामले में मंगलवार को बहस के दौरान जामा मस्जिद पक्ष ही उपस्थित हुआ। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। लघुवाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 12 फरवरी नियत की है। यह वाद योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने लघुवाद न्यायालय में दायर किया था। याचिका में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और जामा मस्जिद इंतेजामिया कमेटी को प्रतिवादी बनाया है।

मस्जिद पक्ष का दावा- बिना अर्जी जिला जज ने दिया पूजा का अधिकार

प्रयागराज: वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तलगृह में पूजा का अधिकार देने वाले तत्कालीन जिला जज के आदेश के विरुद्ध दायर अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को दो घंटे सुनवाई हुई। (पेज-5)

लाक्षागृह की बढ़ाई गई सुरक्षा, खुफिया विभाग भी सतर्क

बागपत : उत्तर प्रदेश में बागपत के बरनावा के प्राचीन टीले को लेकर 53 वर्ष बाद हिंदुओं के पक्ष में आए फैसले के दूसरे दिन महाभारतकालीन लाक्षागृह पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। (पेज-13)

जिस भूमि के लिए हेमंत सोरेन गिरफ्तार, उसे लौटाने का आदेश

रांची : ईडी जिस रांची जमीन घोटाला मामले की जांच कर रही है और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, उस भूमि को रांची के शेड्यूल एरिया रेगुलेटरी कोर्ट ने मूल मालिक को लौटाने का आदेश 29 जनवरी को ही दे दिया था। इधर, ईडी ने हेमंत को पूर्व राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के सामने बैठाकर पूछताछ की। (पेज-6)

अंडर-19 विश्व कप : भारत लगातार पांचवीं बार फाइनल में

नई दिल्ली : भारत ने अंडर-19 विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को दो विकेट से हरा दिया। भारत को जीत के लिए 245 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने आठ विकेट खोकर सात गेंद शेष रहते प्राप्त कर लिया। पांच बार की चैंपियन भारतीय टीम रिकार्ड नौवीं और लगातार पांचवीं बार अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। (पेज-12)

आप नेताओं के ठिकानों पर ईडी के छापे

दिल्ली जल बोर्ड घोटाला ▸ सीएम के निजी सचिव व आप सांसद गुप्ता के आवास की भी ली तलाशी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मनी लांड्रिंग से जुड़ा है मामला, 38 करोड़ के कांट्रैक्ट में 21 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप
- ईडी ने कहा, बढ़ी दरों पर दिया गया डीजेबी का ठेका, फिर ठेकेदार से रिश्वत वसूली
- दावा - वसूली गई राशि में से बड़ा हिस्सा आप के चुनावी में फंड में इस्तेमाल किया गया
- तत्कालीन चीफ इंजीनियर, ठेकेदार की हो चुकी गिरफ्तारी

दिल्ली शराब घोटाले के बाद ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में मनी लांड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार समेत दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता, सीए पंकज मंगल व दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ अन्य लोगों के करीब दर्जनभर ठिकानों की तलाशी ली।

दिल्ली जल बोर्ड के 38 करोड़ रुपये के कांट्रैक्ट में 21 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है और सीबीआइ इसकी पहले से जांच कर रही है। आरोप है कि डीजेबी टेंडरिंग प्रक्रिया में घोटाले की राशि का एक बड़ा हिस्सा चुनावी फंड के रूप में आम आदमी पार्टी को दिया गया था। उधर, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि आप नेताओं के यहां ईडी के यह छापे राजनीतिक दल को डराने के उद्देश्य से मारे जा रहे हैं। ईडी के एक अधिकारी के अनुसार एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 38 करोड़ रुपये का दिल्ली जल बोर्ड का ठेका लिया था। दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने ये जानते हुए कि एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर तकनीक रूप से मापदंडों पर खरी नहीं है, फिर भी उसे ठेका दे दिया। जांच में पाया गया कि डीजेबी का ठेका अत्यधिक बढ़ी दरों पर दिया गया था ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। इस मामले में जगदीश कुमार व ठेकेदार अनिल अग्रवाल को ईडी 31 जनवरी को ही गिरफ्तार कर चुकी है। एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने सोमवार को इन दोनों की हिरासत की अवधि पांच दिन और बढ़ा दी थी। उनके अनुसार 38 करोड़ रुपये के ठेके में से काम के लिए 17 करोड़ रुपये खर्च किए गए और बाकी के 21 करोड़ रुपये आपस में बांट लिए गए और इनके फर्जी बिल दिखा दिए गए। (पेज-2 भी देखें)

नई दिल्ली में मंगलवार को आप के राज्यसभा सदस्य एनडी गुप्ता के आवास पर ईडी की छापेमारी के दौरान सुरक्षाकर्मी। प्रेट्र

ईडी के 23 अधिकारियों ने मेरे निजी सहायक बिभव कुमार और पार्टी के राज्यसभा सदस्य एनडी गुप्ता के आवास पर 16 घंटे तक छापेमारी की लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आप को कुचलने और हमें परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देश कानून और संविधान से चलता है, यह किसी की बपौती नहीं है। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं और वे इस तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। - अरविंद केजरीवाल, सीएम दिल्ली एवं आप संयोजक

अरोड़ा ने नकद में रिश्वत ली

ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जगदीश कुमार अरोड़ा ने नकद में रिश्वत की रकम ली थी और उसे बिभव कुमार, शलभ कुमार और पंकज मंगल तक पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि रिश्वत की इसी रकम की लेनदेन के सुबूत जुटाने के लिए छापा मारा गया। ईडी ने छापे में घोटाले से संबंधित अहम दस्तावेज बरामद होने का दावा किया है। इसके आधार पर अन्य आरोपियों को जल्द ही पूछताछ के लिए समन किया जाएगा। उधर, आप नेता व कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि आबकारी नीति मामले में ईडी को पिछले दो वर्ष की जांच में एक भी सुबूत नहीं मिला है। जो बयान आरोपितों ने कैमरे के सामने दिए हैं, उनकी रिकार्डिंग डिलीट की जा रही है। आबकारी नीति मामले से जुड़े गवाहों और आरोपितों के बयान जांच एजेंसी ने बलपूर्वक और धमकी देकर दिलवाए हैं। केंद्र सरकार ईडी के छापे से पार्टी को डराने और चुप कराने की कोशिश कर रही है।

शरद पवार को झटका, अजीत को मिली पार्टी और चुनाव चिह्न

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने राकांपा को लेकर किया बड़ा फैसला
- शरद पवार से नई पार्टी के नाम का मांगा प्रस्ताव, समाजवादी पार्टी और शिवसेना की तर्ज पर आया निर्णय

पार्टी पर दावे की लड़ाई में शरद पवार को झटका लगा है। लंबी सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने भतीजे अजीत पवार के गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) करार दिया है। साथ ही उन्हें ही पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न घड़ी दोनों देने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही शरद पवार से अपने लिए पार्टी का नया नाम बुधवार को तीन बजे तीन विकल्पों के साथ मुहैया कराने को कहा है।

शरद पवार और अजीत पवार के बीच चल रही लड़ाई को लेकर यह फैसला छह महीने से ज्यादा समय से लगभग दस सुनवाई के बाद दिया है। जिसमें आयोग ने दोनों ही पक्षों से पार्टी के अपने अधिकारों को लेकर सुबूत पेश करने को कहा था। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने अपने-अपने पक्ष में विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों के शपथ पत्र सौंपे थे। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधानसभा, विधान परिषद के साथ ही लोकसभा व राज्यसभा के पार्टी के सदस्यों के समर्थन के आधार पर अपना फैसला सुनाया। आयोग ने समाजवादी पार्टी और शिवसेना पर अधिकारों से जुड़े विवाद में भी इसी आधार पर फैसला दिया था। आयोग की ओर से दिए गए 141 पन्नों के फैसले में बताया गया है कि अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र में पार्टी के 41 विधायक, विधान परिषद के पांच सदस्य, नगालैंड के सभी सात विधायक, झारखंड से एक, लोकसभा के दो और राज्यसभा के एक सदस्य ने समर्थन, जबकि शरद पवार के समर्थन में महाराष्ट्र के 15 विधायकों के साथ ही विधान परिषद के चार सदस्य, केरल के दो विधायक और लोकसभा के चार व राज्यसभा के तीन सदस्यों ने शपथ पत्र दिया था। (पेज-4 भी देखें)

राकांपा को लेकर चुनाव आयोग के निर्णय के बाद मंगलवार को मुंबई में प्रेसवार्ता करते महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार। एएनआइ

उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- बहुविवाह, बाल विवाह, हलाला, इद्दत, तलाक जैसी प्रथाओं पर लगेगी रोक
- महिलाओं को संपत्ति में मिलेगा बराबरी का अधिकार

उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की दिशा में निर्णायक पहल की है। मंगलवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सदन में पेश यूसीसी, उत्तराखंड-2024 विधेयक में 392 धाराएं हैं। इनमें से केवल उत्तराधिकार से संबंधित धाराओं की संख्या 328 है।

विधेयक में महिला अधिकारों के संरक्षण को केंद्र में रखा गया है। कुल 192 पृष्ठों के विधेयक को चार खंडों विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, सहवासी संबंध (लिव इन रिलेशनशिप) व विविध में विभाजित किया गया है। विधेयक के पारित होने के बाद इसे राजभवन और फिर राष्ट्रपति भवन को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके कानून बनने पर बहु विवाह, बाल विवाह, इद्दत और हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी। संहिता के लागू होने पर किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधेयक पेश होने पर भाजपा विधायकों ने जय श्रीराम व भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के यशपाल आर्य ने कहा, विधेयक के अध्ययन के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। सरकार जल्दबाजी क्यों कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधेयक पढ़ने के लिए ढाई घंटे का समय दिया। फिर दोपहर दो बजे विधेयक पर पर चर्चा शुरू हुई। यह उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होगा, जो राज्य से बाहर रह रहे हैं। कानून बनने पर राज्य में कम से कम एक वर्ष निवास करने वाले अथवा राज्य व केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने वालों पर भी यह लागू होगा। अनुसूचित जनजातियों व भारत के संविधान की धारा-21 में संरक्षित समूहों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। (पेज-5 भी देखें)

हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। देवभूमि के लिए वह ऐतिहासिक क्षण निकट है, जब उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन एक भारत, श्रेष्ठ भारत का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा। - पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

देहरादून में मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में संविधान की प्रति के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा समान नागरिक संहिता की प्रति के साथ संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। जागरण

पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से दहला हरदा, 12 की मौत

नईदुनिया, हरदा

25 किमी दूर तक महसूस हुआ धमाकों का कंपन

- सीएम ने आपात बैठक बुलाई, सेना से मदद मांगी

171 घायल, फैक्ट्री मालिक समेत तीन गिरफ्तार

मध्य प्रदेश में हरदा जिले के बैरागढ़ गांव स्थित पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह आग लगने से विस्फोट हो गया। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 171 घायल हो गए। आग कैसे लगी इसका कारण तो पता नहीं चला, मगर 45 मिनट तक रह-रह कर धमाके होते रहे। ये इतने जोरदार थे कि वहां मौजूद लोहे के उपकरण और कंक्रीट करीब दो सौ मीटर की परिधि में उछले। इससे भी तमाम लोग घायल हुए।

हादसे की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने आपात बैठक की। इसके बाद बचावकार्य में सेना की मदद मांगी गई। सारंगपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल एवं उनका सहयोगी रफीक खान उज्जैन की तरफ भाग रहे थे, जिन्हें सटीक सूचना पर देर शाम को गिरफ्तार कर हरदा पुलिस को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार सुबह सवा ग्यारह बजे फैक्ट्री में जब विस्फोट हुआ तब वहां सौ से ज्यादा श्रमिक थे। प्रत्यक्षदर्शी सुरेश कुमार ने बताया कि विस्फोट होते ही फैक्ट्री में काम करने वाले बदहवास होकर बाहर भागे, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं-युवतियां फंस गईं। हताहतों में सबसे ज्यादा इनकी ही संख्या बताई जा रही है। (पहले भी हुआ हादसा: पेज-6)

प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने की राहत राशि की घोषणा

हादसे पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने प्रभावित परिवारों को राहत राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मरने वालों के स्वजन को चार-चार लाख रुपये, गंभीर घायलों को दो-दो लाख और साधारण घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। पीएम ने प्रत्येक मरने वाले के परिवार को प्रधानमंत्री सहायता कोष से दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता की घोषणा की है।

अधोमानक पाई गई थी फैक्ट्री

राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल फायर वर्क्स के नाम से संचालित फैक्ट्री को 2023 में प्रशासन ने अधोमानक पाते हुए सील कर दिया था। इसके बाद अग्रवाल ने संभागायुक्त से अपील की, इसके बाद फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी गई थी।

राष्ट्रपति ने जताया शोक

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा कि मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।

मध्य प्रदेश के हरदा में मंगलवार को पटाखा फैक्ट्री में आग एवं विस्फोट के बाद उठता धुआं। प्रेट्र

उद्योगों को राहत

राज्यसभा से पारित हुआ जल प्रदूषण (नियंत्रण और रोकथाम) संशोधन विधेयक, केंद्र तय करेगा राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति के मानक

जल प्रदूषण से संबंधित छोटे मामले अपराध के दायरे से होंगे बाहर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वर्तमान कानून कर रहे विकास को बाधित, जिनका समाधान जरूरी : भूपेंद्र यादव

राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से और केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार हो, इस उद्देश्य से राज्यसभा ने मंगलवार को जल प्रदूषण (नियंत्रण और रोकथाम) संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक में जल प्रदूषण से जुड़े छोटे-मोटे मामलों को अपराध के दायरे से बाहर करने का प्रविधान भी है। यह विधेयक इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इसके जरिये केंद्र सरकार ने पर्यावरण की चिंता और विकास पर बराबर ध्यान का इरादा प्रकट किया है। विधेयक के माध्यम से केंद्र को यह शक्ति भी मिलेगी कि वह राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमति देने, मना करने अथवा अनुमति रद करने के दिशा-निर्देश तय कर सकेगा।

संशोधन अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से उद्योगों पर मानकों के उल्लंघन को लेकर की जाने वाली तमाम दंडात्मक कार्रवाइयों को सरल कर दिया गया है। उल्लंघन के तमाम मामलों में अब जेल की सजा के बजाय केवल जुर्माना लगेगा। पहले ऐसे कुछ मामलों में अधिकतम चार वर्ष तक की सजा का भी प्रविधान था। विधेयक में जल प्रदूषण से संबंधित छोटे-मोटे मामलों को अपराध के दायरे से बाहर किया गया है और कुछ खास श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को कानूनी पाबंदियों से छूट दी गई है।

यह कानून मूल रूप से 1974 का है, जिसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक के संदर्भ में कुछ विपक्षी सदस्यों के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि यह संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है अथवा इससे केंद्र को राज्यों में जल प्रबंधन पर अनुचित दखल का अवसर मिलेगा। विधेयक पर एक घंटे की चर्चा का जवाब देते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि 1974 के कानून के कारण विकास में कई तरह के अवरोध उत्पन्न होते थे, जिनका समाधान जरूरी है। प्रस्तावित कानून राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला रोकेगा। राज्यों को बोर्ड में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों की नियुक्ति करनी होगी, इसके लिए मानक निर्धारित किए जाएंगे। भूपेंद्र यादव ने भरोसा दिलाया कि जल प्रदूषण से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों अथवा व्यक्तियों पर जो जुर्माना लगाया जाएगा, उसका 75% हिस्सा राज्यों को पर्यावरण संरक्षण निधि के तहत दे दिया जाएगा। इसे कैसे खर्च किया जाएगा, इसके लिए कुछ नियम तय किए जाएंगे। भूपेंद्र यादव ने कहा कि सुगम जीवन और कारोबारी सुगमता में समन्वय होना चाहिए। विधेयक के कानून बन जाने के बाद जल प्रदूषण के तमाम मसलों से कहीं अधिक पारदर्शिता से निपटा जा सकेगा। विधेयक के उद्देश्य में स्पष्ट किया गया है कि संशोधनों से आपराधिक प्रविधानों को तार्किक बनाया गया है, उद्योगों और कंपनियों को यह अवसर दिया गया है कि वे बिना किसी भय के अपना कामकाज कर सकें। अपराध की जैसी गंभीरता होगी, दंड भी उसी के अनुरूप होगा।

राज्यसभा में मंगलवार को कार्यवाही के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। एएनआइ

लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- रियाज सेना में करता था नौकरी, 31 जनवरी, 2023 को सेवानिवृत्त होने के बाद लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास से पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी रियाज अहमद राथर को गिरफ्तार किया है। आतंकी रियाज अहमद राथर सीमा पार से हथियार और गोला बारूद लेकर कश्मीर में लश्कर के अन्य आतंकियों को मुहैया कराता था।

आतंकी रियाज सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद लश्कर के लिए काम करने लगा। रियाज के साथ उसका दोस्त अल्ताफ भी 31 जनवरी 2023 को सेना से सेवानिवृत्त हुआ है। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा के मुताबिक, रियाज जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की तहसील करनाह के न्यू गबरा गांव का निवासी है। वह कश्मीर में हथियार और गोला-बारूद लाने के लिए आतंकी खुर्शीद अहमद राथर और गुलाम सरवर राथर के साथ काम करता था। चार फरवरी को नई दिल्ली थाना पुलिस को सूचना मिली कि रियाज ट्रेन से दिल्ली आया है। इस पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन थाना पुलिस की टीम सक्रिय हो गई। सोमवार सुबह पुलिस की नजर रियाज पर पड़ी। जैसे ही पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की वह भागने लगा। मगर पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। (पेज-2 भी देखें)

रियाज अहमद। फाइल

आतंकी रियाज अहमद राथर सीमा पार से कश्मीर में लेकर आया था हथियार और गोला-बारूद

****

141 रहा मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ)। इस गुणवत्ता की हवा 'मध्यम' श्रेणी की मानी जाती है। आगामी दो दिन हवा में प्रदूषण का स्तर 'मध्यम' श्रेणी में ही बना रहेगा। तेज हवा के असर से इसके और बेहतर होने के आसार हैं।

आज का मौसम

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
7 फरवरी	20.0	09.0
8 फरवरी	20.0	08.0
नोएडा		
7 फरवरी	19.0	07.0
8 फरवरी	18.0	07.0
गुरुग्राम		
7 फरवरी	16.2	08.3
8 फरवरी	15.5	06.7

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

सफाई कर्मियों को नियमित करने की सिफारिश

नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 साल से लगातार कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। इसके लिए पारदर्शी नीति बनाई जानी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति ने मंगलवार को लोकसभा में पेश एमसीडी के संदर्भ में भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की। सांसद किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी की अध्यक्षता वाली समिति ने सिफारिश की कि कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से जल्द से जल्द नियमित किया जाए। (प्रेट्र)

जेएनयू ने एमटीएस की भर्ती प्रक्रिया रोकी

नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ की होने वाली भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। इसके लिए जारी अधिसूचना में प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है। ऐसा तब हुआ है, जब दो महीने पहले कर्मचारियों ने कुलपति को पत्र लिखकर एनटीए के जरिये कराई गई परीक्षा से चयनित उम्मीदवारों की योग्यता पर सवाल उठाए थे। पिछले वर्ष अप्रैल महीने में 300 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। (जासं)

हेडगेवार अस्पताल से जुड़े 10 लोगों के खिलाफ होगी जांच

नई दिल्ली : उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक निजी दवा आपूर्तिकर्ता के कथित बढ़े हुए बिल पारित करने के मामले में डा. हेडगेवार अस्पताल के छह डाक्टरों सहित 10 लोगों की भूमिका की जांच करने की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को अनुमति दे दी है। सतर्कता निदेशालय ने इस मामले में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की अनुमति के बाद एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा था। (राब्यू)

तीन करोड़ लोगों के लिए मात्र छह सीटी स्कैन पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी

टिप्पणी ▶ बुनियादी ढांचा बेहतर बनाने की जरूरत, नहीं दिया जा रहा स्वास्थ्य क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान

कहा, सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं और कर्मचारियों की कमी के कारण देखभाल नहीं होने से जा रही लोगों की जान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

यदि कोई समस्या है, तो उसे सीधे स्वीकार करना चाहिए। जब तीन करोड़ लोग हमारी ओर देख रहे हैं तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे बीच कुछ झगड़ा चल रहा है। - **दिल्ली हाई कोर्ट**

दिल्ली में चिकित्सा सुविधा के बुनियादी ढांचे की खस्ताहाल स्थिति पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। तीन करोड़ नागरिकों के लिए दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में महज छह सीटी स्कैन मशीन होने के तथ्य पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी आबादी के लिए आपके पास सिर्फ छह सीटी स्कैन मशीनें कैसे हो सकती हैं? बुनियादी ढांचे को कई गुना बेहतर बनाने की जरूरत है। आप इसे कैसे बढ़ाएंगे, यह रातों-रात नहीं किया जा सकता? पीठ ने कहा कि लंबे समय से स्वास्थ्य क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े मामले का स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने अदालत में मौजूद स्वास्थ्य सचिव से पूछा कि अधिकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को कैसे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव ने दावा किया है कि सभी छह मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन दो अलग-अलग संस्थानों ने एक अलग मामले में हलफनामा देकर कहा है कि ये पूरी तरह काम नहीं कर रही हैं। अदालत ने इस टिप्पणी के साथ मामले से जुड़े सभी विभागों को अपनी रिपोर्ट व सुझाव देने का निर्देश देते हुए नौ फरवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने सुनवाई के दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा दी गई स्थिति रिपोर्ट को स्वीकार किया। डाक्टरों के 75 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली हैं और पैरामेडिक्स के 20 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं।

स्वास्थ्य सचिव ने कहा, मंत्री के आरोप गलत : दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बैठकों में उपस्थित नहीं होने के आरोप का दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव ने खंडन किया। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहे स्वास्थ्य सचिव एसबी दीपक कुमार ने खुद पर लगे आरोप से इन्कार करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और उन्होंने सभी बैठकों में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री के साथ विभिन्न अस्पतालों में गया हूं और जहां भी मैं नहीं जा सका, उसके बारे में उन्हें सूचित किया है। मैं हमेशा बैठकों में मौजूद रहा हूं। मंत्री की बैठकों के विवरण में मेरी उपस्थिति दिखाई देगी। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि जब भी उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ बैठकें बुलाईं तब स्वास्थ्य सचिव बैठकों में शामिल नहीं हुए।

आप सरकार ने दिल्ली को वेंटिलेटर पर डाला : लेखी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय संस्कृति राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। सोमवार को अदालत ने कहा कि दिल्ली में तीन करोड़ की जनसंख्या पर मात्र छह सीटी स्कैन मशीन हैं। इसे लेकर सरकार ने झूठा शपथपत्र दिया। कट्टर ईमानदार कहकर सत्ता में आने वाले अब भ्रष्टाचार की परिभाषा बन गए हैं। प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि ईडी की जांच में आबकारी घोटाले में ढाई से तीन हजार करोड़ रुपये की चोरी होने की बात सामने आई है। अभी इसकी जांच चल ही रही थी कि जल बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग का घोटाला सामने आ गया। आप ने दिल्ली में 30 हजार नए बेड की व्यवस्था करने और प्रत्येक पांच हजार लोगों पर पांच बेड उपलब्ध कराने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। 900 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाने का वादा किया था, परंतु नए खुलने की जगह पुराने भी बंद हो रहे हैं।

एम्स ने 'प्रोटान थेरेपी' से पीछे खींचे कदम, अब खरीदेगा लीनियर मशीन

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

▶ **दो बार टेंडर जारी होने के बावजूद नहीं खरीदी जा सकी अत्याधुनिक प्रोटान थेरेपी मशीन**

एम्स कैंसर मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दो बार प्रोटान बीम थेरेपी मशीन खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के बावजूद उसे खरीद नहीं पाया। मशीन खरीदने में हुई वर्षों विलंब के कारण संस्थान की स्थायी वित्त समिति ने इस योजना को रोक दिया। लिहाजा, देश में सबसे ज्यादा बजट वाले इस चिकित्सा संस्थान ने अत्याधुनिक प्रोटान बीम थेरेपी की मशीन खरीदने की योजना से फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं। इसकी जगह एम्स ने कैंसर सेंटर आइआरसीएच (इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हास्पिटल) में कैंसर मरीजों की रेडिएशन थेरेपी के लिए अत्याधुनिक लीनियर एक्सीलेरेटर मशीन खरीदने की पहल की है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआइ) में भी नई लीनियर एक्सीलेरेटर मशीन लगाने की योजना है।

मौजूदा समय में एम्स दो कैंसर सेंटर का संचालन कर रहा है। इसमें एम्स के दिल्ली स्थिति परिसर में मौजूद कैंसर सेंटर आइआरसीएच व हरियाणा के झज्जर में स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआइ) शामिल है। एनसीआइ में कैंसर के मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करीब सवा सौ करोड़ की लागत से प्रोटान थेरेपी की मशीन खरीदने की योजना थी। एम्स ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएलएल को यह मशीन खरीदने की जिम्मेदारी दी थी। यह मशीन खरीदने के लिए सितंबर 2018 में पहली बार टेंडर हुआ। तकनीकी अड़चन के कारण यह टेंडर रद हो गया। इसके बाद एम्स ने आइआरसीएच और एनसीआइ के तत्कालीन प्रमुख डा. जीके रथ की अध्यक्षता में एक तकनीकी कमेटी गठित की। इसके बाद 24 मई 2021 को दोबारा यह मशीन खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। इसके कुछ समय बाद डा. जीके रथ एम्स से सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद टेंडर दोबारा रद हो गया। एम्स में बैठकों का दौर जारी रहा और तीसरी बार टेंडर जारी करने का फैसला हुआ था, लेकिन अस्पताल प्रशासन योजना को मूर्त रूप नहीं दे पाया। इस देरी के कारण मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

प्रोटान थेरेपी सबसे अत्याधुनिक तकनीक है। इससे रेडिएशन देने पर शरीर के अन्य हिस्सों के ऊतकों पर दुष्प्रभाव नहीं होता।

संजय सिंह को अदालत ने शपथ ग्रहण करने की दोबारा दी अनुमति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पुलिस हिरासत में आठ और नौ फरवरी को संसद ले जाने को कहा

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद आप नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करने की दूसरी बार अनुमति दी। अदालत ने पुलिस हिरासत में संजय सिंह को आठ और नौ फरवरी को संसद ले जाने को कहा। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिंह के अधिवक्ता और जेल अधीक्षक को शपथ ग्रहण की तारीख के बारे में राज्यसभा सचिवालय से संपर्क करने को कहा। अदालत ने सिंह को किसी भी एक तारीख पर उचित सुरक्षा के बीच संसद ले जाने का निर्देश दिया और कहा कि इस बीच उनको मोबाइल फोन का उपयोग करने या किसी भी आरोपित, संदिग्ध, गवाह और मीडिया से बातचीत की अनुमति नहीं होगी। हालांकि सिंह के परिवार के सदस्यों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान उनके साथ रहने की अनुमति दी।

सिंह के अधिवक्ता ने अदालत से अपने मुवक्किल के राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने को लेकर दो दिन की अनुमति मांगी ताकि अगर वह किसी कारण से पहले दिन शपथ नहीं ले पाएं तो दूसरे दिन उन्हें मौका मिल जाए। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को अदालत ने पांच फरवरी को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने की अनुमति दी थी लेकिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सिंह का शपथ ग्रहण सदन के कामकाज में सूचीबद्ध नहीं होने के कारण उन्हें अनुमति नहीं दी थी।

जमानत याचिका पर हाई कोर्ट आज सुनाएगा निर्णय : संजय सिंह की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। 31 जनवरी को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

आरोपितों के बयान की रिकार्डिंग नष्ट कर रही है ईडी : आप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ **आप का दावा- ईडी ने सुबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज से आडियो डिलीट किया गया**

आप कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करतीं शिक्षा मंत्री आतिशी। सौजन्य-आप

आम आदमी पार्टी (आप) ने दावा किया है कि आबकारी नीति मामले में ईडी को पिछले दो साल की जांच में एक भी सुबूत नहीं मिला है। जो बयान आरोपितों ने कैमरे के सामने दिए हैं, उनकी रिकार्डिंग डिलीट की जा रही है। आबकारी नीति मामले से जुड़े गवाहों और आरोपितों के बयान जांच एजेंसी ने बलपूर्वक और धमकी देकर दिलवाए हैं। घोटाला आबकारी नीति में नहीं, बल्कि घोटाला तो इस मामले में ईडी की ओर से की जा रही जांच में है। केंद्र सरकार ईडी के छापे से आम आदमी पार्टी को डराने और चुप कराने की कोशिश कर रही है।

आप नेता व दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने सोमवार को यह घोषणा की थी कि वह मंगलवार सुबह ईडी को लेकर एक बड़े मामले से पर्दा उठाने जा रही हैं। वह संवाददाता सम्मेलन कर पातीं उससे पहले ही ईडी ने सुबह से ही दिल्ली में कई स्थानों पर आप से संबंधित लोगों के यहां छापेमारी शुरू कर दी।

आतिशी के अलावा आप नेता जस्मिन शाह, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज व आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने ईडी के छापों पर नाराजगी जताते हुए इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा।

आप के चारों नेताओं ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग मामले के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार और आप के राज्यसभा सदस्य और पार्टी के कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता के परिसरों आदि में जो छापेमारी की है यह उनकी हताशा को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि अभी आप के अन्य नेताओं के यहां भी छापेमारी होने वाली है। आप नेताओं ने कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी आम आदमी पार्टी को डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश कर रही है। मगर आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री, भाजपा और उनकी एजेंसियों ईडी और सीबीआइ से डरने वाली नहीं है।

आप नेताओं ने कहा कि ईडी सुबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज से आडियो को डिलीट कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि बिना आडियो के कैसे पता चलेगा कि ईडी ने जिन गवाहों से बयान लिए, वो सही हैं या गलत या फिर उनकी गवाही से मेल खाती है या नहीं।

उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि ईडी की पूरी जांच ही फर्जी है। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि कोई भी जांच एजेंसी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में गवाहों से पूछताछ करेगी और वीडियो के साथ आडियो भी रिकार्ड करना होगा। इसके बावजूद ईडी ने आडियो रिकार्डिंग डिलीट कर दी। उन्होंने कहा कि आखिर किसे बचाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि पिछले डेढ़ साल में गवाहों से हुई पूछताछ का आडियो देश और कोर्ट के सामने रखे जाएं।

जल बोर्ड के भ्रष्टाचार आ रहे हैं सामने : भाजपा

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीवर लाइन व जलापूर्ति लाइन डालने, भूमिगत जलाशय बनाने, टैंकर के माध्यम से जल वितरण करने, पानी बिल जमा करने में भ्रष्टाचार किया गया है। भाजपा जल बोर्ड के भ्रष्टाचार को उठाती रही है। आप सांसद एनडी गुप्ता एवं मुख्यमंत्री के निजी सचिव बिभव कुमार सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर ईडी के छापों से भाजपा के आरोपों की पुष्टि होती है।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र देना चाहिए। नौ वर्ष पहले जल बोर्ड 600 करोड़ रुपये के लाभ में था। अब 73 हजार करोड़ रुपये के घाटे में है। भ्रष्टाचार के अनेक मामले सामने आ चुके हैं। अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। प्रदेश भाजपा मंत्री बांसुरी स्वराज ने कहा कि आप सरकार में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। ईडी ने जल बोर्ड घोटाले की जांच के लिए छापेमारी की तो इससे ध्यान भटकाने के लिए आप नेता आबकारी घोटाले पर बयानबाजी करने लगे।

कोर्ट ने सीएजी से जल बोर्ड के खातों का शीघ्रता से आडिट करने को कहा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ **भाजपा नेता हरीश खुराना ने याचिका दायर कर सीएजी को बोर्ड का आडिट करने का निर्देश देने की मांग की थी**

दिल्ली हाई कोर्ट ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के 2018 से 2021 तक के खातों का शीघ्रता से आडिट करने का आदेश दिया। भाजपा नेता हरीश खुराना की ओर से डीजेबी के खातों का आडिट करने के लिए सीएजी को निर्देश देने की मांग याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया। याचिका में दावा किया गया है कि पिछले कई वर्षों से डीजेबी का वित्तीय आडिट नहीं किया गया है।

सीएजी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्हें डीजेबी से वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए वार्षिक खातों का विवरण प्राप्त हुआ है और वे खातों के आडिट की प्रक्रिया में हैं। यह भी बताया कि उसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है क्योंकि खाते आडिट के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। डीजेबी और दिल्ली सरकार से आडिट के लिए खाते मांगने के लिए कई पत्राचार किए, लेकिन खाते उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण आडिट पूरा नहीं किया जा सका।

याचिका का जवाब देते हुए, डीजेबी ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है कि पारदर्शिता और कानून के अनुपालन के हित में सभी विवरण विधिवत तैयार हों, जिसका आडिट हो।

याचिकाकर्ता ने कहा कि अधिकारी कानून के तहत निर्धारित कार्यों को करने में विफल रहे हैं, इसलिए उसने डीजेबी को उचित खाते और अन्य प्रासंगिक रिकार्ड बनाए रखने और कानून के तहत 2015 के बाद से उचित बैलेंस शीट के साथ वार्षिक विवरण तैयार करने का निर्देश देने और सीएजी को बोर्ड का आडिट करने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि 11 मई, 24 मई और 22 जुलाई 2021 को आरटीआइ से मिली जानकारी में बताया गया कि वर्ष 2015-16 और उसके बाद की बैलेंस शीट की कापी तैयार की जा रही है।

'जमानत याचिकाओं पर अंतहीन बहस नहीं कर सकती पुलिस'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली दंगे की साजिश से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस पर सवाल उठाया है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने टिप्पणी की कि अदालत दोषसिद्धि या बरी किए जाने के खिलाफ अपील याचिका पर सुनवाई करने के बजाय केवल आरोपितों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस तरह की याचिकाओं में बहस हमेशा के लिए नहीं चल सकती। पुलिस आरोपितों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं के खिलाफ अंतहीन बहस नहीं कर सकती।

कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष को प्रत्येक आरोपित द्वारा निभाई गई भूमिका को इंगित करने के लिए एक समयसीमा का पालन करने की आवश्यकता है। प्रकरण में आरोपित यूनाइटेड अगेन्स्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कोई भी समझ सकता है कि आपको एक या सवा घंटा चाहिए, लेकिन हम असीमित समय नहीं दे सकते।

कहीं पुलवामा हमले की बरसी पर दिल्ली को दहलाने तो नहीं आया था रियाज !

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

▶ **एनआइए और स्पेशल सेल समेत तमाम एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ**

▶ **आतंकी रियाज के दिल्ली आने के कारण का पता लगाने का प्रयास जारी है**

दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी रियाज अहमद। स्रोत - पुलिस

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए गए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी रियाज अहमद को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) और स्पेशल सेल को संदेह है कि वह किसी बड़ी वारदात की साजिश रचने के लिए तो दिल्ली नहीं आया था! सुरक्षा एजेंसियां उससे गहन पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह दिल्ली क्यों आया था। पुलवामा हमले की 14 फरवरी को बरसी है। दरभंगा रेलवे स्टेशन विस्फोट की तर्ज पर लश्कर के पीओके स्थित हैंडलर शकूर बाबा कहीं इस दिन एक और हमले की साजिश तो नहीं रच रहा।

डीसीपी केपीएस मल्होत्रा का कहना है कि तमाम एजेंसियां आतंकी रियाज से पूछताछ कर रही हैं। जून 2021 में लश्कर के आतंकियों ने सिकंदराबाद-दरभंगा स्पेशल ट्रेन में विस्फोटकों से भरी एक खेप बुक की थी। लश्कर का उद्देश्य चलती ट्रेन में विस्फोट कराने की थी ताकि बड़े पैमाने पर मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन विस्फोट तब हुआ था जब पार्सल गंतव्य स्टेशन पर उतारकर गोदाम में ले जाया जा रहा था। उस मामले में एनआइए लश्कर के पांच आतंकियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर चुकी है। जांच एजेंसी की मानें तो रियाज लश्कर के बड़े माड्यूल का सदस्य है।

तीन फरवरी को दोस्त अल्ताफ के साथ जबलपुर से आया था दिल्ली

प्रथम पृष्ठ से आगे

आतंकी रियाज अहमद राथर से पूछताछ में पता चला कि वह जबलपुर से अपने दोस्त अल्ताफ के साथ महाकौशल एक्सप्रेस से दिल्ली आया था। वह दूसरे ठिकाने पर जाने की तैयारी में था। इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस उससे अल्ताफ के बारे में पूछताछ कर रही है कि अल्ताफ दिल्ली आया था या कहीं बीच में ही उतर गया।

जम्मू-कश्मीर में पकड़े गए आतंकी माड्यूल का सक्रिय सदस्य है रियाज : जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से पकड़े गए आतंकी माड्यूल का रियाज अहमद राथर सक्रिय सदस्य है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई में पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से पांच एके-47 राइफल, पांच मैग्जीन, 16 कारतूस सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थीं।

केजरीवाल को राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में समन रद

पणजी, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को राहत दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा केजरीवाल को जारी समन मंगलवार को रद कर दिया।

आप की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर ने कहा कि 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल के खिलाफ दायर एक शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जारी समन को हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएफएमसी) मापुसा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ई) के तहत दायर आरोपपत्र के संबंध में केजरीवाल को तलब किया था। पालेकर ने कहा, केजरीवाल ने जेएमएफसी से समय मांगा गया था, क्योंकि हम हाई कोर्ट के समक्ष अपील करना चाहते थे। मामले की सुनवाई 12 फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने होगी।

दावा

पश्चिम विहार में स्कूल आफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के नए भवन का किया उद्घाटन

शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा 40 प्रतिशत बजट : केजरीवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

54 क्लास रूम हैं इस स्कूल में | **1200** बच्चे पढ़ सकेंगे | **2** लाइब्रेरी, 13 लैब, 18 एक्टीविटी रूम की है सुविधा

पश्चिम विहार में स्कूल आफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के नए भवन के उद्घाटन के बाद संबोधित करते केजरीवाल। सौ. : दिल्ली सरकार

पश्चिम विहार के डा. बीआर अंबेडकर स्कूल आफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस (एएसओएसई) के नवनिर्मित भवन का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उद्घाटन किया। इस अवसर पर केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा का बजट बढ़ाकर दोगुना कर दिया और अब शिक्षा-स्वास्थ्य पर दिल्ली के कुल बजट का 40 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सपने मर जाया करते थे, लेकिन अब हर तरह की आधुनिक सुविधाएं देकर उनके सपनों को पंख दिया जा रहा है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री आतिशी भी मौजूद रहीं।

केजरीवाल ने कहा, 'मुझे लगता है कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं हो सकता है। जब मेरी मौत आएगी तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैंने दिल्ली में लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का इंतजाम किया। कम से कम मेरी जिंदगी इतनी तो काम आई।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 से पहले दिल्ली में शिक्षा का बजट पांच हजार करोड़ रुपये था। इसे बढ़ाकर दस हजार करोड़ किया गया। इसी वजह से इतने सारे सरकारी स्कूल बनने लगे। अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश का बजट पेश किया है। केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए मात्र चार प्रतिशत बजट दिया है। केजरीवाल ने कहा कि पहले जब सरकारी और निजी स्कूल के बच्चे आपस में मिलते थे तो सरकारी स्कूल के बच्चे के मन में एक हीन भावना होती थी। लेकिन अब सरकारी स्कूल के बच्चों में वो हीन भावना खत्म हो गई हैं।

सरकारी स्कूल में पढ़ रहे विधायकों के बच्चे

केजरीवाल ने बताया कि मटियाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक गुलाब सिंह और ओखला विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमानतुल्लाह खान जैसे कई विधायक हैं, जिनके बच्चे निजी स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया। उनको लगता है कि उनके इलाके का सरकारी स्कूल अब बहुत अच्छा हो गया है। उन्होंने छात्रों से कभी अपने देश को न भूलने की अपील की। क्योंकि वह टैक्स देने वाले लोगों की मदद से ही अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं।

स्कूल की हालत देखकर पहले आंसू आ जाते थे : आतिशी

आतिशी ने कहा कि पहले सरकारी स्कूलों की हालत देखकर आंखों में आंसू आ जाते थे। शौचालय से बदबू आती थी, टेबल-कुर्सी नहीं होते थे, खिड़कियां, लाइटें और ब्लैक बोर्ड टूटे हुए होते थे। शिक्षकों की जगह-जगह ड्यूटी लगाई जाती थी। नौ वर्षों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की क्रांति आई है। 2015 में पूरी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मात्र 24 हजार कमरे हुआ करते थे। नौ वर्ष में 20 हजार कमरे बनाकर दिखा दिए। अब दाखिले के लिए निजी स्कूलों के बजाय दिल्ली के एएसओएसई के बाहर लंबी लाइनें लगती हैं। इस वर्ष जब एएसओएसई के लिए छह हजार सीटों पर दाखिला खुला तो एक लाख 40 हजार बच्चों ने आवेदन किया।

युवक व 76 वर्षीय महिला के अंगदान से छह लोगों को मिला नया जीवन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ **युवक छत से गिरकर व बुजुर्ग महिला सीढ़ियों से गिरकर हुई हादसे की शिकार**

छत और सीढ़ियों से गिरने के कारण हादसे के शिकार एक 32 वर्षीय युवक और एक 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला के अंगदान से छह लोगों को नया जीवन मिला। उनके अंगदान से मिले दो लिवर व चार किडनी अलग-अलग अस्पतालों में मरीजों को प्रत्यारोपित किए गए।

पहला अंगदान आरएमएल अस्पताल में 32 वर्षीय युवक का हुआ। शराब के नशे में होने के कारण वह आजादपुर में घर के पहले तल की छत से नीचे गिर गया था। इस वजह से सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्रेन डेड होने पर अस्पताल के डाक्टरों और कर्मचारियों ने परिवार के लोगों से उसके अंगदान के लिए प्रेरित किया। किडनी और लिवर दान की प्रक्रिया पूरी की गई। यह आरएमएल अस्पताल में मार्च 2020 के बाद पहला और अब तक का पांचवां अंगदान का मामला है।

इसके बाद एम्स ट्रामा सेंटर में प्रेमवती नामक 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला का अंगदान हुआ। वह संगम विहार की रहने वाली थी। सीढ़ियों से गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी। तीन फरवरी को उन्हें एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया था। जहां ब्रेन डेड होने पर परिवार के लोगों ने स्वयं उनका अंगदान कराया। उनके अंगदान से मिला लिवर व दोनों किडनी राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो) ने आर्मी अस्पताल को आवंटित किया।

****

247 यात्रियों को गत चार वर्षों में नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया। नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री वीके सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि 2020 में नो फ्लाई लिस्ट में यात्रियों की संख्या 10 थी, जो 2021 में बढ़कर 66 हो गई।

विभिन्न प्रयासों से खुदरा महंगाई दर में आ रही है कमी : सीतारमण

राहत के उपाय ▶ पिछले वर्ष 24 लाख टन अरहर और मसूर दाल का किया गया आयात

25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चार लाख टन प्याज सरकार ने बाजार में भेजा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार के विभिन्न प्रयासों से खुदरा महंगाई दर में कमी आ रही है और अब यह दर अपनी अधिकतम सीमा के अंदर है। आरबीआइ के मुताबिक खुदरा महंगाई दर की अधिकतम सीमा छह प्रतिशत है। गत दिसंबर और नवंबर में खुदरा महंगाई दर क्रमशः 5.69 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत थी।

राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान मंगलवार को वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार जल्दी नष्ट होने वाली खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति पर लगातार नजर रख रही है और उनकी आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि दाल का हम अधिक उत्पादन नहीं करते, जिससे उसकी आपूर्ति प्रभावित हो जाती है और उससे दाल की कीमतें ऊपर-नीचे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एएनआइ

होती रहती हैं। इसे देखते हुए हमने दाल का आयात शुरू किया और वर्ष 2023 में 8.79 लाख टन तुअर (अरहर) तो 15.14 लाख टन मसूर दाल का आयात किया। दाल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने भारत दाल के नाम से चना दाल की बिक्री शुरू की है जिसके तहत एक किलोग्राम चना दाल का पैक 60 रुपये तो 30 किलोग्राम का पैक 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। 30 जनवरी तक 2.97 लाख टन भारत चना दाल की बिक्री हो चुकी है।

सीतारमण ने बताया कि दाल की तरह प्याज के दाम को भी काबू में रखने का लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तीन फरवरी तक 3.96 लाख टन प्याज 25 रुपये की दर से बाजार में जारी किया गया। प्याज के आयात पर रोक भी जारी है। प्याज की तरह टमाटर व अन्य शीघ्र नष्ट होने वाली खाद्य वस्तुओं की कमी को दूर करने का प्रयास सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। दिसंबर माह की खुदरा महंगाई दर में प्याज, सब्जियों एवं दाल के दाम प्रमुख कारक थे। सब्जियों के दाम में 27.64 प्रतिशत तो दाल के दाम में 20.73 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई।

एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि गामा किरणों के माध्यम से प्याज को नमीमुक्त करके लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। सरकार उन परेशानियों पर भी विचार कर रही है जो जल्दी खराब होने वाली और भारत में नहीं उगने वाली चीजों की कमी से पैदा होती हैं।

संसद का सत्र एक दिन बढ़ा, श्वेत पत्र लाने की तैयारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि संसद के मौजूदा बजट सत्र को एक दिन बढ़ाकर शनिवार तक किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि सरकार श्वेत पत्र लाने की तैयारी कर रही है। इस श्वेत पत्र में 2014 से पहले और बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना की जाएगी। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी। इसे नौ फरवरी को समाप्त होना था। अब बजट सत्र 10 फरवरी तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा था कि केंद्र सरकार 2014 से पहले और बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए श्वेत पत्र जारी करेगी। वित्त मंत्री ने कहा था, केवल उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक लेने के उद्देश्य से अब यह देखना उचित है कि हम 2014 तक कहां थे और अब कहां हैं। सरकार सदन के पटल पर श्वेत पत्र रखेगी।

देश में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़कर हुई 12146 : कृष्ण पाल गुर्जर

नई दिल्ली, आइएएनएस : देश में गत दो फरवरी तक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 12146 हो चुकी है। महाराष्ट्र 3079 के साथ पहले, दिल्ली 1886 के साथ दूसरे और 1041 ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। शीर्ष दस प्रदेशों की सूची में उत्तर प्रदेश (582) छठे, राजस्थान (500) सातवें और मध्य प्रदेश (341) दसवें स्थान पर हैं। भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि भारी उद्योग मंत्रालय देश में ईवी को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है। ईवी उपयोगकर्ता में विश्वास पैदा करने के लिए सार्वजनिक चार्जिंग ढांचा स्थापित करने के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा बिजली मंत्रालय ने भी देश में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचा निर्माण को गति प्रदान करने के लिए कई पहल शुरू की हैं।

प्लास्टिक के नोट शुरू करने की योजना नहीं : सरकार की प्लास्टिक के नोट शुरू करने की कोई योजना नहीं है। भारतीय बैंक नोटों की स्थायित्व और नकली प्रतिरोध को बढ़ाने का प्रयास एक सतत प्रक्रिया है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि 2022-23 की आरबीआइ की रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 के लिए सिक्यूरिटी मुद्रण पर 4682.80 करोड़ रुपये का खर्च आया और प्लास्टिक नोटों छपाई पर कोई खर्चा नहीं हुआ।

संसद प्रश्नोत्तर

गृह मंत्रालय की सूची में 17 संगठन गैरकानूनी : नित्यानंद

नई दिल्ली, प्रेट्र : वर्तमान में गृह मंत्रालय की सूची में 17 संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत गैरकानूनी संघों के रूप में नामित किया गया है। यूएपीए 1967 की धारा तीन की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर केंद्र सरकार देशभर में किसी भी संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित कर सकती है।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय। प्रेट्र

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि इस सूची में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा), लिबरेशनल टाइगर्स आफ तमिल ईलम (लिट्टे), जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन गुट), सिख फार जस्टिस (एसएफजे), पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) और इसके सहयोगी संगठन रिहाब इंडिया फाउंडेशन (आरआइएफ), कैंपस फ्रंट आफ इंडिया (सीएफआइ), मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट), तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू-कश्मीर (टीईएच) समेत 17 संगठन शामिल हैं।

प्रधानमंत्री किसान योजना में राशि बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों का वित्तीय लाभ बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। योजना के तहत महिला किसानों की धनराशि भी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि योजना के तहत अब तक 11 करोड़ किसानों में 15 किस्तों में 2.81 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 2.62 करोड़ किसानों का योजना का लाभ मिल चुका है।

देश में अब तक 22 एम्स की स्थापना को मंजूरी : मांडविया

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देशभर में 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना को अब तक मंजूरी दी जा चुकी है। 22 में से 16 एम्स में शिक्षण, अनुसंधान, मरीज देखभाल की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि ये 16 एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, नागपुर, बिलासपुर, गोरखपुर, रायबरेली, देवघर, बठिंडा, गुवाहाटी, कल्याणी, मंगलगिरि और बीबीनगर में हैं। इनमें भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश के एम्स पूरी तरह शुरू हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त राजकोट, विजयपुर (जम्मू), मदुरै (तमिलनाडु), अवंतीपोरा (कश्मीर), रेवाड़ी (हरियाणा) और दरभंगा (बिहार) परिचालन के विभिन्न चरणों में हैं।

एक करोड़ से अधिक कमाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 2.16 लाख

निर्धारण वर्ष 2023-24 में 31 दिसंबर 2023 तक देश में वार्षिक एक करोड़ रुपये से अधिक कमाने वालों की संख्या बढ़कर 2.16 लाख हो गई है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को उच्च सदन में बताया कि एक करोड़ रुपये से अधिक कमाने वालों की संख्या निर्धारण वर्ष 2019-20 में 1.09 लाख की तुलना में 2022-23 में बढ़कर 1.87 लाख हो गई। एक अन्य सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गत 31 जनवरी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह व व्यक्तिगत आयकर में साल दर साल 27.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

गूगल ने एक वर्ष में 2200 फर्जी लोन एप प्ले स्टोर से हटाए

गूगल ने सितंबर 2022 से अगस्त 2023 के बीच 2200 से अधिक फर्जी लोन एप को प्ले स्टोर से हटाया। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 के बीच गूगल ने तकरीबन 3500-4000 लोन एप की समीक्षा की और 2500 से अधिक लोन एप को हटा दिया। वित्त राज्यमंत्री भागवत के. कराड ने मंगलवार को उच्च सदन में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार फर्जी लोन एप को नियंत्रित करने के लिए लगातार आरबीआइ और अन्य नियामकों व संबंधित हितधारकों के साथ काम कर रही है।

'एससी-एसटी अभ्यर्थियों को जानबूझकर अनुपयुक्त घोषित किया'

नई दिल्ली, प्रेट्र: चयन समिति के पक्षपातपूर्ण होने के कारण शैक्षणिक संस्थानों में संकाय सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए एससी-एसटी अभ्यर्थियों को जानबूझकर अनुपयुक्त घोषित किया गया। यह जानकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति ने मंगलवार को लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में दी।

समिति ने कहा कि सरकार के पर्याप्त संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने का रुढ़िवादी जवाब स्वीकार्य नहीं है। यह समान रूप से उज्ज्वल और प्रतिभाशाली एससी व एसटी उम्मीदवारों के मूल्यांकन की वास्तव में सही तस्वीर नहीं है। सांसद कीर्ति प्रेमजीभाई सोलंकी की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि एम्स, नई दिल्ली में संकाय पदों के लिए चयन स्थायी चयन समिति द्वारा किया जाता है। इसमें अध्यक्ष सहित सात सदस्य होते हैं। लेकिन समिति में एससी व एसटी समुदाय से जुड़ा कोई सदस्य नहीं है। चयन समिति में इन समुदायों का सदस्य होना जरूरी है।

पेपर लीक कानून के दायरे से बाहर रहेंगे विद्यार्थी और अभ्यर्थी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ लोकसभा में पास हुआ पेपर लीक एवं नकल रोकने से संबंधित विधेयक

▶ दस वर्ष की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माना का प्रविधान

सरकारी नौकरियों में भर्ती एवं विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त है। पेपर लीक या नकल कराते पकड़े जाने पर तीन वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान किया गया है। विद्यार्थी एवं अभ्यर्थी इसके दायरे में नहीं आएंगे। लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 को मंगलवार को लोकसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। एक दिन पहले लोकसभा में यह विधेयक पेश किया गया था।

परीक्षाओं में कदाचार को स्पष्ट करते हुए विधेयक में कहा गया है कि प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी को लीक करना, परीक्षा में अनधिकृत रूप से किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभ्यर्थी की सहायता करना एवं कंप्यूटर नेटवर्क, संसाधन एवं सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा।

इसी तरह का व्यवहार किसी व्यक्ति, समूह या संस्थानों द्वारा किए जाने को कदाचार की श्रेणी में रखा गया है। दोषियों

केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह मंगलवार को लोकसभा में बोलते हुए। एएनआइ

से परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा। उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती एवं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित परीक्षाएं आएंगी।

लोकसभा में संबंधित विधेयक पर मंगलवार को हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता लाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। विद्यार्थी एवं अभ्यर्थी इसके दायरे में नहीं आएंगे और न ही किसी का उत्पीड़न होगा।

उन्होंने इसे बेटे-बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी और राजनीति से ऊपर बताया। इस कानून के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो परीक्षा की पारदर्शी प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करेंगे। कदाचार के कारण परीक्षा रद होने की स्थिति में दोबारा परीक्षा लेने की समय-सीमा तय करने के कुछ सदस्यों की सलाह पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में सीबीआइ जांच या अन्य प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इसलिए, समय-सीमा तय करना संभव नहीं, लेकिन सरकार का प्रयास परीक्षार्थियों के हित में होगा। विद्यार्थियों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए मंत्री ने कहा कि प्रतिभा एवं परिश्रम के आधार पर उन्हें मौके मिलने चाहिए।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत उन्हें हर तरह के विषय पढ़ने और करियर के विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने डीएमके सांसद कथिर आनंद के उस बयान को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि भाषा के कारण कतिपय परीक्षार्थियों के साथ भेदभाव होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) एवं अन्य परीक्षाओं को देश की 13 भाषाओं में आयोजित कराना शुरू किया है। प्रयास है कि आगे आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं।

महिला आरक्षण बस कागज पर, यह धारणा न बनाएं : धनखड़

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने महिला आरक्षण पर शिवसेना (उद्धव गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण केवल कागज पर मिल रहा है, यह धारणा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

▶ शिवसेना सांसद प्रियंका की टिप्पणी को सभापति ने किया खारिज

जगदीप धनखड़। एएनआइ

चर्चा में भाग लेते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने मंगलवार को उच्च सदन में कहा कि पिछले साल संसद में पारित महिला आरक्षण बिल वर्ष 2029 के बाद ही लागू होगा। आप (महिलाएं) तब तक कतार में खड़ी रहें, लेकिन हम (सरकार) आपके लिए दरवाजा 2029 में ही खोलेंगे। इस पर धनखड़ ने कहा कि इस कानून तक पहुंचने का रास्ता एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

उन्होंने कहा कि इस पर कोई अन्यथा भाव जाहिर करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर हमें बहुत तार्किक होने की जरूरत है। महिला आरक्षण बिल का पूरी संसद ने समर्थन किया है। इससे प्रसन्नचित संसद सदस्यों में एक आप भी थीं प्रियंका जी। आप जानतीं हैं कि फलीभूत होने से पहले एक प्रक्रिया का पालन करना होता है।

धनखड़ ने कहा कि एक इकोसिस्टम बनाने के लिए कुछ दिया ही जा रहा है। इसलिए ऐसा भाव न दर्शाएं कि कुछ ऐसा दिया गया है जो तत्काल लागू किया जा सकता है। सभी को पता है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पहले परिसीमन करना पड़ता है और आरक्षण के लिए संसदीय क्षेत्रों की पहचान करना जरूरी है। तीन दशकों से हमारी माताएं और बहनें इस आरक्षण के लिए इंतजार करती रही हैं। आखिरकार सबके सहयोग से यह फलीभूत होने जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में निकाय चुनावों में ओबीसी को मिलेगा आरक्षण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ विपक्ष की विधानसभा चुनाव कराने की समय सीमा निर्धारित करने की मांग

▶ संबंधित विधेयक लोकसभा में चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया

जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकायों के चुनाव में भी अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण मिल सकेगा। संबंधित विधेयक को लोकसभा में मंगलवार को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सब तरफ विकास है। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की जनता परेशान है। विधेयक के जरिये जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम-1989; जम्मू-कश्मीर निगम अधिनियम-2000 और जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम-2000 में संशोधन किया गया। केंद्र शासित इस प्रदेश में अभी तक पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रविधान नहीं था।

राय ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य निकाय चुनावों में निष्पक्षता को स्थापित करना है। अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। शांति-सुरक्षा के साथ सिंचाई, कृषि एवं पर्यटन को गति मिली है। सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में सुधार है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का नतीजा है कि हिंसा, पत्थरबाजी एवं आतंकी घटनाओं में कमी आई है। वहां के लोगों ने सरकार पर भरोसा किया। जम्मू के भाजपा सदस्य जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण देकर उन्हें विकास के रास्ते पर लाया गया है। इसके पहले विपक्षी सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर में पंचायत एवं निकाय चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराने की मांग की। नेशनल कांफ्रेंस सदस्य हसनैन मसूदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले ही चुनाव आयोग से इस साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कहा था। केंद्र को शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप से पहले चुनाव कराने पर निर्णय लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले कहा था कि सरकार बड़े फैसले लेगी। ऐसा कोई फैसला लेने से पहले विधानसभा चुनाव कराकर पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए।

एलजी बोले, लोस चुनाव के तुरंत बाद कराए जाएंगे पंचायत व निकाय चुनाव : इस बीच, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। इसके लिए जनप्रतिनिधि अभी से तैयार रहें। विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयार रहें।

उपराज्यपाल ने कठुआ में एटामिक नार्थ मल्टीनेशनल कंपनी के आफिस का उद्घाटन किया। यह एक आइटी सेक्टर की कंपनी है जो कि बिजनेस प्रोसेस सर्विस देगी।

1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर लगेगी बाड़ : शाह

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के प्रति कटिबद्ध है। केंद्र सरकार ने पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है। बेहतर निगरानी के लिए सीमा के साथ-साथ एक पेट्रोलिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। कुल सीमा में से मणिपुर के मोरेह में 10 किलोमीटर के हिस्से में बाड़ लगाई भी जा चुकी है।

गृह मंत्री बोले-देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के प्रति केंद्र प्रतिबद्ध

शाह ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि हाईब्रिड सर्विलांस सिस्टम (एचएसएस) के माध्यम से बाड़ लगाने के लिए दो पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन प्रोजेक्टों के तहत अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में से प्रत्येक में पहले एक-एक किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने को भी मंजूरी मिल चुकी है।

बता दें कि गृह मंत्रालय के शीर्ष अफसरों ने पहले ही संकेत दिए थे कि केंद्र सरकार अवैध घुसपैठियों और विद्रोहियों का भारत में प्रवेश रोकने के लिए म्यांमार के साथ मुक्त आगमन व्यवस्था (एफएमआर) को खत्म करने पर विचार कर रही है। मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश तक फैली 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा एफएमआर के तहत संचालित होती है। यह भारत-म्यांमार सीमा के पास रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक-दूसरे के क्षेत्रों में 16 किलोमीटर आने-जाने की अनुमति देती है।

वैसे भी म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना इंफाल घाटी के मैतेयी समुदाय की लगातार मांग रही है। वे आरोप लगाते रहे हैं कि आदिवासी आतंकवादी अक्सर खुली सीमा से भारत में प्रवेश करते हैं। बिना बाड़ वाली सीमा का फायदा उठाकर इस रास्ते से भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी भी की जा रही है।

सिफारिश

जल संसाधनों पर स्थायी समिति ने अपनी 27वीं रिपोर्ट में की सिफारिश, झाग का बड़ा कारण बिना ट्रीटमेंट वाले सीवेज में फास्फेट और सर्फेक्टेंट्स की मौजूदगी

यमुना में झाग रोकने के लिए समूचे सीवेज के ट्रीटमेंट की जरूरत

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद की एक स्थायी समिति ने कहा है कि यमुना में झाग बनने से रोकने के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से इस नदी में प्रवाहित किए जाने वाले समूचे सीवेज का ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। यमुना में झाग का बड़ा कारण बिना ट्रीटमेंट वाले सीवेज में फास्फेट और सर्फेक्टेंट्स की मौजूदगी है। समिति का कहना है कि प्रदूषित नदी में झाग से त्वचा पर खुजली और संक्रमण हो सकता है।

जल संसाधनों पर स्थायी समिति ने अपनी 27वीं रिपोर्ट में रेखांकित किया है कि यमुना में झाग को दिल्ली में आइटी ब्रिज, ओखला व कालिंदी कुंज जैसे स्थानों पर देखा गया है। ओखला बैराज से नीचे की तरफ झाग ज्यादातर पानी के नीचे गिरने की वजह से बनता है। इस बैराज का रखरखाव उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, ओखला बैराज पर दिल्ली का पूरा पानी (ट्रीटमेंट वाला और बिना ट्रीटमेंट वाला) अवरुद्ध कर दिया जाता है और सिर्फ अतिरिक्त पानी ही नीचे छोड़ा जाता है। समिति ने रिपोर्ट में अपनी पहले की सिफारिशें दोहराई हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों (एसटीपी) की तकनीक को उन्नत बनाकर उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए और सभी उद्योगों को साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्रों से जोड़ा जाए।

यमुना से लगते बाढ़ वाले क्षेत्रों या वेटलैंड पर अतिक्रमण के मुद्दे पर समिति ने कहा कि सिर्फ दिल्ली और हरियाणा ने ही आवश्यक जानकारी मुहैया कराई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे यमुना बेसिन के राज्यों को भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। समिति ने अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे भी तीन महीने के भीतर जानकारी देने को कहा है।

समिति ने कहा है कि हथिनीकुंड बैराज पर उपलब्ध यमुना के पानी का पूरा इस्तेमाल कर लिया जाता है इसलिए वजीराबाद के नीचे गैर-मानसूनी मौसम में नदी में पानी का प्रवाह न के बराबर होता है। कृषि क्षेत्र में पानी की खपत को कम करने और यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए समिति ने नदी क्षेत्रों में माइक्रो व ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और वाटर हार्वेस्टिंग की सिफारिश की है। अवैध रेत खनन रोकने पर भी जोर दिया है।

दंडात्मक प्रविधान की सिफारिश : समिति ने जल संसाधन विभाग से ऐसे दिशानिर्देश या नियम तैयार करने सिफारिश की है, जिसमें यमुना सहित सभी नदियों में अपशिष्ट प्रवाहित करने के विरुद्ध दंडात्मक प्रविधान शामिल हों।

दिल्ली में नहाने योग्य नहीं : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत यमुना को तीन हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें पल्ला से ओखला तक बुनियादी रूप से दिल्ली का हिस्सा बेहद प्रदूषित है। समिति ने विभाग पाया कि यमुना का दिल्ली वाला हिस्सा (40 किलोमीटर) नहाने योग्य नहीं है।

कोष स्थापना का दिया सुझाव

समिति ने जल संसाधन विभाग को सुझाव दिया है कि वह यमुना नदी के लिए भी स्वच्छ गंगा कोष की तर्ज पर कोष स्थापित करने की संभावना तलाशे ताकि नदी को साफ करने से जुड़े कामों में पैसे की कमी से बाधा नहीं आए। समिति ने नमामि गंगे कार्यक्रम की सराहना भी की।

दिल्ली में यमुना की दुर्दशा। फाइल

देरी पर जताई नाखुशी

संसद की एक प्राक्कलन समिति ने अपनी 2018 की सिफारिशों पर एक्शन टेकन नोट्स दाखिल करने में पर्यावरण मंत्रालय की ओर से देरी पर नाखुशी व्यक्त की है। इस प्राक्कलन समिति ने मंगलवार को अपनी ताजा रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

****

25 मई 1999 को शरद पवार, पीए संगमा तथा तारिक अनवर ने की थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। विदेशी मूल की सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध करने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 7 फरवरी, 2024

फैसला आते ही शरद पवार गुट में निराशा, अजीत गुट में जश्न का माहौल

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- शरद गुट ने कहा, हमारा चिह्न भी शरद पवार, हमारी पार्टी भी शरद पवार
- अजीत बोले, लोकतंत्र में फैसला संख्या बल से होता है, यह हमारे साथ

चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार गुट को वास्तविक राकांपा करार दिए जाने के बाद मंगलवार को मुंबई में खुशी मनाते समर्थक। प्रेट्र

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) पर दावे को लेकर आए केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले के बाद जहां शरद पवार गुट में निराशा का माहौल है, वहीं अजीत पवार गुट ने पूरे महाराष्ट्र में जश्न मनाना शुरू कर दिया है। शरद पवार की सांसद पुत्री सुप्रिया सुले चुनाव आयोग के फैसले को 'अदृश्य शक्ति' की जीत बता रही हैं, तो उन्हीं के गुट के विधायक जीतेंद्र आह्वाड का कहना है कि हमारा चुनाव चिह्न भी शरद पवार हैं, और हमारी पार्टी भी शरद पवार हैं।

मंगलवार शाम चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद अजीत पवार ने कहा कि वह चुनाव आयोग के फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। लेकिन, शरद पवार गुट इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले ने दिल्ली में कहा कि जिसने पार्टी की स्थापना की और शून्य से यहां तक लेकर आए, आज उन्हीं को पार्टी से निकाल दिया गया। यह तो एक 'अदृश्य शक्ति' की ही विजय है। सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग के फैसले को षड्यंत्र बताते हुए कहा कि जो फैसला चुनाव आयोग ने पिछले वर्ष शिवसेना के बारे में सुनाया था, वही फैसला आज राकांपा के बारे में सुनाया है। सिर्फ पार्टियों के नाम बदल दिए हैं। सुले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टी संगठन से बनती है, न कि विधायकों की संख्या से। जबकि, चुनाव आयोग ने विधायकों की संख्या के आधार पर फैसला सुनाया है। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने अपनी 60 वर्ष की उम्र में एक नया दल खड़ा कर दिया था। अब हम पुनः एक नया दल खड़ा करेंगे। माना जा रहा है कि शरद पवार गुट अब शरद पवार के चेहरे को ही अपनी नई पार्टी के चुनाव चिह्न एवं शरद पवार के नाम 'शरद गोविंद चंद्र पवार' को पार्टी के नाम के रूप में चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। आयोग ने उसे बुधवार तक तीन नाम और तीन चिह्न देने के निर्देश दिए हैं। राकांपा पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि वह जल्द ही इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव से पहले ही इस मामले में हमें न्याय देगा।

दूसरी ओर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने चुनाव आयोग के निर्णय पर संतोष और खुशी जताते हुए कहा कि हम इस निर्णय को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। कुछ माह पहले महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद हमारी पार्टी का एक मसला चुनाव आयोग में गया था। वहां हमने अपना पक्ष रखा। चुनाव आयोग ने अब हमारी दलीलों को सही मानते हुए हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। इसी प्रकार का एक मामला राज्य विधानसभा अध्यक्ष के पास भी लंबित है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही उसका फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा। सुप्रिया सुले द्वारा यह कहे जाने पर कि पार्टी पर अधिकार संगठन से होता है, अजीत ने कहा कि राज्य के ज्यादातर जिलाध्यक्ष और विधायक हमारे साथ हैं। लोकतंत्र में संख्या बल से ही फैसला होता है। इसलिए, चुनाव आयोग ने संख्या बल देखते हुए हमारे पक्ष में निर्णय दिया है। वरिष्ठ नेता प्रफुल पटेल ने कहा कि इसका लाभ हमें चुनाव में भी मिलेगा।

अजीत पवार 40 विधायकों के साथ भाजपा और शिंदे गुट में हो गए थे शामिल

प्रथम पृष्ठ से आगे

इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा के पांच विधायक और लोकसभा के एक सदस्य ने दोनों ही पक्षों के साथ रहने को लेकर शपथ पत्र दिया था। गौरतलब है कि दो जुलाई 2023 को अजीत पवार 40 विधायकों के साथ भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने दावा किया था। इसके बाद यह पूरा मामला चुनाव आयोग पहुंचा था।

पार्टी किसकी होगी, यह कैसे होता है तय : पार्टी से जुड़े विवाद का फैसला मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर किया जाता है। पहला, चुने हुए प्रतिनिधि किस गुट के पास ज्यादा हैं। दूसरा, पार्टी के पदाधिकारी किसके पास ज्यादा हैं और तीसरा, पार्टी से जुड़ी संपत्तियों पर कौन काबिज है। लेकिन, पार्टी पदाधिकारियों और संपत्तियों को लेकर पारदर्शी प्रक्रिया न होने से किस गुट को असली पार्टी माना जाए इसका फैसला आमतौर पर चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर होता है। समाजवादी पार्टी और शिवसेना से जुड़े विवादों में भी आयोग ने इस फार्मूले पर निर्णय दिया था।

महाराष्ट्र देश की दिशा तय करेगा : उद्धव

मुंबई, प्रेट्र: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र देश की दिशा तय करेगा। एक भगवा तूफान दिल्ली से टकराएगा और तानाशाही को उखाड़ फेंकेगा। मुंबई स्थित अपने आवास मातोश्री में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि तानाशाही विकल्प नहीं हो सकती। इसे जड़ से उखाड़ फेंका जाना चाहिए। अपने नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने वाले मराठवाड़ा के लोगों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि कुछ लोगों के मन में विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए और महाविकास आघाडी (एमवीए) को लेकर सवाल है, लेकिन विकल्प कहां है।

उद्धव ठाकरे। फाइल

ठाकरे ने दावा किया कि भाजपा के कई कार्यकर्ता और मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मन की बात और जन की बात के बीच कोई संबंध नहीं है।

एक महीने में दो लाख गांवों तक पहुंचेगी भाजपा

नड्डा 12 फरवरी को मुजफ्फरनगर से करेंगे भाजपा किसान मोर्चा की ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ

पार्टी ने इस यात्रा के माध्यम से हर दिन प्रत्येक जिले में पांच गांवों तक पहुंचने का रखा है लक्ष्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- उपलब्धियां गिनाने के साथ ही किसानों से संकल्प पत्र के लिए सुझाव भी लेगा किसान मोर्चा

जेपी नड्डा। फाइल

लोकसभा चुनाव में भाजपा की 370 से अधिक और राजग की 400 पार सीटों का जो बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिखाया है, उसकी जमीन तैयार करने के लिए पार्टी संगठन ने कमर कस ली है। चुनाव परिणामों पर सीधा असर डालने वाली ग्रामीण आबादी के बीच अपनी पैठ को और गहरा करने के लिए भाजपा ने मात्र एक माह में ही देश के दो लाख से अधिक गांवों तक पहुंचने का कार्यक्रम बनाया है। भाजपा किसान मोर्चा की इस गांव परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 फरवरी को मुजफ्फरनगर से करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी अपनी प्राथमिकता में जिन चार जातियों को गिनाते हैं उनमें महिला, युवा और गरीब के साथ ही किसान भी हैं। लिहाजा आगामी लोकसभा चुनाव में भी किसानों को भाजपा के पाले में अधिक से अधिक संख्या में बनाए रखने के लिए भाजपा ने प्रयास तेज कर दिए हैं। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि मोर्चा द्वारा देशभर में गांव परिक्रमा यात्रा निकाली जाएगी। 12 फरवरी को मुजफ्फरनगर में गौ माता, ट्रैक्टर और हल के पूजन के साथ भाजपा अध्यक्ष नड्डा इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वह किसानों और मजदूरों की जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों और प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया जाएगा। यात्रा के शुभारंभ समारोह का सीधा प्रसारण देश के सभी संगठनात्मक जिलों में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया जाएगा, जिनमें प्रत्येक स्थान पर 300 से अधिक किसानों को आमंत्रित किया जाएगा।

किसान मोर्चा अध्यक्ष ने बताया कि एक माह के इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभर के दो लाख से अधिक गांवों की परिक्रमा का लक्ष्य है। परिक्रमा के दौरान ग्राम देवता, गौ माता, कृषि संयंत्र, ट्रैक्टर और हल का पूजन किया जाएगा। डोर-टू-डोर अभियान चलाकर किसानों-मजदूरों और ग्रामीणों के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करने के साथ ही लोकसभा चुनाव- 2024 के संकल्प पत्र के लिए किसानों से सुझाव भी लिए जाएंगे। देशभर से एकत्र उन सुझावों को पार्टी अध्यक्ष नड्डा को सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि यह यात्रा प्रत्येक जिले में प्रतिदिन पांच गांवों में निकाली जाएगी। हर जिले में 2000 किसानों को एकत्र करने का लक्ष्य तय किया गया है।

पांच फिल्में सुनाएंगी मोदी की पूरी हुई गारंटी की गाथा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- भाजपा ने इंटरनेट मीडिया पर लांच की मुद्रा, आवास, उज्ज्वला, यूपीआइ और जनधन योजना की फिल्में
- 'सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं' के तराने में हैं दस वर्ष की उपलब्धियां

जनता के मन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी गारंटी (मोदी की गारंटी) के जरिये विश्वास भरने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसे अब लोकसभा चुनाव अभियान के रूप में जन-जन तक पहुंचाने की भाजपा की तैयारी है। इसके लिए सिर्फ भविष्य के वादों का ही सहारा नहीं है, बल्कि भाजपा ने मोदी सरकार के 10 वर्षों में पूरे किए गए वादों और उपलब्धियों को तराने में पिरोते हुए 'सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं' थीम सांग पर आठ भाषाओं में पांच फिल्में लांच की हैं।

लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ वापसी के लिए भाजपा ने अपने प्रचार अभियान को तेजी देना शुरू कर दिया है। मजबूत संगठन के आधार के साथ ही भाजपा को पीएम मोदी के आकर्षण पर सबसे अधिक विश्वास है। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली बड़ी विजय ने भाजपा के विश्वास को और अधिक बल दिया है कि जनता मोदी की गारंटी पर कहीं अधिक भरोसा करती है।

यही वजह है कि आज के दौर में प्रचार के बेहद सशक्त माध्यम इंटरनेट मीडिया पर पार्टी ने इसी सोच को प्रदर्शित करते हुए प्रचार अभियान शुरू किया है। इसके लिए बड़े लाभार्थी वर्ग वाली योजनाओं पीएम मुद्रा योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, यूपीआइ और पीएम आवास योजना पर 'सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं' थीम सांग के साथ फिल्में लांच की हैं। ये फिल्में हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल भाषा में हैं। इन्हें प्रधानमंत्री मोदी के अधिकृत एक्स हैंडल, भाजपा के सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म, नमो एप पर साझा किया गया है। भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्यों के मंत्री और वालंटियर्स द्वारा साझा किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस थीम सांग की लांचिंग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दौरान तब लांच किया गया था, जब पीएम मोदी ने देशभर के 40 लाख से अधिक नए मतदाताओं को वर्चुअल संबोधित किया था।

अपनी हताशा से नहीं निपट पा रही कांग्रेस : मेघवाल

नई दिल्ली, एएनआइ: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए बिखर रहा है इसलिए पार्टी अपनी हताशा से निपट नहीं पा रही है।

अर्जुन मेघवाल। फाइल

पत्रकारों से वार्ता में मेघवाल ने कहा, 'उत्तर प्रदेश और बिहार में वे पर्याप्त सीटें नहीं जीतेंगे। यहां तक कि उनके गठबंधन सहयोगी भी उन्हें सीटें नहीं दे रहे हैं, जीतने की बात तो छोड़ ही दीजिए।' दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी के उस दावे पर भी केंद्रीय मंत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि कांग्रेस को अपने लिए राहुल गांधी के अलावा कोई और चेहरा चुनने पर फोकस करना चाहिए। मेघवाल ने कहा कि शर्मिष्ठा मुखर्जी से नाराज होने के बजाय कांग्रेस को तथ्यों परखने के लिए प्रणब मुखर्जी की डायरियों को देखना चाहिए। उन्होंने कहा, 'अगर प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की थी तो वे उसे डायरी में चेक कर सकते हैं। आप शर्मिष्ठा को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं?' उल्लेखनीय है कि शर्मिष्ठा मुखर्जी ने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है, 'प्रणब माई फादर : ए डाटर रिमेंबर्स।'

'कमल नाथ के लिए हमारे दरवाजे बंद'

नईदुनिया, छिंदवाड़ा: लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने मंगलवार को छिंदवाड़ा पहुंचे भाजपा के क्लस्टर प्रभारी और प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। भाजपा जल्द ही छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए विजयवर्गीय ने दावा किया कि भाजपा छिंदवाड़ा लोकसभा सीट लाखों वोटों से जीतेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि छिंदवाड़ा के पार्टी संगठन में लोकसभा चुनाव तक कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। वर्तमान टीम ही लोकसभा चुनाव तक काम करेगी। उल्लेखनीय है कि यह भी चर्चा हो रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ व सांसद नकुल नाथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं।

कैलाश विजयवर्गीय। फाइल

कर्नाटक सरकार को गाय विरोधी बताते हुए भाजपा ने किया प्रदर्शन

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक में भाजपा ने मंगलवार को राज्य की कांग्रेस सरकार पर गाय विरोधी होने का आरोप लगाते हुए मवेशियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेता गायों के साथ यहां फ्रीडम पार्क में एकत्र हुए। उन्होंने गायों पर बैनर लगाए हुए थे। उन पर लिखा था- यह सरकार पशुधन के पक्ष में नहीं है।

पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि बेंगलुरु शहरी और बेंगलुरु ग्रामीण जिलों में पशु चिकित्सा अस्पताल अपर्याप्त संख्या हैं। यही नहीं, कई मौजूदा अस्पतालों को भी अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि इसके बाद से इस क्षेत्र में दूध का उत्पादन घट गया है। पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के राज्य महासचिव पी राजीव ने आरोप लगाया कि सिद्दमैया सरकार गाय विरोधी है क्योंकि वह बेंगलुरु में कोई गाय नहीं चाहती। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार ने अपनी पशु विरोधी नीति नहीं छोड़ी तो गायों के साथ विधान सौध (कर्नाटक राज्य विधानमंडल-सचिवालय परिसर) का घेराव किया जाएगा।

इस अवसर पर रायथा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एएस नादहल्ली ने कांग्रेस सरकार पर पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हित में शुरू की गई योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया।

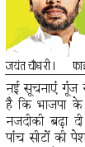

रालोद और भाजपा में बात बढ़ी... पांच सीटों की पेशकश

आशु सिंह, बागपत

- एनडीए के बढ़ते कुनबे के बीच रालोद से नए सिरे से बात
- सपा और रालोद गठबंधन में कुछ सीटों पर फंसा है पेच

एनडीए के बढ़ते कुनबे के बीच क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षाएं भी हिलोरें ले रही हैं। केंद्र में अपना खोया वजूद पाने का प्रयास कर रहा राष्ट्रीय लोकदल भी हर हलचल पर नजर रखे हुए है। रालोद अध्यक्ष जयन्त चौधरी पूरे परिदृश्य को सधे अंदाज में देख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में रोज नई सूचनाएं गूंज रही हैं। इसी बीच खबर है कि भाजपा के एक धड़े ने रालोद से नजदीकी बढ़ा दी है। रालोद को उप्र में पांच सीटों की पेशकश की गई है।

जयंत चौधरी। फाइल

रालोद के एनडीए के साथ जाने की नई चर्चा उस समय तेज हुई जब 12 फरवरी को चौधरी अजित सिंह की जन्मतिथि पर छपरौली में उनकी प्रतिमा के अनावरण का होने वाला कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। हालांकि, पार्टी की ओर से इसका कारण खराब मौसम बताया गया। कार्यक्रम में जयन्त चौधरी को आना था। हर जिले से कार्यकर्ता बुलाए गए थे। कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार जोरशोर से कार्यकर्ता कर रहे थे। बता दें कि रालोद का सपा से गठबंधन हो चुका है, लेकिन सपा की कुछ शर्तों के कारण गठबंधन में दरार नजर आने लगी है। सूत्रों के अनुसार सपा ने रालोद को सात सीटें देने का भरोसा दिया है। ये बागपत, कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ या अमरोहा, हाथरस और मथुरा हैं। सपा ने कैराना, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में प्रत्याशी अपना और निशान रालोद का रखने की शर्त रखी है। रालोद कैराना और बिजनौर पर तो राजी है, लेकिन मुजफ्फरनगर पर पेच फंस गया है। रालोद ने ऐसी स्थिति में अपनी सीटें बढ़ाने की बात रखी है। वहीं, अब भाजपा ने रालोद को पांच सीटें बिना शर्त देने की पेशकश की है। ये सीटें कैराना, बागपत, अमरोहा, मथुरा और मुजफ्फरनगर हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा का एक धड़ा रालोद को अपने खेमे में लाना चाहता है। इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अबकी बार 400 पार का लक्ष्य भेदने में आसानी होगी। बता दें कि पश्चिमी उप्र की 12 सीटों पर रालोद का खासा प्रभाव है। जिस गठबंधन में रालोद रहेगा उसका पलड़ा यहां भारी हो जाएगा। सपा परिवार की फिरोजाबाद और बदायूं जैसी सीटों पर रालोद का अच्छा खासा वोट बैंक है। इन सीटों पर भाजपा की नजर है।

राजग में शामिल होने को एएमएमके भाजपा से मांगेगी चार से छह सीटें

चेन्नई, आइएएनएस: तमिलनाडु में राजग में शामिल होने के लिए अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) ने चार से छह सीटों की मांग की है। सूत्रों के अनुसार, अन्नाद्रमुक की पूर्व अंतरिम महासचिव वीके शशिकला के भतीजे व पार्टी संस्थापक टीटीवी दिनाकरन इस बात पर अड़े हैं कि उनकी पार्टी दक्षिण तमिलनाडु में थेवर समुदाय के गढ़ों में चुनाव लड़ेगी। अन्नाद्रमुक से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा खुद को राज्य के कुछ इलाकों में प्रभाव रखने वाली पार्टियों से गठजोड़ करने की कोशिश कर रही है। एएमएमके अन्नाद्रमुक से अलग हुआ समूह है। इसे दक्षिण तमिलनाडु के शक्तिशाली थेवर समुदाय का मजबूत समर्थन प्राप्त है और 2019 के आम चुनाव में पार्टी 8.6 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया था। पार्टी ने दक्षिण तमिलनाडु की थेनी, विरुधुनगर, रामनाथपुरम और शिवगंगा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। एएमएमके इन चार सीटों के अतिरिक्त भाजपा से मदुरै और तिरुनेलवेली सीटों की भी मांग करेगी। अन्नाद्रमुक से निष्कासित दिग्गज नेता व पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम भी दक्षिण तमिलनाडु में शक्तिशाली चेहरा है और थेवर समुदाय से आते हैं।

टीटीवी दिनाकरन।

भाजपा को कुत्तों से क्या परेशानी है, समझ नहीं आता : राहुल

जागरण टीम, गुमला

- गुमला में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कार्यकर्ता को कुत्ते का बिस्किट खिलाने पर दी सफाई
- झारखंड के खूंटी, गुमला, सिमडेगा से होकर ओडिशा के राउरकेला की ओर बढ़ी न्याय यात्रा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को झारखंड में न्याय यात्रा के दौरान खूंटी जिले के तोरपा स्थित भालू टोली में ग्राम प्रधान एनम टोपनो के घर पहुंचे और उनसे काफी देर तक बात की। इस क्रम में राहुल ने टोपनो से तीर-धनुष चलाने के गुर भी सीखे। जागरण

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा के क्रम में मंगलवार को झारखंड के खूंटी व गुमला में रैली कर जनसभाओं को संबोधित किया। गुमला में मीडिया से बात करते हुए राहुल ने कार्यकर्ता को बिस्किट खिलाए जाने के मामले में सफाई दी। साथ ही तंज कसा कि भाजपा को कुत्तों से क्या परेशानी है, यह समझ में नहीं आता।

दरअसल, भाजपा ने राहुल से संबंधित एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। उक्त वीडियो में राहुल एक कुत्ते को बिस्किट खिलाते दिख रहे हैं। जब कुत्ते ने बिस्किट नहीं खाया तो राहुल ने वही बिस्किट बगल में खड़े एक व्यक्ति को दे दिया, जिसके बारे में भाजपा के नेता कांग्रेस कार्यकर्ता होने का दावा कर रहे हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर जमकर राहुल की खिंचाई की। इस संबंध में सफाई देते हुए राहुल ने कहा कि जब मैंने कुत्ते को बिस्किट दिया तो उसने मेरे हाथ से नहीं खाया। इसलिए मैंने बगल में खड़े कुत्ते के मालिक को बिस्किट दिए, ताकि वह कुत्ते को खिला दें। इसके बाद कुत्ते ने अपने मालिक के हाथ से बिस्किट खा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या समस्या है। प्रेस वार्ता में मौजूद झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि यह वीडियो चार फरवरी का है, जब राहुल अपनी न्याय यात्रा के क्रम में झारखंड के धनबाद में थे। खूंटी में राहुल गांधी ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके वंशजों को सम्मानित किया। के राउरकेला पहुंची।

ममता बनर्जी आइएनडीआइए का हिस्सा हैं, सीटों पर जारी है बातचीत

राहुल गांधी ने गुमला में न्याय यात्रा के क्रम में कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आएनडीआइए का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन के सदस्यों के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। बता दें कि पिछले हफ्ते बनर्जी ने कहा था कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। यहां से राहुल की यात्रा ओडिशा के राउरकेला पहुंची। जातिगत जनगणना की वकालत करते हुए राहुल ने कहा कि जनसंख्या के अनुसार लोगों की भागीदारी सभी जगह होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। अखिलेश अमेठी या रायबरेली में यात्रा में शामिल होंगे।

****

कांग्रेस हाईकमान ने बंगाल में शुरू कीं लोस चुनाव की तैयारियां, चुनाव कमेटी गठित

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस से सीटों पर समझौते की आस के बीच कांग्रेस हाईकमान ने बंगाल में लोकसभा (लोस) चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बाबत पार्टी के राज्य अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में 28 सदस्यीय चुनाव कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में प्रदीप भट्टाचार्य, दीपा दासमुंशी, अब्दुल मन्नान, मनोज चक्रवर्ती, शंकर मालाकार, निलय प्रमाणिक, सुजय घटक, माया घोष, मनोरंजन हालदार समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कमेटी लोस चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन व प्रचार की रणनीति तय करेगी। राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के इस कदम को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बंगाल में तृणमूल के साथ गठबंधन चाहता है और इस बाबत प्रयास भी किया जा रहा है लेकिन इसके कारण वह लोस चुनाव की तैयारियों में पिछड़ना नहीं चाहता।

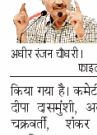

अधीर रंजन चौधरी। फाइल

हेमंत सोरेन की भाभी को चम्पाई कैबिनेट में मिल सकता मौका

राज्य ब्यूरो, रांची

- सीता सोरेन ने कहा- कभी नहीं थी नाराज, फैलाई गई अफवाह
- कैबिनेट में जगह पाने के लिए नेताओं के बीच लाबिंग हो गई तेज

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को चम्पाई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। सीता दुमका जिले के जामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने मंगलवार को मीडिया के सवालों पर कहा कि वह कभी भी मुख्यमंत्री या मंत्री पद को लेकर नाराज नहीं थीं। नाराजगी की सभी बातें अफवाह हैं। हालांकि मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए जाने की संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा (झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन) का आशीर्वाद मिलेगा तो वह जरूर मंत्री बनेंगी। पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, उसका वे निर्वहन करेंगी।

वहीं, चम्पाई कैबिनेट में जगह पाने के लिए लाबिंग भी तेज हो गई है। कैबिनेट विस्तार में झामुमो और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के पद भरे जाएंगे। जानकारी के अनुसार बहुत ज्यादा फेरबदल होने की संभावना नहीं है। झामुमो में इसे लेकर एक हद तक स्पष्टता है। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को लेकर उत्सुकता ज्यादा है। पार्टी के विधायकों ने चेहरे बदलने का दबाव बढ़ाया है। ऐसे में कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्तता के कारण इसपर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता आपसी सहमति से इसपर निर्णय करेंगे। जानकारी आलाकमान को दी जाएगी।

सीता सोरेन। जागरण आर्काइव

1,344 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से गुजरात के मेहसाणा से अयोध्या के लिए रवाना हुए। यह गुजरात से रवाना होने वाली 26 आस्था विशेष ट्रेनों में से पहली ट्रेन है।

देवभूमि की ऊर्जा के सहारे दूसरे राज्यों पर दबाव बढ़ाएंगे हिंदू संगठन

यूसीसी के समर्थन में विहिप व संत समिति, अन्य राज्यों में लागू करने की दोहराई मांग

अयोध्या में विहिप की केंद्रीय प्रबंध समिति व प्रन्यासी मंडल की बैठक में बनेगी रणनीति

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की लंबे अर्से से पैरोकारी कर रहे हिंदू संगठनों को देवभूमि ने नई ऊर्जा दी है। अब वे उत्तराखंड सरकार के ऐतिहासिक निर्णय के सहारे दूसरे राज्यों में भी कानून में समानता को लेकर दबाव बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, जहां विशेष रूप से यूसीसी को लेकर विमर्श तेज है। विहिप की कोशिश होगी कि इसके लिए जनमत भी तैयार हो। इसी माह अयोध्या में 25 से 27 फरवरी तक आयोजित केंद्रीय प्रबंध समिति और प्रन्यासी मंडल की तीन दिवसीय शीर्ष बैठक में इसके लिए नए सिरे से रणनीति तैयार की जाएगी। विहिप और अखिल भारतीय संत समिति जैसे संगठनों ने विशेष रूप से उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी से संबंधित विधेयक रखे जाने पर हर्ष व्यक्त किया है। संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती ने उत्तराखंड सरकार को बधाई देते हुए कहा कि इसे पूरे देश में लागू करने की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से एक राष्ट्र, एक जन व एक कानून की मांग कर रहे हैं।

स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती। फाइल

मैं प्रसन्न हूं कि यूसीसी कानून लाया गया है। कोई धार्मिक प्रथा संविधान की भावना के विपरीत है। उसे चलने नहीं दिया जा सकता है। सब समाजों में कुछ-कुछ विकृतियां आ गई हैं। उसे दूर किया जाना आवश्यक है। स्थापित किया गया है।

– आलोक कुमार, कार्याध्यक्ष, विहिप

'मुस्लिम बेटियों के लिए संजीवनी'

जागरण संवाददाता, देहरादून

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि यूसीसी विधेयक लागू होने पर न केवल मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत देगा, बल्कि मुस्लिम बेटियों के लिए संजीवनी साबित होगा। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि इससे मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के अंतर्गत वर्षों से चली आ रही तीन तलाक व हलाला जैसी कुप्रथा का अंत होगा और समान कानून व्यवस्था के तहत मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय मिलेगा। मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए यह कानून मील का पत्थर साबित होगा और इससे उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। उत्तराखंड सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। तीन तलाक का मुद्दा उठाने वालीं उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष शायरा बानो ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे। विधेयक लागू होना बड़ी बात है।

शादाब शम्स, अध्यक्ष, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड

मुफ्ती शमून, अध्यक्ष, मदरसा शिक्षा परिषद

मौलाना अरशद मदनी

मदनी ने कहा-मुस्लिमों को भय में रखने की कोशिश

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने विरोध करते हुए कहा कि मुस्लिमों के कानून इंसानों का बनाया नहीं, बल्कि कुरान और हदीस द्वारा बनाया गया है। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, अपनी शरीयत से समझौता नहीं कर सकता। यूसीसी लागू करना नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात करने की एक सोची समझी साजिश है।

चार खंडों में विभाजित है विधेयक

प्रथम पृष्ठ से आगे

पहला खंड : विवाह और विवाह-विच्छेद

- सभी धर्मों में विवाह के लिए समान उम्र का प्रविधान। लड़की की न्यूनतम आयु 18 व लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष।
- बहु विवाह व बाल विवाह अमान्य।
- विवाह के पक्षकार निषेध रिश्तेदारी की डिग्रियों के भीतर न हों। इस डिग्री में सगे रिश्तेदारों से संबंध निषेध। यह उन पर लागू नहीं होगा, जिनकी रूढ़ि और प्रथा ऐसे संबंधों में उनके विवाह की अनुमति देते हों।
- 26 मार्च, 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य। विवाह विच्छेद का पंजीकरण भी अनिवार्य।
- पंजीकरण न कराने पर विवाह मान्य, लेकिन अधिकतम तीन माह तक का कारावास और अधिकतम 25 हजार रुपये तक का जुर्माना।
- विधिक प्रक्रिया से ही होगा विवाह-विच्छेद।
- विवाह-विच्छेद के संबंध में याचिका लंबित रहने पर भरण-पोषण और बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में प्रविधान।
- यूसीसी की धाराओं के उल्लंघन पर छह माह तक का कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की व्यवस्था। विवाह-विच्छेद के मामलों में तीन वर्ष तक का कारावास होगा।
- पुनर्विवाह के लिए तय नियम के उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना व छह माह तक का कारावास।

दूसरा खंड: उत्तराधिकार में महिलाओं को समान अधिकार

- संपत्ति में सभी धर्मों की महिलाओं को समान अधिकार।
- सभी जीवित बच्चे, पुत्र अथवा पुत्री संपत्ति में बराबर के अधिकारी।
- व्यक्ति की वसीयत नहीं है और उसकी कोई संतान अथवा पत्नी नहीं है तो उत्तराधिकार के लिए रिश्तेदारों को प्राथमिकता।

तीसरा खंड: लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकरण अनिवार्य

- पंजीकरण न कराने पर अधिकतम तीन माह का कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना।
- लिव इन अवधि में पैदा होने वाला बच्चा वैध संतान माना जाएगा।
- निषेध डिग्री के भीतर वर्णित संबंधों को लिव इन में रहने की अनुमति नहीं। यह उन पर लागू नहीं होगा, जिनकी रूढ़ि और प्रथा ऐसे संबंधों में उनके विवाह की अनुमति देते हों।
- यद्यपि ऐसी रूढ़ि और प्रथा लोकनीति और नैतिकता के विपरीत नहीं होनी चाहिए।
- किसी एक पक्ष के नाबालिग अथवा विवाहित होने पर लिव इन की अनुमति नहीं।
- लिव इन संबंध कोई भी पक्ष समाप्त कर सकता है। निबंधक और लिव इन पार्टनर को देनी होगी जानकारी।
- गलत जानकारी देने अथवा नोटिस के बाद भी जानकारी न देने पर अधिकतम छह माह का कारावास अथवा अधिकतम 25 हजार रुपये जुर्माना।
- यदि कोई पुरुष महिला को छोड़ता है तो वह उससे भरण पोषण की मांग कर सकती है।

चौथा खंड: नियम बनाने की शक्ति सरकार में निहित

- किसी भी प्रकार का संदेह दूर करने के लिए उत्तराखंड में विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2010 को निरस्त करने की संस्तुति।

न्यूज गैलरी

लद्दाख के मुद्दों पर भाग लेंगे दोनों संगठनों के प्रतिनिधि

जम्मू : लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर 19 फरवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में होने वाली उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी की बैठक में लेह अपेक्स बाडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के सदस्य भाग लेंगे। लेह अपेक्स बाडी की बैठक मंगलवार को लद्दाख में वरिष्ठ नेता थुप्सन शेवांग की अध्यक्षता में हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आए निमंत्रण पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान लेह अपेक्स बाडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि वे 19 फरवरी को होने वाली दूसरे दौरे की बैठक में भाग लेंगे और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। (राब्यू)

पूरे दक्षिण का बजट उत्तर प्रदेश के बजट से कम'

बेंगलुरु : कांग्रेस के लोकसभा सांसद डीके सुरेश ने मंगलवार को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भेदभावपूर्ण बजट आवंटन करने और दक्षिण भारतीय राज्यों को धोखा देने का आरोप लगाया। सुरेश ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया– "दक्षिण भारतीय राज्य टैक्स में सबसे अधिक योगदान करते हैं लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। पूरे दक्षिण का बजट आवंटन दो लाख करोड़ रुपये से कम है, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश का ही बजट आवंटन दो लाख करोड़ रुपये है। सुरेश ने हाल ही में यह कहकर भी विवाद खड़ा कर दिया था कि धन के आवंटन में भेदभाव के चलते दक्षिणी राज्यों को एक अलग देश की मांग करनी पड़ सकती है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने केंद्र द्वारा राज्य को कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान में कमी के विरोध में दिल्ली चलने का आह्वान किया। (एएनआइ)

नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म में 123 साल की सजा

तिरुअनंतपुरम : केरल की एक अदालत ने मंगलवार को 2022 में दो नाबालिग बेटियों में से बड़ी के साथ बार-बार दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 123 साल की सजा सुनाई। छोटी बेटी का यौन उत्पीड़न करने पर तीन साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को धारा 376(3) (16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार), धारा 5 (एल) व 5 (एम) के तहत 40-40 साल की सजा व पाक्सो अधिनियम-किशोर अधिनियम की धारा 75 के तहत तीन साल की सजा सुनाई। सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। (प्रेट्र)

रामलला के दरबार में नतमस्तक हुई अरुणाचल सरकार

जागरण संवाददाता, अयोध्या

- मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कैबिनेट के साथ किया रामलला का दर्शन
- नित्य नए आयाम गढ़ रहा रामलला को शिरोधार्य करने का महोत्सव

रामलला के प्रति आदर-अनुराग की व्यापकता-विविधता मंगलवार को भी पूरी मोहकता से प्रवाहित हुई, जब रामलला के दरबार में पूरी अरुणाचल सरकार श्रद्धावनत होने पहुंची। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनकी कैबिनेट के सदस्यों, विधायकों एवं अधिकारियों सहित अरुणाचल के 70 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की आस्था महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही छलकी। उन्होंने न केवल एयरपोर्ट पर चार्टर्ड विमान से उतरते ही जयकारा लगाया, बल्कि कुछ ने मोक्षदायिनी नगरी की रज भी शिरोधार्य की। आस्था से अभिभूत अतिथियों का स्वागत भी अभिभूत करने वाला सिद्ध हुआ।

स्वागत में तिलक, पुष्पहार धारण कराने के साथ उन पर पुष्पवर्षा भी की गई, तो अवध के प्रतिनिधि नृत्य फरवाही की प्रस्तुति से भी उन्हें रिझाया गया। कुछ ही देर बाद विभोरजन्य आत्मीयता का चरम रामलला के सम्मुख परिभाषित हुआ। मौन और किंचित नम आंखों के साथ रामलला को आत्मस्थ करने के बाद अतिथियों की शारीरिक भाव-भाषा में दिव्यता का पुट समाहित हुआ।

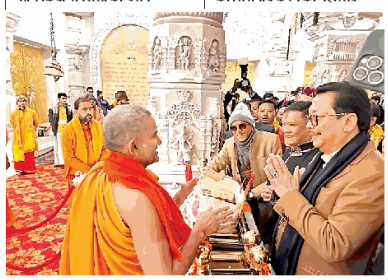

रामलला के सम्मुख श्रद्धावनत अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को प्रसाद देते रामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य एवं उडुपी पीठाधिपति स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ(बाएं) एवं इस अवसर पर उपस्थित ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय, दाएं से तीसरे) : जागरण

...तो श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय, सदस्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ एवं डा. अनिल मिश्र ने अपनी आत्मीयतापूर्ण अगवानी से उन्हें भाव विभोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

अरुणाचल भवन निर्माण के लिए पत्र : सीएम खांडू ने कहा कि अयोध्या में अरुणाचल भवन निर्माण कराए जाने को लेकर हमने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। राम मंदिर निर्माण के बाद अब देश विकास की नई गाथा लिखेगा।

दिल्ली, हिमाचल, बिहार व झारखंड से पहुंचे श्रद्धालु

जासं, अयोध्या: अलग-अलग भाषा, प्रांत और यहां तक कि कुछ का पहनावा भी... लक्ष्य सिर्फ एक। अपने रामलला को जी भर देखना...। ऐसे मनोभावों से ओत-प्रोत हो मंगलवार को दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार व झारखंड से रामभक्त अयोध्या पहुंचे। भोर में तीन बजे के करीब हिमाचल प्रदेश से भक्तों के ट्रेन से उतरते ही जय श्रीराम की अनुगूंज से कैंट रेलवे स्टेशन गूंज उठा। हिमाचल से आई सुमन कहती हैं, यहां आकर सब भूल गए। उनके नेत्र भी थोड़े सजल थे।

अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीन एआरएम तैनात

जासं, लखनऊ: रामनगरी अयोध्या में लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्हें आवागमन में असुविधा न हो इसके लिए तीन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों (एआरएम) को नियुक्त किया जा रहा है। तीनों अधिकारी एक सप्ताह तक अयोध्या में रहकर श्रद्धालुओं की देखरेख करेंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक अयोध्या ने परिवहन निगम मुख्यालय को सूचित किया था कि रामनगरी में तीन फरवरी से बड़ी संख्या आस्था स्पेशल से श्रद्धालु पहुंचेंगे।

नई दिल्ली में मंगलवार को भेंट के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का अभिवादन करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

भारत की सांस्कृतिक विरासत, राजनीति में आडवाणी का अमूल्य योगदान : अमित शाह

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उन्हें भारत रत्न मिलने पर बधाई दी। अमित शाह ने कहा कि आडवाणी ने देश की सांस्कृतिक विरासत, राजनीति और प्रगति में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि आडवाणी जी आज भेंट कर शुभकामना दीं। पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न देने का निर्णय लेकर उनके अथक संघर्षों व योगदान को सम्मानित करने का काम किया है।

मस्जिद पक्ष का दावा– बिना अर्जी जिला जज ने दिया पूजा का अधिकार

- मंदिर पक्ष ने कहा– जिला जज ने धारा 151के तहत विवेकाधिकार का उपयोग किया
- उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को मीडिया ट्रायल से बचने की सलाह भी दी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तलगृह में पूजा का अधिकार देने वाले तत्कालीन जिला जज के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को दो घंटे सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ के समक्ष मस्जिद पक्ष ने तर्क रखा कि कि जिला जज ने बिना अर्जी पूजा का अधिकार दिया है, तो मंदिर पक्ष ने कहा कि आग्रह पर धारा 151 के तहत विवेकाधिकार से यह आदेश जिला जज ने दिया है। अर्जी मंजूर होने के बाद उसी पर बिना किसी अर्जी के दोबारा आदेश दिया जा सकता है, इसी कानूनी मुद्दे पर बुधवार सुबह 10 बजे से सुनवाई होगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को मीडिया ट्रायल से बचने की सलाह भी दी है।

अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने अपील दाखिल कर डीएम को परिसर का रिसीवर नियुक्त करने संबंधी जिला जज के 17 जनवरी, 2024 के आदेश को भी चुनौती दी है। पूजा का अधिकार देने वाले 31 जनवरी, 2024 के आदेश की चुनौती अपील में भी संशोधन अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

मस्जिद पक्ष की दलील: अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता एसएफए नकवी व पुनीत गुप्ता ने तर्क दिया कि जिला जज ने वादी की अर्जी को जब 17 जनवरी को मंजूर कर डीएम को रिसीवर नियुक्त करने की मांग मान ली तो बिना किसी अर्जी के 31 जनवरी 2024 का आदेश कैसे पारित किया? इसे रद किया जाए। यह भी कहा कि वादी कभी भी पूजा नहीं करता था और यह कहना सही नहीं है कि 1993 में लोहे की बैरिकेडिंग के कारण पूजा करने से रोक दिया गया। प्रश्न यह भी उठा कि क्या परिसर मस्जिद पक्ष के कब्जे में था? हस्तक्षेप के लिए क्या मस्जिद पक्ष के कब्जे का कोई साक्ष्य है?

मंदिर पक्ष का जवा: मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 17 जनवरी को अर्जी मंजूर करते हुए जिला जज ने पहली मांग पर डीएम को रिसीवर नियुक्त करने का निर्देश दिया है। डीएम ने 24 जनवरी को परिसर अपने कब्जे व सुरक्षा में ले लिया।

बंद तलगृहों के सर्वे की मांग पर मस्जिद पक्ष ने की आपत्ति

ज्ञानवापी के बंद तलगृहों का एएसआइ से सर्वे कराने की मांग के प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से सर्वे की मांग पर आपत्ति की गई। अदालत ने सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख दी है।

...तो तेजस्वी को शराब पीने वाला बताने पर रद की गई राजद एमएलसी की सदस्यता

राज्य ब्यूरो, पटना

- पार्टी के आवेदन पर परिषद के सभापति ने रद की प्रो. रामबली सिंह की सदस्यता
- पिछले साल के प्रसारित वीडियो में शराब पर चर्चा करते दिखे थे

शराबबंदी कानून के दायरे में सिर्फ शराब पीने वाले ही नहीं आ रहे हैं। शराब की चर्चा करने वाले भी आ रहे हैं। बिहार विधान परिषद के राजद सदस्य (एमएलसी) प्रो. रामबली सिंह की सदस्यता रद हो गई। कई कारणों में से एक यह भी बताया गया कि उन्होंने एक वीडियो में शराब की चर्चा की थी। वह प्रसारित हो गया। वीडियो में प्रो. रामबली बता रहे थे– तेजस्वी यादव भी शराब पीते हैं।

यह पिछले साल की घटना है। तेजस्वी उस समय राज्य के उपमुख्यमंत्री थे। राजद के तत्कालीन उपमुख्य सचेतक सुनील कुमार सिंह ने प्रो. सिंह की परिषद की सदस्यता रद करने के लिए जो आवेदन विधान परिषद के सभापति को दिया था, उसमें इस वीडियो की भी चर्चा है। हालांकि, प्रो. सिंह इसे सदस्यता रद करने का इकलौता कारण नहीं मानते हैं। परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने मंगलवार को यह निर्णय दिया।

प्रो. सिंह ने मंगलवार को कहा कि वह प्रकरण को न्यायालय में चुनौती देंगे। संविधान की 10 वीं अनुसूची के जिन प्रविधानों के आधार पर उनकी सदस्यता रद की गई है, वे उनके मामले में लागू नहीं होते हैं।

उनके मुताबिक सदस्यता रद करने के तीन कारण होते हैं-व्हिप का उल्लंघन, दल विरोधी आचरण और स्वेच्छा से दल का परित्याग। उनके मामले में इनमें से एक भी कारण नहीं है।

विदित हो कि इससे पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें तीन बार कारण बताओ नोटिस जारी किया था। प्रो. सिंह ने किसी का जवाब नहीं दिया। विधान परिषद की ओर से भी प्रो. सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया था। लेकिन वह उसका भी संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके। प्रो. सिंह 2020 में विधानसभा कोटा से निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 28 जून, 2026 तक था।

बैंकों के सिस्टम में गड़बड़ी से यूपीआइ भुगतान में दिक्कत

मुंबई, प्रेट्र: नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआइ) ने कहा कि कुछ बैंकों के सिस्टम में गड़बड़ी के कारण मंगलवार शाम यूपीआइ प्लेटफार्म के माध्यम से डिजिटल भुगतान सेवा बाधित रही। एनपीसीआइ ने एक्स पर पोस्ट किया, यूपीआइ कनेक्टिविटी पर असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि कुछ बैंकों में तकनीकी समस्याएं हैं। हालांकि उन बैंकों का नाम नहीं बताया गया जिनके सिस्टम में गड़बड़ी आई।

एनपीसीआइ ने कहा कि उसके सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं। समस्या के त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित बैंकों के साथ काम काम किया जा रहा है। इस बीच एचडीएफसी बैंक ने स्वीकार किया कि प्रभावित होने वालों में उसके ग्राहक भी शामिल हैं।

पहल

शिक्षा के लिए प्रेरणा बनी बेटी, साथ कालेज ले जाता था बेटा, पूर्व सरपंच पति को पत्नी के जज्बे पर गर्व, सवाल उठे पर पक्का रखा इरादा

बिहार में बेटे के साथ मां भी दे रही इंटर की परीक्षा

प्रमोद टैगोर, संझौली (रोहतास)

शिक्षा के क्षेत्र में यह खूबसूरत बदलाव का उदाहरण है। बेटी तन्वी स्नातक खंड एक की परीक्षा दे रही है तो उससे प्रेरित मां प्रतिमा (38 वर्ष) भी बेटे ऋषभ के साथ इंटर की परीक्षा में शामिल हो रहीं हैं। बेटी ने मां के दिल में शादी के बाद छूट गई पढ़ाई की कसक को महसूस कर उन्हें प्रोत्साहित किया। परिवार ने भी साथ दिया। आज बेटे के साथ मां का परीक्षा देना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। यह परिवार बिहार में रोहतास जिले के संझौली प्रखंड की सुसाडी ग्राम का रहने वाला है। अब गांव के लोग उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा मानने लगे हैं।

पढ़ने में परिवार का मिला साथ : सुसाडी के पूर्व सरपंच उत्तम कुमार की पत्नी प्रतिमा कुमारी ने शादी से पहले वर्ष 2000 में झारखंड के लालमटिया उच्च विद्यालय से मैट्रिक की थी। इसके बाद पढ़ाई छूट गई। वर्ष 2003 में विवाह के बाद गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों में फंस गईं। वित्तीय हालात भी अच्छी नहीं थी। फिर, तीन संतानों को पढ़ाने-लिखाने की जिम्मेदारी कंधे पर आ गई, लेकिन दिल में आगे पढ़ने की इच्छा दबी रही। बड़ी बेटी तन्वी ने पढ़ने के सपने को पूरा करने की हिम्मत दी। उन्होंने स्नातक में पढ़ते हुए मां को पढ़ाया।

प्रतिमा बताती हैं कि बेटी के अलावा पति व दो बेटों ने भी साथ दिया तो 22 साल बाद दोबारा कालेज में नामांकन कराया। शुरू में कालेज जाने को लेकर डरीं, पर कुछ दिनों बाद अच्छा लगने लगा। प्रतिमा की 19 साल की बेटी तन्वी कहती हैं कि मेरे छोटे भाई ऋषभ के साथ मां भी पढ़ीं और आज हम दोनों भाई-बहन व मां परीक्षाएं दे रहें हैं। तन्वी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा दे रही हैं। वे बिक्रमगंज के पटेल कालेज की परीक्षार्थी हैं। मां उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय डिलियां (डेहरी आन सोन) केंद्र पर इंटर कला की परीक्षार्थी हैं तो 17 वर्षीय बेटे ऋषभ सासाराम के संत अन्ना विद्यालय केंद्र पर इंटर विज्ञान की परीक्षा दे रहे हैं। पति को पत्नी के जज्बे पर गर्व है तो तीसरी कक्षा में पढ़ रहा बेटा श्रेयास भी मां को आदर्श मानता है। प्रतिमा कहती हैं चाहती हूं कि मेरी जैसी महिलाएं पढ़-लिखकर सम्मान पाएं।

बिहार के रोहतास जिले के संझौली की निवासी प्रतिमा देवी, पति उत्तम कुमार बेटा श्रेयास के साथ, बेटा ऋषभ व बेटी तन्वी (बाएं से दाएं)। सौजन्य: स्वयं

'ये मां, बेटी और बेटा शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल हैं। ये समाज के लिए अनुकरणीय हैं। पक्के इरादे वाली ऐसी महिलाएं ही समाज के लिए आदर्श बनती हैं। शिक्षा को लेकर इस जागरूकता से अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे।' – अनिल बसाक, एसडीएम, बिक्रमगंज।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को पासपोर्ट जमा करने को कहा

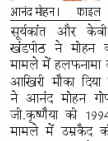

- गोपालगंज के डीएम की हत्या मामले में पुलिस स्टेशन में हर पखवारे लगानी होगी हाजिरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: बिहार के गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या के दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट ने अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और स्थानीय पुलिस स्टेशन में हर पखवारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मोहन को माफी देने के मामले में हलफनामा दायर करने का एक आखिरी मौका दिया है। बिहार सरकार ने आनंद मोहन गोपालगंज के डीएम जी.कृष्णैया की 1994 में हुई हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा माफ कर दी थी। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी आनंद मोहन को स्थानीय पुलिस स्टेशन में तत्काल अपना पासपोर्ट जमा कराना चाहिए। साथ ही उसे पुलिस स्टेशन में हर 15 दिन पर अपनी हाजिरी सुनिश्चित करनी होगी। संक्षिप्त सुनवाई के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने मारे गए अफसर की पत्नी उमा कृष्णैया की ओर से पेश होते हुए खंडपीठ से कहा कि यह मामला कुछ अरसे से अटका पड़ा है क्योंकि केंद्र ने माफी को चुनौती देने वाली याचिका पर अब तक अपना जवाब नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल मई में केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया था। बिहार सरकार के हलफनामे का जिक्र करते हुए लूथरा ने कहा कि यह एक अजीबोगरीब मामला है जिसमें उम्रकैद की सजा पाए दोषी को समय से पहले रिहा कर दिया गया है और अब वह राजनीतिक भूमिका निभा रहा है।

आनंद मोहन। फाइल

****

16 जून 2022 को अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की तीन सेवाओं में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 7 फरवरी, 2024

कर्नाटक में कृष्णा नदी में मिली राम लला जैसी प्राचीन विष्णु प्रतिमा

रायचूर, प्रेट्र : कर्नाटक के रायचूर जिले के एक गांव में कृष्णा नदी से भगवान विष्णु की एक प्राचीन प्रतिमा मिली है। राम लला की नवनिर्मित प्रतिमा से मिलता हुआ यह प्राचीन विग्रह पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार 11वीं या 12वीं शताब्दी का हो सकता है। भगवान विष्णु की इस खड़ी प्रतिमा के प्रभामंडल के चारों ओर 'दशावतारों' को उकेरा गया है।

सूत्रों का कहना है कि इस अनूठे संयोग में सबसे अद्भुत बात यह है कि तकरीबन हजार साल पुराने विग्रह का रूप-रंग और स्वरूप अयोध्या में राम लला के भव्य-दिव्य मंदिर में स्थापित विग्रह से मिलता-जुलता है। भगवान विष्णु के इस विग्रह के साथ ही एक प्राचीन शिवलिंग भी मिला है। रायचूर यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास और पुरातत्व की लेक्चरर डा.पद्मजा देसाई ने भगवान विष्णु की प्रतिमा के संबंध में बताया कि यह निश्चित रूप से एक मंदिर के गर्भगृह का हिस्सा रही होगी। संभवतः इसे मंदिर में हुई तोड़फोड़ से बचाने के लिए नदी में डाला गया होगा। इस प्रतिमा को थोड़ी क्षति पहुंची है। विग्रह की नाक थोड़ी क्षतिग्रस्त है।

डा. देसाई ने बताया कि कृष्णा नदी क्षेत्र में पाई गई इस प्रतिमा में विशेष नक्काशी की गई है। उसके प्रभामंडल पर विष्णु के दशावतार बने हैं। उस पर मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्की अलंकृत हैं। विष्णु जी की खड़ी प्रतिमा के चार हाथ हैं जिसमें दो ऊपर उठे हाथ शंख और चक्र से सुसज्जित हैं। नीचे की ओर सीधे किए दो हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हैं। इनमें एक 'कटि हस्त' और दूसरा 'वरद हस्त' है। हालांकि इस विग्रह पर गरुड़ का चित्रण नहीं है। जबकि आमतौर पर विष्णु प्रतिमा में गरुड़ भी होते हैं। यह विग्रह ग्रंथों में उल्लेखित भगवान वेंकेटेश्वर से मिलती-जुलती है। देसाई ने इंगित किया कि विष्णु जी को साज-सज्जा पसंद है इसलिए उन्हें मालाओं और आभूषणों से अलंकृत किया गया है।

- 11वीं-12वीं शताब्दी की प्रतिमा रायचूर जिले में कृष्णा नदी की वेसिन से मिली
- आभामंडल पर दशावतार वने हैं, नदी क्षेत्र से प्राचीन शिवलिंग भी मिला

कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी से मिला शिवलिंग एवं भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति। प्रेट्र

बिहार के जमुई में तालाब से मिली भगवान सूर्य की पालकालीन प्रतिमा

जासं, जमुई

- तालाव की खोदाई में मिली प्रतिमा, पुरातत्ववेत्ताओं ने इसे दसवीं शताब्दी का वताया
- 2022 में भी मिल चुका है दसवीं शताब्दी का शिवलिंग और भगवान वलराम की प्रतिमा

बिहार में जमुई जिले के सिझौड़ी गांव में मंगलवार दोपहर एक तालाब की खोदाई के दौरान भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा मिली। ग्रामीणों ने प्रतिमा को पास के ही मंदिर में रख दिया है। जमुई के इतिहासकार सह पुरातत्ववेत्ता ने तीन फीट ऊंची इस प्रतिमा को पालकालीन दसवीं शताब्दी का बताया है। बता दें, चार मार्च, 2022 को जमुई के कुमार गांव के मां नेतुला मंदिर स्थित तालाब से पालकालीन नौवीं से दसवीं शताब्दी का शिवलिंग मिला था। 19 अगस्त 2022 की जन्माष्टमी को लोहंडा गांव के तालाब से पालकालीन भगवान बलराम की प्रतिमा मिली थी। पाल साम्राज्य का शासन वर्ष 750 से लेकर 1174 तक माना जाता है।

सिझौड़ी गांव के राजीव मंडल ने बताया कि खोदाई के दौरान मजदूरों को काले पत्थर की भगवान सूर्य की दुर्लभ प्रतिमा मिली। इसकी सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे बीडीओ अमित कुमार, सीओ कृष्ण कुमार सौरभ एवं पुलिस प्रशासन की टीम ने प्रतिमा का अवलोकन किया। उन्होंने पुरातत्व विभाग के शोध अधिकारी को इसकी सूचना दी।

> मुकुटधारी भगवान सूर्य की यह दुर्लभ प्रतिमा है। यह पालकालीन दसवीं शताब्दी की है। यह अखंडित व अच्छी हालत में है। मूर्ति के दोनों हाथों में कमल तथा नीचे दंड व पिंगल हैं। जमुई व उसके आसपास के क्षेत्रों में इस काल की काले पत्थर की प्रतिमाएं मिलती रही हैं। इस क्षेत्र में ब्राह्मण एवं बुद्ध धर्म से संबंधित प्रतिमाएं भी अक्सर पाई जाती हैं।
> – डा. रवि शंकर गुप्ता, पुरातत्ववेत्ता, जमुई

बिहार में जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के सिझौड़ी गांव स्थित तालाब की खोदाई में मिली भगवान सूर्य की पालकालीन प्रतिमा। जागरण

बाघों के आवासों में नहीं लगेंगे मोबाइल टावर

नई दिल्ली, प्रेट्र: पर्यावरण मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार ने देश में बाघों के महत्वपूर्ण आवासों में मोबाइल टावर लगाने की अनुमति नहीं दी। पर्यावरण मंत्रालय ने अपने आदेश में बाघ संरक्षित व वन्यजीव समृद्ध क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने की स्थिति में अपराधियों द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी का दुरुपयोग किए जाने पर चिंता जताई थी।

जनवरी में जारी आदेश में मंत्रालय ने बताया, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और बाघ संरक्षित क्षेत्रों व गलियारों में मोबाइल टावरों के निर्माण व आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इसमें कहा गया कि वन्यजीव समृद्ध क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया कराने को प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए लेकिन इस प्रकार की स्थापना से वन्यजीव अभ्यारण्यों की सुरक्षा और संरक्षण प्रभावित नहीं होना चाहिए। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य वन्यजीव वार्डन व संचार मंत्रालयों को जारी आदेश में कहा गया कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान पर मोबाइल टावर की स्थापना नहीं होनी चाहिए।

एससी-एसटी कोटे में कोटे पर 'सुप्रीम' मंथन शुरू

सात जजों की पीठ कर रही विचार, क्या राज्य सरकार को है आरक्षण के लिहाज से एससी-एसटी वर्ग में वर्गीकरण का अधिकार

ईवी चैन्नया मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने कहा था, राज्य सरकार को नहीं है एसटी जातियों के वर्गीकरण का अधिकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आरक्षण का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इस बार अदालत कोटे में कोटे पर विचार कर रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने एससी-एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में अति दलित व पिछड़े यानी एससी-एसटी वर्ग के ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण और प्राथमिकता देने के मुद्दे पर मंथन शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है कि क्या राज्य सरकार को आरक्षण के लिहाज से एससी-एसटी वर्ग में जातियों के उप-वर्गीकरण का अधिकार है। क्या राज्य सरकार एससी-एसटी वर्ग में ज्यादा पिछड़ी, ज्यादा जरूरतमंद जातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए उप-वर्गीकरण कर सकती है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी में कहा भी, क्या यहां भी वही मानदंड नहीं लागू होना चाहिए जैसा कि पिछड़े बनाम अगड़ों के बीच अपनाया जाता है। मामले में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट के सामने पंजाब का मामला है। पंजाब सरकार 2006 में पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) कानून, 2006 लाई थी। इस कानून में पंजाब में एससी वर्ग को मिलने वाले कुल आरक्षण में से 50 प्रतिशत सीटें और पहली प्राथमिकता वाल्मीकि और मजहबियों (मजहबी सिख) के लिए तय कर दी गई थीं।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 2010 में पंजाब के इस कानून को असंवैधानिक ठहरा दिया था जिसके विरुद्ध पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है जिस पर सात जजों की पीठ सुनवाई कर रही है। सात जज इस मामले को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने ईवी चैन्नया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में दिए फैसले में कहा था कि राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की एक अन्य पीठ ने माना था कि ईवी चैन्नया मामले में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है इसलिए आरक्षण के लिहाज से एससी-एसटी वर्ग में उप-वर्गीकरण के इस मामले पर सात जजों की पीठ विचार कर रही है। मुख्य मामला पंजाब का है, लेकिन पंजाब के साथ लगभग दो दर्जन याचिकाएं लंबित हैं जिनमें कोटे में कोटे का मामला उठाया गया है। सात जजों की पीठ ईवी चैन्नया फैसले में दी गई व्यवस्था पर भी पुनर्विचार करेगी।

मंगलवार को मामले पर सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ बैठी। बहस की शुरुआत पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने की। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने आरक्षण की अवधारणा और एससी के आरक्षण से वाल्मीकि और मजहबी सिखों को 50 प्रतिशत आरक्षण और प्राथमिकता के कानून को सही ठहराते हुए कहा कि यह वर्गीकरण किसी वर्ग को बाहर करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है बल्कि जो वंचित रह गए है उन्हें अंदर लाने का प्रयास है। इसमें संतुलन कायम किया गया है। एक तो एससी के कुल आरक्षण में से सिर्फ 50 प्रतिशत सीटों को वाल्मीकि और मजहबियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर आरक्षित किया गया है दूसरे यह व्यवस्था बहिष्करण की नहीं, बल्कि प्रिफरेंसियल बेसिस पर है। संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में नौ जजों की इंद्रा साहनी (मंडल जजमेंट) फैसले में दी गई व्यवस्था का हवाला दिया, जो वर्गीकरण की इजाजत देता है।

हालांकि हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इंद्रा साहनी का फैसला सिर्फ ओबीसी के बारे में था, वह फैसला एसीसी-एसटी आरक्षण पर लागू नहीं होगा। मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश ने आरक्षण में लागू होने वाले बहिष्करण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब पाठ्यक्रम पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षित होता है तो उन पाठ्क्रम की प्रतिस्पर्धा से अगड़ा वर्ग बाहर हो जाता है। फिर भी हमारा संवैधानिक न्याय शास्त्र इसकी इजाजत देता है क्योंकि हम समानता को औपचारिक नहीं बल्कि एक वास्तविक समानता के रूप में मानते हैं। पिछड़े समुदाय के बारे में भी यही बात लागू होती है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि क्या बैकवर्ड बनाम फारवर्ड का मानक यहां पिछड़ों के बीच भी लागू होगा। जैसा कि पंजाब के कानून में किया गया है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ विचार का प्रश्न यह है कि क्या जिस मानदंड और आधार पर बैकवर्ड बनाम फारवर्ड में बहिष्करण लागू होता है, वही मानदंड यहां लागू होगा। ज्ञात हो कि ईवी चैन्नया के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य सरकारें एससी को दिए गए आरक्षण में कोई दखल नहीं दे सकतीं। केवल संसद ही एससी की जातियों को सूची से बाहर कर सकती है।

जिस भूमि के लिए हेमंत सोरेन हुए गिरफ्तार, उसे लौटाने का आदेश

- 29 जनवरी को दिल्ली आवास में ईडी कर रही थी छापेमारी, इधर रांची में कोर्ट ने जारी कर दिया आदेश
- सर्वोच्च न्यायालय में गिरफ्तारी के विरुद्ध दाखिल याचिका में हेमंत की ओर से किया गया है उल्लेख

हेमंत सोरेन फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, रांची

ईडी जिस रांची जमीन घोटाला मामले की जांच कर रही है और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, उस 8.5 एकड़ भूमि को रांची के शेड्यूल एरिया रेगुलेटरी कोर्ट (एसएआर) ने मूल मालिक को लौटाने का आदेश 29 जनवरी को ही दे दिया था। उल्लेखनीय है कि 29 को ही ईडी के अधिकारी हेमंत के दिल्ली के आवास में उनसे पूछताछ व छापेमारी के लिए डेरा डाले हुए थे, लेकिन हेमंत ईडी टीम को नहीं मिले थे।

हेमंत ने भूमि लौटाने का जिक्र अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में किया था। उसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया था। आवेदन में कहा गया है कि रांची के बरियातू में स्थित जिस 8.5 एकड़ जमीन को हड़पने की कोशिश मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उसे मूल मालिक को लौटाने के लिए एसएआर कोर्ट ने आदेश दे दिया है। दरअसल, रांची एसएआर कोर्ट ने 29 जनवरी, 2024 को ही यह आदेश जारी किया था। ईडी अब यह जानने में जुटी है कि आखिरकार इतनी तेजी से यह आदेश कैसे जारी हो गया। 29 जनवरी को जब जमीन घोटाला केस में ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी, उसी दिन एसएआर कोर्ट का जमीन वापसी को लेकर फैसला भी आ गया था।

याचिका में हेमंत ने उक्त जमीन का पूरा इतिहास संलग्न किया था। सर्वोच्च न्यायालय से हेमंत सोरेन की इस याचिका को खारिज कर उन्हें झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का आदेश दिया था, जहां अभी सुनवाई जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका के साथ एसएआर केस नंबर 81/23-24 में रांची की स्पेशल रेगुलेशन अधिकारी मनीषा तिर्की की अदालत से 29 जनवरी 2024 को जारी आदेश की कापी भी संलग्न की गई है। यह केस राजकुमार पाहन बनाम बुधन राम व अन्य से संबंधित था, जिसमें एसएआर कोर्ट ने अंचलाधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह आदेश दिया था कि उक्त जमीन छोटानागपुर टेनेंसी (सीएनटी) एक्ट के अधीन है, जिसकी गलत तरीके से खरीद-बिक्री व दस्तावेज तैयार किए गए। दस्तावेज रद करते हुए, उस पर बने ढांचे को नष्ट कर उस जमीन को मूल रैयत को वापस करें। जमीन की जांच रिपोर्ट में बड़गाईं अंचल के सक्षम पदाधिकारियों ने बताया था कि आवेदक राजकुमार पाहन के नाम पर बाकास्त भुइहरी पहनई जमीन (जंगल को साफ कर विकसित की गई ऐसी जमीन, जिस पर पाहन पुजारी का हक होता है और उसे बेचा नहीं जा सकता) व बुधु पाहन व अन्य के नाम पर कुछ जमीन है। इस जमीन पर कई गैर आदिवासियों ने अवैध तरीके से खरीद-बिक्री की और उनके नाम पर जमाबंदी व कब्जा है। एसएआर कोर्ट से उन्हें नोटिस दिया गया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद उनकी जमाबंदी रद करने व जमीन खाली करने संबंधित आदेश जारी किया गया है। यह सीएनटी एक्ट के तहत आदेश जारी हुआ है।

पूर्व कर्मचारी के सामने बैठकर जवाब दे रहे पूर्व सीएम

जमीन घोटाला मामले में ईडी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पूर्व राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के सामने बैठाकर पूछताछ की। खबर लिखे जाने तक पूछताछ जारी थी। ईडी ने मंगलवार को रांची के बड़गाईं अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को रिमांड पर लिया है, जबकि हेमंत पहले से ही पांच दिनों की रिमांड पर हैं। भानु प्रताप ने ईडी को बताया है कि रांची में डीएवी बरियातू स्कूल के पीछे स्थित पत्थर की बाउंड्री के अंदर की 8.5 एकड़ भूमि को अंचल अमीन के साथ नापी करने और विस्तृत विवरण देने का आदेश तत्कालीन अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने दिया था। मनोज कुमार ने यह भी बताया था कि उक्त जमीन बास (हेमंत सोरेन) की है।

मध्य प्रदेश में हरदा में पहले भी हो चुका है हादसा, फैक्ट्री मालिक को हुई थी सजा

प्रथम पृष्ठ से आगे

मध्य प्रदेश में हरदा जिले के बैरागढ़ गांव स्थित पटाखा फैक्ट्री में इससे पहले 2015 में भी दो मज़दूरों की मृत्यु हो गई थी। तब जांच में यह बात सामने आई थी कि राजू की फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। दिनेश शर्मा ने 2013 में अपना गोदाम फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल उर्फ राजू को किराये पर दिया था, लेकिन उसने उसमें विस्फोटक पदार्थ रखने की अनुमति जिला दंडाधिकारी से नहीं ली थी। उनसे बिना प्रशिक्षण व समुचित सुरक्षा उपाय के पोटाश, बारूद के इस्तेमाल से पटाखे बनवाए जा रहे थे। इस मामले में हरदा न्यायालय के तात्कालिक द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार दक्षणी ने राजू और दिनेश को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। 2023 में अग्रवाल परिवार पर जीएसटी का छापा पड़ा था, जिसमें 46 लाख की टैक्स चोरी पकड़ी गई थी।

घटनास्थल से काफी दूर तक मानव अंग जहां-तहां बिखर गए : प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट इतना तेज हुआ कि घटनास्थल से काफी दूर तक मानव अंग जहां-तहां बिखर गए। विस्फोट की चपेट में आसपास के दर्जनभर से ज्यादा मकान आए। ऊंची-ऊंची आग की लपटें उठने लगीं और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। धमाकों से हुआ कंपन 25 किलोमीटर की परिधि तक महसूस किया गया। हादसे के बाद फैक्ट्री के करीब एक किलोमीटर के दायरे में लोगों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया।

हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद घटनास्थल का दृश्य। प्रेट्र

मेरठ में 90 वर्षीय पूर्व शिक्षिका के शव को चूहों ने कुतर डाला

जागरण संवाददाता, मेरठ

- दस दिन पहले ही हो चुकी थी मौत, नब्बे साल की अविवाहित रहती थीं अकेली
- पड़ोसी सोमवार रात घर पहुंचा तो पता चला, भतीजे ने कहा-आने का समय नहीं

मेरठ में घर में अकेली रहने वाली नब्बे साल की पूर्व शिक्षिका को मरे दस दिन हो गए और किसी को खबर नहीं लगी। पड़ोस में रहने वाला रिश्ते का भतीजा खैर-खबर लेने घर पहुंचा तो बदबू आई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो बेडरूम का दृश्य भयावह था। चेहरे समेत शरीर को चूहों ने कुतर रखा था। फारेंसिक टीम के मुताबिक, महिला की मौत करीब दस दिन पहले हुई होगी। बेकद्री की हद तब हुई जब बाहर रहने वाले स्वजन ने आने के लिए समय न होने की बात कहते हुए अंतिम संस्कार का खर्च आनलाइन भेजने को कहा। इसके बाद पड़ोसी एवं दूर के रिश्तेदारों ने मानवता का परिचय दिया और ब्रजघाट पर अंतिम संस्कार कर दिया।

लंबे समय से घर में अकेली रहती थीं: कमला सरीन अविवाहित थीं और लंबे समय से घर में अकेली रहती थीं। कमला की करोड़ों की संपत्ति है। कई घर और दुकानें भी किराए पर हैं। कमला सरीन के सबसे बड़े भाई रामपाल आइएएस थे। चारों भाइयों के परिवार देश के अन्य शहरों एवं विदेश में रहते हैं।

प्रतिष्ठित सोफिया गर्ल्स स्कूल की शिक्षिका थीं: 90 वर्षीय कमला सरीन मेरठ की प्रतिष्ठित सोफिया गर्ल्स स्कूल की शिक्षिका थीं। पड़ोसियों ने दस दिन से नहीं देखा था। सोमवार रात रिश्ते के भतीजे एवं पड़ोसी सीए संजीव सरीन उनके घर गए तो आंगन में भयंकर बदबू आ रही थी। खिड़की से झांककर देखा तो बेड पर कमला का शव पड़ा था। पुलिस पहुंची तो बेडरूम का गेट तोड़ा गया। शव पूरी तरह से सड़ चुका था। चेहरे को चूहों ने कुतर दिया था। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है। साथ ही स्वजनों की संवेदनहीनता को लेकर भी क्षेत्र में चर्चा होती रही।

अग्निवीर बनने को मनोवैज्ञानिक परीक्षण जरूरी

बदलाव

सेना में अधिकारियों की भर्ती के दौरान ही होता था ऐसा, पहली बार जवानों की भर्ती में इसे किया जा रहा है लागू

अमित मिश्रा, ग्वालियर

भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के लिए अब अभ्यर्थियों को मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जिसे एडाप्टिबिलिटी टेस्ट का नाम दिया गया है, से भी गुजरना होगा। ऐसा सेना में सिर्फ अधिकारियों की भर्ती के दौरान ही होता था। पहली बार जवानों की भर्ती में इसे लागू किया जा रहा है। लागू करने से पहले इसका पुणे में 2023 में भर्ती के दौरान ट्रायल किया गया था, जिसकी समीक्षा की गई और परिणाम सकारात्मक रहे। इसी के बाद भर्ती में मनोवैज्ञानिक परीक्षण को स्थायी रूप से शामिल करने का निर्णय लिया गया। नए बदलाव का नोटिफिकेशन सात फरवरी को रात 12 बजे जारी किया जाएगा।

सेना के एक अधिकारी ने बताया कि एडाप्टिबिलिटी टेस्ट लिखित और मेडिकल परीक्षा के बीच में होगा। पहले लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद शारीरिक प्रवीणता परीक्षा होगी। सफल अभ्यर्थियों को परीक्षास्थल पर उनका मोबाइल फोन दिया जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लिंक भेजा जाएगा, जिसमें एडाप्टिबिलिटी टेस्ट के 50 प्रश्न के 50 अंक होंगे। इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही मेडिकल परीक्षण के लिए प्रवेश मिलेगा। परीक्षण का उद्देश्य है, अभ्यर्थियों का मानसिक स्तर जानना। यह जानना कि वह सेना के जोखिम, सेना की जिम्मेदारी और सेना के कार्य को समझते हैं या नहीं। उनका मानसिक स्तर सेना के लायक है या नहीं।

बता दें कि सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। इसके पहले लिखित परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव हुआ था। लिखित परीक्षा पूर्व में शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के बाद होती थी, लेकिन सेना ने बदलाव करते हुए लिखित परीक्षा पहले और शारीरिक प्रवीणता परीक्षा बाद में कर दी। इसी प्रक्रिया के साथ ग्वालियर भर्ती कार्यालय में आठ फरवरी से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। 21 मार्च तक 250 रुपये आनलाइन शुल्क जमा कर आवेदन किए जा सकेंगे।

अग्निवीर क्लर्क अब अग्निवीर आफिस असिस्टेंट कहलाएंगे : अग्निवीर क्लर्क पद का नाम भी परिवर्तित कर अग्निवीर आफिस असिस्टेंट किया गया है। अग्निवीर आफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के समय ही टाइपिंग टेस्ट देना होगा। 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड पर सफल माने जाएंगे।

प्रतीकात्मक

> सेना में अग्निवीर बनने को मनोवैज्ञानिक परीक्षण से भी अभ्यर्थियों को गुजरना होगा। आठ फरवरी से 21 मार्च के बीच आवेदन किए जा सकेंगे। लिखित परीक्षा और मेडिकल परीक्षण के बीच मनोवैज्ञानिक परीक्षण होगा।
> – कर्नल संतोष कुमार, डायरेक्टर, सेना भर्ती कार्यालय, ग्वालियर

बर्फबारी से बढ़ी दुश्वारियां

हिमाचल प्रदेश में जोरदार हिमपात से जहां चोटियां बर्फ से लकदक हो गई हैं, वहीं दुश्वारियां भी बढ़ी हैं। यह दृश्य अटल टनल का है, जहां हिमपात के कारण सड़क पर बर्फ का भारी ढेर लग गया है। इसके कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। एएनआइ

****

17.22 प्रतिशत की दर से राजस्थान में आर्थिक अपराध का ग्राफ बढ़ा है। जयपुर भी आर्थिक अपराध के लिहाज से देश में टाप पर पहुंच गया है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की साल 2022 की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

पोखरण में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान में जैसलमेर जिले के पोखरण में कैंट के समीप से मंगलवार को सेना की इंटेलिजेंस विंग ने एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा है। जासूस मनुजी भील परिवार के साथ 2014 में दीर्घकालिक वीजा लेकर भारत आया था। वह इस साल जनवरी महीने से सेना के कैंट इलाके में मजदूरी कर रहा था। पिछले दो-तीन दिन से संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए उस पर नजर रखी जा रही थी।

जब जासूस की गिरफ्तारी हुई, उस समय पर मोबाइल पर पाकिस्तान में किसी से बात कर रहा था। उसके मोबाइल में पाकिस्तान के कई नंबरों पर बात करने और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पाक के लोगों से आडियो-वीडियो काल करने के साक्ष्य मिले हैं। वह पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के बहावलपुर का मूलनिवासी है। बताया जा रहा है कि वह पाक सेना के अधिकारियों के संपर्क में था। सेना की इंटेलिजेंस विंग ने उसको जैसलमेर की पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया, जांच एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। राजस्थान का जैसलमेर जिला पाकिस्तान से सटा हुआ है।

गोवा एक भारत–श्रेष्ठ भारत का नायाब उदाहरण : मोदी

- प्रधानमंत्री बोले- यह क्षेत्रफल व जनसंख्या के हिसाब से छोटा पर सामाजिक विविधता में समृद्ध राज्य
- गोवा में 1330 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
- कहा-बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए

दक्षिण गोवा, एएनआइ : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि गोवा क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में भले ही छोटा है लेकिन यह सामाजिक विविधता में बेहद समृद्ध है और यह 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का एक नायाब उदाहरण है।

'विकसित भारत, विकसित गोवा 2047' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का मूल का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने कहा कि सामाजिक विविधता के लिहाज से गोवा बहुत समृद्ध है। यहां विभिन्न समुदायों और धर्मों के लोग आपस में मिल-जुलकर एक साथ रहते हैं। वे पीढ़ियों से एक साथ रहते आए हैं। इसलिए जब गोवा के ये लोग भाजपा को बार-बार चुनते हैं तो इसका संदेश पूरे देश में जाता है। भाजपा का लक्ष्य ही देश का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने राज्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में से कई में गोवा ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जब संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त होता है तो मतभेद समाप्त हो जाते हैं और इसका लाभ सभी तक पहुंचता है।

मोदी ने कहा कि कुछ पार्टियां हमेशा झूठ और डर फैलाने की राजनीति करती आई हैं, लेकिन गोवा ने ऐसी पार्टियों को बार-बार करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यहां का ऐतिहासिक लोहिया मैदान इस बात का सुबूत है कि जब देश के लिए कुछ करने की बात आती है, तो गोवा के लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। इस दौरान मोदी ने देश में सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों के तेजी से हो रहे विकास पर प्रकाश डाला। कहा-डबल इंजन सरकार गरीबों के कल्याण के लिए बड़ी योजनाएं चलाने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे में रिकार्ड निवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि इस साल के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 10 साल पहले यह राशि दो लाख करोड़ रुपये से भी कम थी। मोदी ने भारत को एक समग्र पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर प्रकार का पर्यटन एक ही वीजा पर उपलब्ध है। पिछली सरकारों के पास पर्यटन स्थलों, तटीय क्षेत्रों और द्वीपों के विकास के लिए दूरदर्शिता का अभाव था। इससे पहले पीएम ने गोवा में 1330 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। पीएम ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान का नया परिसर भी राष्ट्र को समर्पित किया। जलक्रीडा संस्थान जनता और सशस्त्र बलों दोनों के लिए जलक्रीड़ा और जल बचाव गतिविधियों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 28 विशेष पाठ्यक्रम शुरू करेगा।

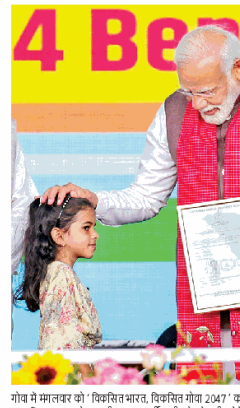

गोवा में मंगलवार को 'विकसित भारत, विकसित गोवा 2047' कार्यक्रम के दौरान दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना की एक लाभार्थी बच्ची को स्नेहाशीष देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र

महाराष्ट्र में सहायक कर आयुक्त पर एक करोड़ की रिश्वत मांगने का मामला

मुंबई, प्रेट्र: भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने महाराष्ट्र में राज्य सहायक कर आयुक्त और जीएसटी विभाग के कुछ अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कर संबंधी लंबित मामले का निपटारा करने के लिए एक कंपनी के निदेशक से एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में मामला पंजीकृत किया है। एसीबी ने भ्रष्टाचार रोकथाम की धारा सात के तहत राज्य कर (जांच शाखा) के सहायक आयुक्त अर्जुन सूर्यवंशी एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध दो फरवरी को मामला पंजीकृत किया। राज्य कर एवं मुख्य निगरानी अधिकारी द्वारा महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (एसीबी) को पत्र लिखकर जांच की मांग करने के बाद एफआइआर पंजीकृत की गई। जांच में पता चला कि सूर्यवंशी और उनकी टीम ने पिछले वर्ष पांच जुलाई और सात अगस्त के बीच फर्म पर छापेमारी की थी। फर्म पर 20 करोड़ से ज्यादा कर बकाया था। फर्म ने कर का भुगतान नहीं किया। 21 अगस्त को सूर्यवंशी ने एक वाट्सएप संदेश भेजकर मामला निपटाने के लिए रिश्वत के रूप में एक करोड़ रुपये देने की मांग की।

बंगाल में अब मनरेगा में व्यापक फर्जीवाड़ा

मवेशी तस्करी, शिक्षक भर्ती, पालिका भर्ती और राशन घोटाले की पहले ही चल रही है जांच

ईडी ने राज्य के चार जिलों में छह जगहों पर चलाया तलाशी अभियान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- दावा-मनरेगा के तहत जारी किए गए लगभग 25 लाख फर्जी रोजगार कार्ड

बंगाल में मवेशी तस्करी, शिक्षक भर्ती, पालिका भर्ती तथा राशन आवंटन घोटाले के बाद अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में व्यापक फर्जीवाड़ा सामने आया है। मनरेगा कोष के गबन की जांच के सिलसिले में मंगलवार को ईडी ने राज्य में पहली बार कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की।

सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा व हुगली जिले के धनेखाली में दर्ज एफआइआर के आधार पर चार जिलों उत्तर 24 परगना, हुगली, झाड़ग्राम व मुर्शिदाबाद में छह जगहों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ईडी को पता चला है कि लगभग 25 लाख फर्जी जाब कार्ड बनाकर करोड़ों रुपये का हेरफेर किया गया है। इस फर्जीवाड़े में वरिष्ठ पूर्व व वर्तमान सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है। माना जा रहा है कि पिछले तीन-चार वर्षों में यह फर्जीवाड़ा किया गया है। कोलकाता से सटे साल्टलेक के आइए ब्लाक में एक पूर्व खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के आवास पर छापा मारा गया। मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर में एक डिप्टी मजिस्ट्रेट संचयन पान से जुड़ी संपत्ति की तलाशी ली गई है। ईडी ने बहरमपुर में निष्कासित पंचायत कर्मचारी रथींद्र कुमार दे से पूछताछ की।

बंगाल में ईडी की छापेमारी।

बताते चलें कि कुछ वर्ष पूर्व भ्रष्टाचार के आरोप में रथींद्र कुमार को निष्कासित किया गया था। उस पर गबन के पैसे विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित करने का आरोप है। इसमें से उसने 17 लाख रुपये अपनी एक महिला मित्र के बैंक खाते में भेजे थे। 2020 में कुछ अज्ञात कारणों से इस मामले की जांच प्रक्रिया रुक गई थी। वहीं, तलाशी अभियान के दौरान ईडी के अधिकारी गलती से हुगली जिले के चुंचुड़ा में एक व्यवसायी के आवास पर चले गए थे। हालांकि, गलती का एहसास होने पर वे वहां से लौट गए।

ईडी के छापे प्रतिशोध की राजनीति : तृणमूल

तृणमूल की वरिष्ठ नेता व मंत्री शशि पांजा ने ईडी की छापेमारी को प्रतिशोध की राजनीति और राज्य का बकाया दिए जाने की मांग को लेकर पार्टी के जारी धरने से ध्यान हटाने का कदम करार दिया है। हालांकि, भाजपा के राज्य प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने इन आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि तृणमूल का हर नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहा है।

सुवेंदु ने 373 करोड़ की हेराफेरी की शिकायत की

बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को ममता बनर्जी सरकार पर 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रदान की गई निधि में से 373 करोड़ रुपये की राशि की हेराफेरी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि 373 करोड़ रुपये का इस्तेमाल नगर पालिकाओं के बिजली बिलों के भुगतान में किया गया। इसके अलावा अधिकारी ने राज्य में मनरेगा श्रमिकों के बकाया पारिश्रमिक के भुगतान को लेकर राज्य सरकार द्वारा तैयार मानक संचालक प्रक्रिया (एसओपी) संबंधी पत्र को सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि इसमें राज्य सरकार ने फर्जी रोजगार कार्ड होने की बात स्वीकार की है।

शिक्षक भर्ती घोटाला : ओएमआर शीट को स्कैन करके बढ़ाए गए नंबर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ ने कलकत्ता हाई कोर्ट को हलफनामा दायर कर बताया है कि अयोग्य अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए ओएमआर (आप्टिकल मार्क रिकाग्निशन) शीट को स्कैन करके नंबर बढ़ाए गए थे।

न्यायाधीश देबांग्शु बसाक व न्यायाधीश मोहम्मद शबर रशीदी की खंडपीठ में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि ओएमआर शीट तैयार करने वाली संस्था नाइसा के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित कार्यालय से हार्ड डिस्क जब्त की गई है। इसकी जांच में पता चला है कि ओएमआर शीट की स्कैनिंग के समय सफल अभ्यर्थियों की सूची में गड़बड़ी की गई थी। नौकरी दिलाने के लिए असफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक बढ़ाकर उनके नाम सूची में शामिल कराए गए। इसमें नाइसा के कई कर्मचारियों की मिलीभगत रही।

खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआइ की ओर से हलफनामे पेश कर जो तथ्य पेश किए गए हैं, संबंधित अभ्यर्थी उसे देख सकते हैं। इस बाबत उन्हें सीबीआइ के पास आवेदन करना होगा। इस मामले में स्कूल सर्विस कमीशन की ओर से जो तथ्य दिए गए हैं, उन्हें भी देखा जा सकता है।

कर्नाटक के सीएम सिद्दरमैया पर हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना

मुख्यमंत्री समेत कई कांग्रेस नेताओं को विशेष अदालत में पेश होने का निर्देश

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक प्रदर्शन को रोकने के लिए सड़कें ब्लाक करने के मामले में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने की याचिका खारिज करते हुए सांसदों/विधायकों की एक विशेष अदालत में छह मार्च को पेश होने को कहा है। हाई कोर्ट ने सिद्दरमैया समेत कांग्रेस महासचिव व पार्टी के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, मंत्री एमबी पाटिल और रामलिंगा रेड्डी के खिलाफ दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

जनप्रतिनिधियों को नियमों का पालन करना चाहिए: जस्टिस कृष्णा एस.दीक्षित की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि एक प्रदर्शन के दौरान सड़कों को सिर्फ इसलिए बंद करवाया गया कि वह जनता के एक प्रतिनिधि हैं, बिलकुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने से जनता को परेशानी होती है। कोर्ट ने आगे कहा कि हम सड़कों को अवरुद्ध करना स्वीकार नहीं कर सकते।

सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के वकील ने अपील करने तक आदेश पर रोक लगाने की मांग की लेकिन खंडपीठ ने ऐसा करने से इन्कार करते हुए छह मार्च को सिद्दरमैया को पेश होने को कहा। साथ ही, एआइसीसी महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को अदालत के समक्ष सात मार्च को, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी को 15 मार्च को और मंत्री एमबी पाटिल को 11 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी नेताओं को अलग-अलग 10 हजार रुपये का हर्जाना भरने को कहा है। उल्लेखनीय है कि यह जुर्माना मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और पार्टी के अन्य नेताओं पर बेंगलुरु की हाईग्राउंड पुलिस सब इंस्पेक्टर जहीदा को एक मामले में घसीटने पर किया गया है। एक सरकारी कर्मचारी के 40 प्रतिशत कमीशन मांगने पर एक ठेकेदार संतोष पाटिल के आत्महत्या करने पर लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक यह मुकदमा सड़कें ब्लाक करके आने जानेवालों के लिए परेशानी खड़ी करने का है।

राजस्थान में 40 नाबालिगों से कुकर्म करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, जयपुर

- एक बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या मामले में जांच कर पुलिस को मिली जानकारी
- मुख्य आरोपित मोहम्मद रसूल गिरफ्तार, प्रशासन ने बुलडोजर से घर किया ध्वस्त

राजस्थान के नागौर में 40 नाबालिगों से कुकर्म करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। प्रशासन ने गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपित मोहम्मद रसूल के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। उसने करीब दो सौ वर्गगज जमीन पर कब्जा करके घर बना लिया था।

15 वर्षीय बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नागौर में पैसे, कपड़े और अच्छा भोजन का लालच देकर कुछ लोग बच्चों के साथ कुकर्म करते हैं। इस गिरोह में शामिल एक दर्जन आरोपितों ने अब तक करीब 40 नाबालिगों को अपना शिकार बनाया है। पुलिस उप अधीक्षक ओमप्रकाश गोदारा ने बताया कि रसूल ने नाबालिग को अपने चंगुल में फंसाया था। पहले तो उसने खुद और फिर उसके साथियों ने बच्चे से कुकर्म किया। जनवरी में बच्चे के साथ रसूल ने कुकर्म किया, इस बारे में कुछ लोगों को जानकारी मिल गई। मामला पुलिस तक पहुंचा तो साक्ष्य मिटाने को रसूल ने 19 जनवरी को बच्चे को झांसा देकर बुलाया और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। आरोपित ने बच्चे का शव बोरे में बांधकर गोबर के ढेर में छिपा दिया। इधर, बच्चे के पिता ने गुमशुदगी की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच कर मामला बंद कर दिया, लेकिन पिता ने अधिकारियों से संपर्क किया और कुछ अहम जानकारियां दीं। इसके बाद दोबारा जांच हुई तो हत्याकांड और नाबालिगों से कुकर्म करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने रसूल को सोमवार को गिरफ्तार करने के साथ ही गिरोह में शामिल आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। बच्चे की हत्या करने के लिए उपयोग की गई कुल्हाड़ी पुलिस ने मंगलवार को बरामद कर ली है। गिरोह के कुछ सदस्य फरार हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपित नाबालिगों के मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजते थे।

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में बच्ची से दुष्कर्म पर सुनाई 30 वर्ष सजा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में एक मंदिर में सात वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। कोर्ट ने दोषी को 30 वर्ष जेल की सजा सुनाई और इस कृत्य को बर्बर बताया। यह घटना 2018 की है।

पीड़िता की दादी ने नाबालिग पोती को अगवा कर उससे दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपित बच्ची को एक मंदिर में ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाया था और उसे धारा 376 एबी (12 वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार) के तहत मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने याचिकाकर्ता की मौजूदा उम्र और पहले से कारावास में रहने की बात को संज्ञान में लिया। कोर्ट ने सजा में बदलाव करते हुए दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

राज्य स्तर पर प्रदूषण निकायों के लिए तिमाही बोर्ड बैठक अनिवार्य : सीपीसीबी

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक में उठा मुद्दा तो लिया गया सख्त निर्णय

राज्य स्तर पर प्रदूषण निकायों को हर तीन माह में बोर्ड बैठक करनी ही होगी। इसके अलावा न सिर्फ बैठक करनी होगी बल्कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को भी भेजनी होगी। सीपीसीबी इसे लेकर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को लिखित में दिशानिर्देश जारी करने जा रहा है।

गौरतलब है कि राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण समितियां। नियम है कि हर तीन माह में इनकी एक बोर्ड बैठक होनी चाहिए, परंतु देखा जा रहा है कि कई राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश इस नियम का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे। कहीं-कहीं तो साल साल भर तक बोर्ड बैठक नहीं होती। इससे प्रदूषण से जंग प्रभावी ढंग से नहीं लड़ी जाती तो बहुत से मामलों में मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) में हर तिमाही बोर्ड बैठक का नियम नहीं माना जा रहा। सप्ताहांत में हुई सीपीसीबी की बोर्ड बैठक में यह मुद्दा उठा। सदस्यों का कहना था कि जहां-जहां तिमाही बैठक के नियम की निरंतर अनदेखी हो रही है, उनसे शक्तियां वापस लेनी चाहिए। अगर समय-समय पर बोर्ड बैठक नहीं होगी तो निर्णयों में पारदर्शिता नहीं रहेगी और पर्यावरण संरक्षण संबंधी सीपीसीबी की मुहिम को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। बैठक में वाटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आफ पल्यूशन) एक्ट 1974 के प्रविधानों का उल्लेख भी किया गया। इसके मुताबिक केंद्र शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों को वाटर एक्ट की धारा चार में सीपीसीबी से ही शक्तियां मिलती हैं। ऐसे में कोई समिति अपना कार्य ठीक से नहीं करती या हर तीन महीने में बैठक नहीं बुलाती तो सीपीसीबी उसे निर्देश जारी कर सकता है और उससे शक्तियां लेकर उसका कार्य टेकओवर भी कर सकता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की अगली बोर्ड बैठक 20 फरवरी को रखी गई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फाइल

किसी भी प्रदूषण निकाय द्वारा समय समय पर बोर्ड बैठक न बुलाना और मनमर्जी से निर्णय लेते रहना गंभीर मुद्दा है। इस एजेंडे को बोर्ड ने पिछली बार डेफर कर दिया था। इस बार जब बोर्ड को सीपीसीबी की शक्तियों से अवगत कराया गया तो उसने आगे की कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया। जल्द ही इस संदर्भ में लिखित निर्देश भी जारी किए जाएंगे।
– डा. अनिल गुप्ता, सदस्य, सीपीसीबी

जस्टिस गंगोपाध्याय ने भरी अदालत में बंगाल के महाधिवक्ता से माफी मांगी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार को भरी अदालत में बंगाल के महाधिवक्ता किशोर दत्ता से माफी मांगी। मेडिकल प्रवेश में अनियमितता के मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय ने हाल ही में उन पर नाराजगी जताई थी। इसी को लेकर जस्टिस गंगोपाध्याय ने किशोर को अपनी अदालत में बुलाया और उनसे माफी मांगी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने किशोर के साथ अपने पुराने रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उस दिन कोर्ट रूम में गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब बातें नहीं कही जानी चाहिए थी। जब उन्होंने माफी मांगी तो महाधिवक्ता ने कहा कि मैंने भी उस दिन बहुत सी बातें कही थीं, जिन्हें नहीं कहना चाहिए था। जज ने कहा कि किशोर, मैं, जयमाल्य (जस्टिस जयमाल्या बागची) और कुछ अन्य लोग एक साथ घूमते थे। हमारी दोस्ती है।

जागरण विशेष

तकनीक और बाजार तक पहुंच बना आर्थिकी सुधार रहा घड़ा क्लस्टर

सरकारी योजना व सहकार भाव से संवर रहा पंजाब के मोगा में कारीगरों का जीवन

सत्येन ओझा • मोगा

देश के विकास को गति देने के लिए आवश्यक है कि आमजन तक भी समृद्धि का प्रकाश पहुंचे। इसके लिए केंद्र सरकार की आकांक्षी जिलों के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। इन्हीं में से एक है पंजाब के मोगा जिले का घड़ा क्लस्टर। पारंपरिक विधि से मिट्टी के बर्तन बनाकर जीवनयापन करने वालों के जीवन की आर्थिकी बेहतर करने के लिए इसके माध्यम से सरकार न केवल तकनीकी प्रशिक्षण उन तक पहुंचा रही बल्कि उन्हें देश से विदेश तक बड़ा बाजार भी उपलब्ध करा रही। कारीगरों की आय में वृद्धि के रूप में योजना का सुफल दिखने लगा है। अब इसे गति देने की तैयारी है।

जुड़ रहे कारीगर: जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव योजना की घोषणा की थी तो मोगा में घड़ा क्लस्टर बनाना तय हुआ। योजना की शुरुआत दो वर्ष पहले हुई। पहले लोगों को इससे जोड़ने और इसका लाभ समझाने में थोड़ा समय लगा, पर अब मिट्टी को आकार देकर बर्तन और अन्य उत्पाद बनाने वाले कारीगर इससे जुड़ने में रुचि दिखा रहे हैं। उद्योग केंद्र कारीगरों को जागरूक करने के साथ उन्हें छह माह का प्रशिक्षण भी देता है। इसके लिए जिला उद्योग केंद्र में मशीन स्थापित की गई है।

सरकारी अनुदान भी: क्लस्टर का उद्देश्य सहकार के भाव के साथ पारंपरिक कला को आगे बढ़ाना और इससे जुड़े परिवारों की आर्थिकी को मजबूत करना है। इसके तहत कम से कम 100 व्यक्तियों (अधिकतम 500) का क्लस्टर बनता है। इसके संचालन के लिए जरूरी राशि का 10 प्रतिशत इसके सदस्य कारीगरों को देना होता है, शेष 90 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के रूप में देती है। हर क्लस्टर का सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकरण होता है। साथ ही कारीगरों द्वारा बनाए उत्पादों को दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में लगने वाले व्यापार मेलों व प्रदर्शनियों में भेजने की व्यवस्था सरकार की तरफ से होती है। हाल ही में अयोध्या में प्रभु श्रीराम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मोगा के घड़ा क्लस्टर में बने दीयों की बिक्री हुई थी।

बेहतर उत्पादों की श्रृंखला: इसका नाम भले ही घड़ा क्लस्टर है, पर इसके अंतर्गत मिट्टी के डिजाइनर दीये, सुराही, खिलौने, मिट्टी के तवे भी बनाए जा रहे हैं। शहर के बाजारों और शापिंग माल में बिकने वाले मिट्टी के सुंदर उत्पाद भी यहां बनाने की तैयारी है। साथ ही मिट्टी के खिलौने, कूलर के अंदर पानी ठंडा रखने के लिए मिट्टी का स्टैंड जैसे उत्पाद भी तैयार किये जा सकते हैं। मशीनों से तैयार होने के कारण इन उत्पादों की सुंदरता और गुणवत्ता बेहतर होती है।

घड़ा क्लस्टर योजना सिर्फ कारीगरों की ही जिंदगी नहीं बदलेगी, बल्कि आकांक्षी जिले के रूप में मोगा की आर्थिक समृद्धि की नई कहानी भी गढ़ेगी। योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

सुखमंदर सिंह रेखी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र

मोगा के जिला उद्योग केंद्र में बड़ी मशीन पर कुम्हारों को प्रशिक्षण देने के बाद बिजली से संचालित स्टील के छोटे-छोटे चाक दिए गए हैं, जिनकी सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाती एक महिला • जागरण

बदल रहा लोगों का जीवन

घड़ा क्लस्टर से जुड़ीं रजनी का कहना है कि पहले उनके बनाए जिस उत्पाद का मूल्य 20 रुपये मिलता था, अब 40 रुपये मिल रहा है। छह महीने में परिवार की स्थिति बेहतर हुई है। अब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम हैं। वह कहती हैं कि पहले सीजन के आधार पर हम काम करते थे। जैसे गर्मी में घड़ों व सुराही का काम होता था, अब पूरे साल ही सीजन रहता है, क्योंकि खिलौने व सजावटी उत्पाद भी हम बना लेते हैं। इसी क्लस्टर से जुड़े धर्मपाल सिंह कहते हैं कि आय बढ़ी है तो परिवार के रहन-सहन का स्तर बदल रहा है। पहले माह में 10 हजार रुपये कमा पाते थे। अब 25-30 हजार कमा लेते हैं।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

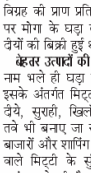

स्कूल से छुट्टी के लिए किशोर ने ली पहली कक्षा के छात्र की जान

जासं, पुरुलिया

- आरोपित को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने रिमांड होम भेजा
- किशोर ने तालाब के पास पत्थर से सिर कूच ली मासूम की जान

बंगाल के पुरुलिया में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां शारदा शिशु मंदिर निजी आवासीय स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले किशोर ने अपने ही स्कूल के पहली कक्षा के एक मासूम की हत्या कर दी। आरोपित छात्र ने हत्या की जो वजह बताई है, उसे जानकर पुलिस हैरान है। पुरुलिया के एसपी अभिजित बनर्जी ने बताया कि आरोपित ने सिर्फ इस वजह से बच्चे की हत्या कर दी, कि मौत की घटना के बाद स्कूल में छुट्टी हो जाएगी। वह हास्टल से घर जाना चाहता था। मंगलवार को पुलिस ने आरोपित छात्र को आनन्द मठ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के न्यायाधीश के समक्ष हाजिर किया। न्यायाधीश ने आरोपित किशोर को हुगली जिला कल्याण भारती रिमांड होम में भेजने का निर्देश दिया है। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है।

ऐसे खुला मामला : आवासीय स्कूल में प्रथम कक्षा में पढ़ने वाला छात्र 29 जनवरी से लापता था। बाद में 30 जनवरी को स्कूल के पास एक तालाब में बच्चे का शव बरामद हुआ था। छात्र के शरीर पर जख्म के गहरे निशाना भी मिले थे। स्वजन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था। बाद में जांच के क्रम में पुलिस को कुछ सुराग मिले, जिसके आधार पर वह हत्यारोपित तक पहुंची। हत्यारोपित छात्र और मारा गया मासूम दोनों ही एक ही छात्रावास में रहते थे।

****

दैनिक जागरण

सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है

घातक अनदेखी

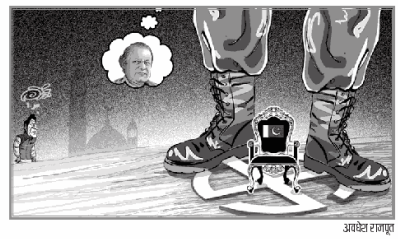

मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से दस से अधिक लोगों की मौत के साथ 50 से ज्यादा लोग घायल तो हुए ही, आसपास के घरों को भी अच्छी-खासी क्षति हुई। ऐसा इसीलिए हुआ, क्योंकि फैक्ट्री घरों के आसपास ही थी और किसी ने इसकी चिंता नहीं की कि हादसे की स्थिति में जान-माल की क्षति कहीं अधिक हो सकती है। इस पर भी हैरानी नहीं कि यह सामने आ रहा है कि फैक्ट्री में मनमाने तरीके से बारूद का भंडारण किया जा रहा था। यह भंडारण कितने बड़े पैमाने पर किया गया था, इसका पता इससे चलता है कि उसमें विस्फोट के कारण आधे घंटे तक धमाके होते रहे और इलाके में अफरातफरी फैल गई। हादसे की गंभीरता का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि आसपास के कई शहरों से अग्निशमन गाड़ियों को बुलाना पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भीषण हादसे का शिकार बनी पटाखा फैक्ट्री सुरक्षा मानकों की अनदेखी करके चलाई जा रही थी। यह अनदेखी इसके बाद भी हो रही थी कि कथित तौर पर फैक्ट्री का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता था।

कोई भी समझ सकता है कि फैक्ट्री के निरीक्षण के नाम पर खानापूरी की जा रही होगी। संबंधित विभाग के अधिकारी कागजों में यह दर्ज करके कर्तव्य की इतिश्री कर लेते होंगे कि फैक्ट्री तय मानकों के हिसाब से चलाई जा रही है। फैक्ट्रियों, होटलों आदि के साथ सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा के मामले में अपने देश में ऐसा ही होता है। निरीक्षण के नाम पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी ही की जाती है। इसी कारण अपने देश में वैसे हादसे लगातार होते ही रहते हैं, जैसा हरदा में हुआ। इन हादसों में तमाम लोग मारे जाते हैं और शासन-प्रशासन के साथ देश की भी बदनामी होती है, लेकिन कोई जरूरी सबक सीखने से इन्कार किया जाता है। स्थिति यह है कि जांच और कार्रवाई के नाम पर भी लीपापोती होती है और जिम्मेदार लोग मुश्किल से ही जवाबदेह बनाए जाते हैं। एक ऐसे समय जब देश को विकसित बनाने की कोशिश हो रही है, तब यह देखना दयनीय है कि इस पर निगाह नहीं जा रही है कि कार्यस्थलों, सड़कों, सार्वजनिक आयोजनों आदि में सुरक्षा के सामान्य नियमों की उपेक्षा ही अधिक होती है। जब देश के बड़े शहरों तक में ऐसा होता है, तब यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि हरदा जैसे शहरों में क्या होता होगा? आखिर कब चेतेंगे हम और यह देखेंगे कि भारत से कहीं कम विकासशील देशों में सार्वजनिक सुरक्षा के नियमों का पालन कहीं अधिक संतोषजनक है? कम से कम अब तो यह समझा ही जाना चाहिए कि सार्वजनिक सुरक्षा के नियमों की अनदेखी देश की प्रगति में एक बड़ी बाधा है। ध्यान रहे कि अपने यहां जैसे सुरक्षा मानकों की उपेक्षा की जाती है, वैसे ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की भी परवाह नहीं की जाती।

पशुओं के हमले

हिमाचल प्रदेश में बेसहारा पशुओं की समस्या गंभीर होती जा रही है। कई क्षेत्रों में किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है। चिंताजनक है कि इनके हमलों से लोगों को जख्म भी मिल रहे हैं। इनके हमलों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। कांगड़ा जिला के जवाली उपमंडल के तहत लुधियाड़ पंचायत में एक बुजुर्ग की बेसहारा बैल के हमले से मौत हो गई है। शनिवार को बेसहारा बैल ने घर में बैठे बुजुर्ग पर हमला कर घायल कर दिया था। इसके बाद घायल को पीजीआइ चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कुछ दिन पहले शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में चंबी खड्ड में भी बेसहारा पशु के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। शनिवार रात को चामुंडा मंदिर के निकट बड़ोई में एक बेसहारा बैल के हमले में महिला घायल हो गई थी। इससे पहले भी प्रदेश के कई कस्बों एवं गांवों में बेसहारा पशुओं के हमले होते रहे हैं। इनमें भी लोगों को जख्म मिल चुके हैं। कुछ लोगों की मौत भी हुई है। सरकारी स्तर पर बेसहारा पशुओं की समस्या के हल की योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाती हैं। शहरों एवं कस्बों में बेसहारा पशुओं के झुंड आम देखे जा सकते हैं। इस समस्या के लिए लोग ही दोषी हैं। लोग पशुओं को तब तक रखते हैं जब तक उन्हें लाभ देते हैं। इसके बाद उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। बेसहारा पशु सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बनते हैं। कई बार वाहनों की टक्कर से बेसहारा पशु भी घायल हो जाते हैं। पशुओं को खुला छोड़ने पर रोक है, पशुओं की टैगिंग भी की गई है इसके बावजूद पशुओं को बेसहारा छोड़ा जा रहा है। सरकारी तंत्र को योजनाएं धरातल पर उतारने के प्रयासों में तेजी लानी चाहिए ताकि कोई पशु बेसहारा न रहे और न लोगों पर इनके हमले हो सकें और किसान खेती भी कर सकें।

सड़कों पर घूमते बेसहारा पशु कई लोगों की मौत का कारण बने हैं

राजनीतिक अनिश्चितता से घिरा पाकिस्तान

विवेक काटजू

पाकिस्तानी सेना ने वे सभी दांव चले हैं, जिनसे लोकप्रिय होने के बाद भी इमरान खान की पार्टी सत्ता की दौड़ से बाहर हो जाए

पाकिस्तान में आठ फरवरी को नेशनल और प्रांतीय असेंबली के चुनाव होने हैं। नेशनल असेंबली का कार्यकाल गत वर्ष अगस्त में समाप्त हो चुका है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम सरकार ने पाकिस्तानी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चुनाव से पहले त्यागपत्र दे दिया था, ताकि कार्यवाहक सरकार गठित हो सके। पाकिस्तान में यही व्यवस्था है कि नेशनल असेंबली भंग होने के 90 दिनों के भीतर कार्यवाहक सरकार के अंतर्गत चुनाव संपन्न होने चाहिए। हालांकि पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने जारी परिसीमन प्रक्रिया के चलते निर्धारित अवधि में चुनाव कराने में असमर्थता जताई थी। आयोग का आग्रह कुछ हद तक सही, लेकिन पूरी तरह सच्चाई के करीब नहीं था। चुनावों को टालने के पीछे की वास्तविक वजह यही थी कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर यह सुनिश्चित करने में लगे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआइ सत्ता की होड़ से बाहर हो जाए। इमरान खान और पीटीआइ को राजनीतिक रूप से पूरी तरह किनारे लगाने के लिए कुछ समय तो चाहिए ही था।

जनरल मुनीर और इमरान के बीच टकराव पुराना है। इमरान ने प्रधानमंत्री रहते हुए तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बाजवा को इसके लिए मनाया था कि वह आइएसआइ के मुखिया पद से मुनीर को विदा कर दें। आइएसआइ प्रमुख का पद पाकिस्तान में रुतबे का प्रतीक माना जाता है। बाद में बाजवा और इमरान के बीच ही समीकरण बिगड़ गए। बाजवा ने अप्रैल 2022 में इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई और उनकी जगह पीडीएम सरकार गठित करा दी। पीडीएम असल में इमरान विरोधी दलों का एक गठबंधन है, जिसमें नवाज शरीफ की पीएमएल-एन, भुट्टो-जरदारी परिवार की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी और मौलाना फजल-उर-रहमान की जेयूआइ-एफ शामिल हैं।

जब बाजवा को सेना प्रमुख के रूप में मिला सेवा विस्तार नवंबर 2022 में समाप्त हो गया, तब नवाज शरीफ ने सुनिश्चित किया कि शीर्ष सैन्य पद पर आसिम मुनीर की ताजपोशी हो। वह भी तब जबकि उनकी नियुक्ति की राह में कुछ तकनीकी बाधाएं थीं। नवाज शरीफ इमरान और मुनीर के बीच कड़वाहट से भलीभांति परिचित थे और उन्हें अनुमान था कि इमरान को सत्ता से दूर रखने के लिए मुनीर किसी भी सीमा तक जाने से संकोच नही करेंगे। अभी तक नवाज शरीफ सही साबित होते दिख रहे हैं। मुनीर और न्यायपालिका की एक प्रकार की जुगलबंदी के चलते इमरान गत वर्ष मई से ही जेल में हैं और कई मामलों में दोषी भी सिद्ध हो चुके हैं, जिसके लिए उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। इसके चलते वह चुनाव लड़ने के लिहाज से भी अयोग्य हो गए हैं। चुनाव आयोग ने पीटीआइ का चुनाव चिह्न 'क्रिकेट बैट' भी जब्त कर लिया है। इस कारण पीटीआइ प्रत्याशियों को निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। यूं तो पूरी चुनाव प्रक्रिया ही कुछ निस्तेज किस्म की है, लेकिन पीटीआइ पर रैलियां आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। उसका चुनाव प्रचार पूरी तरह इंटरनेट मीडिया के भरोसे है।

अवधेश राजपूत

इमरान खान की छवि को हरसंभव तरीके से खराब करने के बावजूद इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि युवा और महिला मतदाताओं के बीच वह खासे लोकप्रिय हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सेना, अन्य राजनीतिक दलों और न्यायाधीशों द्वारा इमरान को किनारे करने की तमाम कोशिशों के बाद भी लोग निर्दलीय के रूप में लड़ रहे पीटीआइ प्रत्याशियों के पक्ष में कैसे मतदान करते हैं। पठान होने के नाते इमरान खैबर-पख्तूनख्वा यानी केपी प्रांत में भी काफी लोकप्रिय हैं। ऐसे में वहां उनके समर्थकों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पाकिस्तान की सियासी तकदीर का फैसला पंजाब प्रांत ही करता आया है। केपी, सिंध और बलूचिस्तान में नेशनल असेंबली की जितनी सीटें हैं, उससे अधिक अकेले पंजाब में हैं। इसलिए असली राजनीतिक लड़ाई पंजाब में लड़ी जाएगी। इस बीच सेना ने वे सभी दांव भी चले हैं, जिनसे इमरान की पार्टी के अधिकांश बड़े नेता उनका साथ छोड़ गए और बचे-खुचे नेता भारी दबाव में हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में नवाज शरीफ ही मुनीर की पहली पसंद होंगे। नवाज राजनीतिक वनवास के बाद गत वर्ष नवंबर में ही पाकिस्तान लौटे हैं। तब से वह लगातार इमरान पर हमलावर हैं। उन पर लगे सभी प्रतिबंध हट गए हैं। वह नेशनल असेंबली की दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। सेना भी हरसंभव प्रयास करेगी कि उनकी पार्टी सरकार बनाने लायक सीटें ले आए। नेशनल असेंबली में 342 सीटें हैं। इनमें से 272 पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो 60 सीटें महिलाओं और 10 गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों का वितरण आनुपातिक प्रतिनिधित्व और चुनाव आयोग को प्रेषित अग्रिम सूची के आधार पर होता है। चूंकि पीटीआइ आधिकारिक रूप से चुनाव ही नहीं लड़ रही है तो फिर उसे आरक्षित सीटों में कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा। सिंध पीपीपी का मजबूत गढ़ है और वहां सत्ता हासिल करने में उसे खास परेशानी नहीं आएगी। वह पंजाब में पीएमएल-एन को टक्कर देने की कोशिश में लगी है, लेकिन उसे शायद ही कामयाबी मिले। बलूचिस्तान भौगोलिक रूप से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन राजनीतिक रूप से उतना महत्वपूर्ण नहीं। क्या पीएमएल-एन वहां अपना दमखम दिखा पाएगी?

अगर चुनाव जनरल मुनीर की मंशा के अनुरूप होते हैं तो पीएमएल-एल न केवल केंद्र में सरकार बनाने में सफल होगी, बल्कि पंजाब की सत्ता पर भी काबिज हो जाएगी। हालांकि नवाज शरीफ की सेहत पूरी तरह दुरुस्त नहीं, लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए तो वही पाकिस्तान की कमान संभालते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक कामकाज का व्यापक दारोमदार उनके भाई शहबाज शरीफ पर रहेगा, जिनके सेना के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वहीं, अगर पीटीआइ के समर्थक बड़ी संख्या में जीतकर आते हैं और भले ही सरकार बनाने में सफल न भी हों तो यह इमरान खान के लिए बड़ी नैतिक विजय होगी, जिससे सेना पर भी दबाव बढ़ेगा। तब पाकिस्तान एक ऐसे समय भारी अनिश्चितता की ओर बढ़ेगा, जब उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

अयोध्या के बाद आगे क्या

राजीव सचान

काशी और मथुरा के मामले हल होने चाहिए, लेकिन इसी के साथ देश को मंदिर-मस्जिद के विवादों से बाहर भी निकलना चाहिए

राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल यह प्रश्न किया था कि अयोध्या के बाद आगे क्या, बल्कि इसका उत्तर देते हुए यह भी कहा था कि हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नींव रखनी है। निःसंदेह ऐसा ही किया जाना चाहिए, लेकिन क्या काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामलों को ओझल किया जा सकता है? ये दोनों मामले पहले से ही अदालतों के समक्ष हैं और 1991 के उस पूजास्थल अधिनियम के बाद भी हैं, जो यह कहता है कि धार्मिक स्थलों का चरित्र वैसा ही रहेगा, जैसा 15 अगस्त 1947 को था। कई याचिकाओं के जरिये इस आधार पर इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है कि यह तो न्याय मांगने के बुनियादी सिद्धांत का ही उल्लंघन करता है। इन याचिकाओं का निर्धारण होना शेष है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि यह अधिनियम यह जानने पर रोक नहीं लगाता कि किसी धार्मिक स्थल का वास्तविक चरित्र क्या था। इसी कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो सका और शाही ईदगाह मस्जिद का कराए जाने की पहल हो रही है।

राम जन्मभूमि विवाद के समय मंदिर पक्ष की ओर से यह कहा गया था कि यदि अयोध्या, वाराणसी और मथुरा की मस्जिदें उसे मिल जाएं तो वह उन अन्य स्थलों से अपना दावा छोड़ देगा, जहां मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनाई गईं। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। अयोध्या में तो प्रमाण खोजने पड़े थे, लेकिन इसके लिए तो किसी साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं कि काशी और मथुरा में मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें खड़ी की गईं। खुद औरंगजेब के दरबारी की किताब में यह लिखा गया है कि ऐसा किया गया। इस तथ्य और सत्य को मस्जिद पक्ष भी जान रहा है, लेकिन अब वह तरह-तरह के बहाने बना रहा है। संसद की ओर से पारित नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले अब पूजास्थल अधिनियम का उल्लेख कर संविधान की दुहाई दे रहे हैं। ऐसा करने वाले मूर्तिभंजक औरंगजेब को दयालु शासक साबित करने की भी हास्यास्पद कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ वे अब अपने इस इस्लामी सिद्धांत से भी मुंह मोड़ रहे हैं कि झगड़े या किसी अन्य की इबादत वाली जगह पर बनाई गई मस्जिद में पढ़ी गई नमाज स्वीकार नहीं होती। यदि यह इस्लामी सिद्धांत तनिक भी मूल्य-महत्व रखता है तो फिर काशी और मथुरा में जबरन बनाई गई मस्जिदों पर नमाज पढ़ने की जिद का क्या औचित्य? यह तर्क बिल्कुल सही है कि जो औरंगजेब ने किया, उसके लिए आज के मुसलमान जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते, लेकिन यह तब दम तोड़ देता है कि जब इस बर्बर मुगल शासक के अत्याचारों को जायज ठहराने की कोशिश की जाती है या फिर इस प्रश्न से मुंह चुराया जाता है कि आखिर ज्ञानवापी परिसर की दीवारों पर अंकित देवी-देवताओं की प्रतिमाएं, हिंदू धर्म में महत्व रखने वाले प्रतीक और संस्कृत के श्लोक क्या कह रहे हैं?

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर। प्रेट्र

आज यह कहना कठिन है कि काशी एवं मथुरा के मामले कब और किस तरह सुलझेंगे, लेकिन यह आसानी से कहा जा सकता है कि इन विवादों की अनदेखी कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अच्छा यह होगा कि मस्जिद पक्ष की ओर से जो गलती अयोध्या मामले में की गई और एक बड़ा अवसर गंवा दिया गया, वह काशी एवं मथुरा के मामले में न हो। इन मामलों को आपसी बातचीत से सुलझाने की आवश्यकता है। यह काम तभी हो सकता है, जब मस्जिद पक्ष की ओर से सत्य को स्वीकार किया जाए। इसी के साथ उसकी इस आशंका का निवारण भी किया जाए कि आखिर काशी और मथुरा जैसे कितने मामले हैं? मंदिर पक्ष के लोग यह दावा करने में लगे हुए हैं कि ऐसे मंदिरों की संख्या सैकड़ों-हजारों में है, जिन्हें तोड़कर वहां मस्जिदें बनाई गईं। इससे इन्कार नहीं कि औरंगजेब जैसे शासकों ने बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ा और इसी कारण उत्तर भारत में कोई प्राचीन मंदिर मुश्किल से ही मिलता है, लेकिन उनकी संख्या को लेकर अलग-अलग दावे हैं। कोई सैकड़ों मंदिरों को गिना रहा है तो कोई हजारों। यदि इन सैकड़ों-हजारों दावों पर बल दिया गया तो फिर हमारे समक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से किया गया यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? कई लोगों को यह प्रश्न नहीं रास आया था, लेकिन आखिर इस पर तो विचार करना ही होगा कि देश कब तक मंदिर-मस्जिद विवाद में उलझा रहेगा?

काशी और मथुरा जैसे मामले तो समझ आते हैं, क्योंकि वे सदियों से आस्था के बड़े केंद्र होने के साथ देश की अस्मिता और उसकी संस्कृति-सभ्यता से जुड़े हैं, लेकिन क्या अन्य सैकड़ों-हजारों मंदिरों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है? क्या काशी और मथुरा के मंदिरों की तरह इन सैकड़ों-हजारों मंदिरों के भग्नावशेषों और उनके परिसरों में अनवरत पूजा-पाठ होता चला आ रहा है? मंदिर पक्ष को मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों पर दावा इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि मस्जिद पक्ष अयोध्या पर राजी नहीं हुआ और काशी एवं मथुरा पर सुलह-समझौते को लेकर सकारात्मक रवैया नहीं प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए अब हम इतने स्थानों पर दावा करेंगे। निःसंदेह काशी एवं मथुरा जैसे मामले सुलझने ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ मंदिर-मस्जिद विवादों से बाहर निकलने की कोई राह भी खोजी जानी चाहिए। इसी में सबका हित है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भय पर विजय

भय मन का एक नकारात्मक भाव है। यह भाव मनुष्य की तर्कशक्ति को निष्प्रभावी बना देता है। साथ ही उसकी रचनात्मकता तथा कल्पना करने की शक्ति को भी कुंद कर देता हैं। भय की उत्पत्ति का तो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन प्रायः यह असुरक्षा एवं एकाकीपन से उत्पन्न अवसाद के कारण उत्पन्न होता हैं। निडरता से तो डर को भी डर लगता है। स्वामी विवेकानंद ने यथार्थ ही कहा, 'भय से ही दुख आते हैं, भय से ही मृत्यु होती है और भय से ही बुराइयां उत्पन्न होती हैं।'

डर ने मनुष्य को बुरी तरह जकड़ कर रखा है। एक व्यक्ति को भय किसी दूसरे व्यक्ति एवं किसी वस्तु के कारण उत्पन्न होता है। डर मनुष्य के शारीरिक जीवन पर भी प्रभाव डालता है। जब किसी व्यक्ति को भय होता है तब वह व्यक्ति बहुत अधिक परेशान रहने लगता है। वह अपनी गतिविधियों को सीमित कर लेता है। यहां तक कि दूसरों के साथ संवाद को भी। यह स्थिति अहित ही करती है। गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी सीख दी है, 'अगर आज हम अपने डर पर काबू नहीं पा लेते तो कल हमारा डर हम पर काबू पा लेगा।'

अभ्यास एवं संयम के द्वारा भय पर नियंत्रण किया जा सकता है। अव्वल तो जीवन में कभी भी हमें भय को पास नहीं फटकने देना चाहिए। यदि किसी कारणवश भय करीब आता भी है तो उससे संघर्ष करना चाहिए। नेल्सन मंडेला ने भय से लड़कर उसे खुद से दूर रखने को ही सफलता की सीढ़ी मानते हुए कहा, 'मैंने यह जाना है कि डर का न होना साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर वह नहीं है जो भयभीत नहीं होता, बल्कि वह है जो इस भय को परास्त करता है।' इसलिए किसी भी कारणवश कोई भय आपको भयभीत करे तो उसे अनदेखा करने के बजाय उससे पार पाने का प्रयास करना चाहिए। तभी जीवन की परीक्षा में नैया पार लगेगी।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

जलवायु संकट से मुकाबला

सुधीर कुमार

पद्मश्री से सम्मानित चामी मुर्मु का प्रयास बताता है कि जलवायु संकट से मुकाबले के लिए दृढ़ता के साथ काम करने की जरूरत है

झारखंड के सरायकेला-खरसांवा की 52 वर्षीय चामी मुर्मु को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। 'झारखंड की लेडी टार्जन' कही जाने वाली इस 'आदिवासी महिला योद्धा' ने पांच सौ से भी अधिक गांवों में 28 लाख से भी अधिक पौधे लगाए हैं। साथ ही लगभग तीन हजार स्वयं सहायता समूहों (एनजीओ) के माध्यम से 30 हजार महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उन्नत भी बनाया है। सामान्य परिवार से संबंध रखने वाली चामी पिछले साढ़े तीन दशक से पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तीकरण के अभियान में तन्मयता से जुटी हैं। आज वह असंख्य महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन चुकी हैं। चामी जैसी पर्यावरण प्रहरियों का प्रयास यह बताता है कि जलवायु संकट का मुकाबला केवल सभा-सम्मेलनों में हिस्सेदारी देकर बड़ी-बड़ी बातें कहने से कतई मुमकिन नहीं है, बल्कि इसके लिए धरातल पर गुमनाम रहकर दृढ़ता के साथ काम करने की जरूरत है।

वर्ष 1988 में चामी ने 11 महिलाओं के साथ अपने ही गांव में 'सहयोगी महिला' नामक एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया। इस संगठन के तहत सबसे पहले एक पौधशाला (नर्सरी) प्रारंभ किया। इसके बाद पौधारोपण का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ा। एक निम्न आय वर्गीय परिवार से संबंध रखने और पितृसत्तात्मक समाज में होने के कारण उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें घर एवं समुदाय के लोगों द्वारा इस कार्य के लिए रोका गया। चामी को सबक सिखाने के लिए गांव के पुरुषों ने 1996 में उनके द्वारा लगाए गए एक लाख से भी अधिक पौधों को नष्ट कर दिया। हालांकि वह पीछे मुड़ने के बजाय उसी दृढ़ता से जुटी रहीं। वह अपना परिवार पर्यावरण को मानती हैं। पेड़-पौधे उनके घर के सदस्य की तरह हैं। वर्ष 2000 में उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार तथा 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

चामी और उनके सहयोगियों द्वारा जल संचयन, जैविक कृषि, महिला सशक्तीकरण और महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किए जा रहे हैं। आज अपने साथ वह हजारों महिलाओं का नेटवर्क स्थापित करने में सक्षम हो पाई हैं। इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ही वे अपने कार्यों को आगे बढ़ा पाने में कामयाब हुई हैं। समूह की सदस्य महिलाएं न सिर्फ पौधे लगाती हैं, बल्कि उनकी देखभाल भी अपना दायित्व समझती हैं। बहरहाल चामी मुर्मु समेत देश के अनगिनत पर्यावरण योद्धाओं के साथ-साथ आमजन को भी पर्यावरण संरक्षण के निमित्त अपने प्रयास जारी रखने होंगे। याद रहे, जलवायु परिवर्तन से निपटना सतत एवं सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

शिक्षा के समक्ष चुनौतियों का संज्ञान

'शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की चुनौती' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने सही कहा है कि उन्हीं देशों का भविष्य सुनहरा बनता है, जहां ज्ञान-बुद्धि-विवेक को प्राथमिकता मिलती है। उन्होंने 'असर' की रिपोर्ट का संदर्भ भी दिया है। यह संदर्भ इसलिए नहीं चौंकाता, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कक्षा 10 तक सभी बच्चों को उत्तीर्ण करने की लगभग अनिवार्यता है। वास्तव में, कक्षा आठ तक के सरकारी स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था और अधिकांश प्राइमरी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षा सहित कुल छह कक्षाओं के लिए केवल एक अध्यापक का होना बहुत ही चिंता का विषय है। क्या एक अध्यापक के भरोसे अपेक्षाएं पूरी होने की संभावना है। सरकारी स्कूलों की गिरती साख के आधारभूत कारणों का विवेचन आवश्यक हो गया है। संसाधनों की देश में कमी नहीं है, किंतु उनके समुचित उपयोग का सोच नदारद है। मिड-डे मील जैसी व्यवस्था में अध्यापकों का बहुत समय चला जाता है। ऐसे में इसकी व्यवस्था किसी अन्य पक्ष को क्यों नहीं सौंप दी जाती? नई पीढ़ी की शिक्षा पर कोई भी समझौता देश के भविष्य के लिए खतरे जैसा है। इसलिए अध्यापकों पर प्रश्न उठाने और उनके सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था से पहले स्कूलों में पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की तैनाती अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी युवाशक्ति अपेक्षित स्तर के कौशल एवं ज्ञान के साथ स्कूलों से निकले और आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करते हुए देशहित में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके।

योगराज, खरड़ (पंजाब)

सनातन विरोधी सपा

उप्र विधानसभा में अयोध्या में प्रभु राम के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा निरूपित करने के समारोह पर बधाई देने के प्रस्ताव पर सपा के 14 सदस्यों ने विरोध में वोट दिया। सपा विधायकों का यह आचरण उसके उसी सोच की पुनरावृत्ति है जिसके अंतर्गत 1990 में कारसेवकों पर गोली चलाई गई थी। अगणित राम भक्तों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। 22 जनवरी के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण पाने के पश्चात भी अखिलेश ने "कभी बाद में" जाने को ही उचित समझा। उसके नेता राम भक्तों को "अराजक तत्व" कह रहे हैं। रामचरित मानस पर अनर्गल बयान दे रहे हैं। क्या किसी और धर्म और उनकी पुस्तकों के साथ ऐसी बेअदबी कर सकते हैं?

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

सरकारी स्कूलों की गिरती साख

'शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की चुनौती' शीर्षक से लिखे आलेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने सरकारी एवं सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों, प्रबंधकों या यूं कहें इसके कर्ताधर्ता के लिए इसकी गिरती साख को रोकने के जो तमाम उपाय सुझाए हैं। वह सभी पक्षों के लिए गौर करने लायक है। इसके बिना हम शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार की बात नहीं सकते हैं। शिक्षक समय से विद्यालय नहीं आता है, उसकी पठन-पाठन में रुचि नहीं है तो इसके कारणों की पड़ताल करनी होगी। शिक्षक बनना महज बेरोजगारी दूर करने का उपाय नहीं हो सकता है। यह सेवा है। यह शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को भी सोचना चाहिए। बारंबार रिपोर्ट आती है कि छठवीं-सातवीं के इतने प्रतिशत बच्चे कक्षा दूसरी-तीसरी के गणित और भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं। फिर विमर्श शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? सवाल है मौजूदा दौर में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को हर उस काम में लगा दिया गया है। जिसका संबंध अध्यापन से बिल्कुल नहीं है। उनसे इतर तमाम जानकारी की सूचना मांगी जाती है। निःसंदेह लोक कल्याणकारी अवधारणा के तहत यह भी जरूरी है। पर ऐसे तमाम माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के बीच कार्यों (कार्य की प्रकृति के आधार पर) का बंटवारा हो। तभी अपेक्षित सुधार देखने को मिलेंगे।

mukeshkr.m7542@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

50 हजार कुशल श्रमिकों की मांग की है इजरायल ने भारत से। अकेले हरियाणा से करीब 10 हजार निर्माण श्रमिकों के इजरायल भेजे जाने का प्रस्ताव है।

आजकल

परीक्षाओं को कदाचार मुक्त करने का प्रयास

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था-टेलीपरफार्मेंस से संबद्ध

लोकसभा से सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पास हो गया है। अब राज्यसभा में पारित होने के पश्चात इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही यह विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा। इसका मकसद देश में सभी तरह की सरकारी परीक्षाओं में किसी भी किस्म की गड़बड़ी पर लगाम लगाना है। ऐसा कर ही हम अपने योग्य और प्रतिभावान युवाओं को नकल और पर्चा लीक आदि हरकतों के कारण हो रही ज्यादती से बचा सकेंगे

मेहनतकश परीक्षार्थियों के हितों का ध्यान रखना जरूरी। फाइल

किसी भी प्रतियोगिता का उद्देश्य काबिलियत की परख करना होता है। पुराने जमाने में यह काम शासकों की सेनाओं में भर्ती के लिए किया जाता था। तब ऐसी परीक्षाओं का पैमाना शारीरिक सौष्ठव हुआ करता था। आधुनिक समय में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ाई-लिखाई और दिमागी समझ इसका आधार बनी, पर योग्यता तय करने के जिस परीक्षा की जरूरत होती है, अगर उसमें कदाचार यानी नकल और पर्चा लीक जैसे घुन लग जाएं तो क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है, जिससे निजात पाने की हर कोशिश पिछले एक-डेढ़ दशक में नाकाम साबित होती रही है। खास तौर से पेपर लीक और नकल कराने के मामलों में संगठित गिरोहों की घुसपैठ ने हालात बद से बदतर ही किए हैं, पर अब इसका एक पक्का इलाज मिलने जा रहा है।

सख्ती का उद्देश्य : इसके लिए केंद्र सरकार ने संसद में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 बिल पेश किया है। लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के पश्चात इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इस विधेयक में नकल और पर्चा लीक आदि परीक्षा से जुड़े कदाचार के मामलों में एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने और 10 साल कैद का प्रविधान किया गया है। सभी तरह की सरकारी परीक्षाओं में किसी भी किस्म की गड़बड़ी करने वालों पर पूरी तरह लगाम लगाने के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक का मकसद देश के योग्य और प्रतिभावान युवाओं के साथ संगठित गिरोहों की हरकतों के कारण हो रही ज्यादती पर रोक लगाना भी है। हालांकि तमाम भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधलियों की रोकथाम के लिए कुछ राज्यों ने सख्ती की है। पेपर लीक जैसे मामलों में शामिल लोगों पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई की गई हैं, लेकिन समय-समय पर आ रही कदाचार की घटनाओं से साबित हुआ है कि भर्ती परीक्षाओं में अवैध तरीकों से नैया पार लगाने की कोशिशें निरंतर जारी हैं। इसकी बड़ी वजह ऐसी धांधलियों के जरिये होने वाली बेहिसाब कमाई है, जिस कारण ऐसे काम संगठित गिरोह बनाकर अंजाम दिए जा रहे हैं।

उम्मीदवारों की हताशा : जब कभी प्रतियोगी या प्रवेश परीक्षाओं में कदाचार की बात उठती है, तब सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवारों की हताशा का आता है। अहम प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रतिष्ठित कोर्सों की प्रवेश परीक्षाओं के पर्चे अगर पहले से लीक हो जाएं, भर्तियों में पैसे लेकर धांधली की जाए या साठगांठ कर नकल कराते हुए परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण करा लिया जाए तो सबसे ज्यादा कष्ट उन मेहनतकश परीक्षार्थियों को होता है, जो अपनी प्रतिभा के बल पर किसी परीक्षा में अपनी योग्यता साबित करने का प्रयास करते हैं। पेपर लीक से चंद खोखले छात्रों को फायदा जरूर होता है, लेकिन ये घटनाएं अन्य हजारों उम्मीदवारों और छात्रों के लिए बेहद कष्टकर होती हैं। कदाचार का यह अनवरत सिलसिला परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए दोबारा तैयारी करने से लेकर आने-जाने और तमाम खर्चों को वहन करने का ही विकल्प छोड़ता है, जिसकी भरपाई की कोई ठोस कोशिश हमारे देश में किसी सरकार ने नहीं की है। कभी-कभार कुछ राज्यों की सरकारों ने ऐसे मामले सामने आने पर परीक्षा की फीस दोबारा भरने से छूट जरूर दी और अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में वापसी की मुफ्त यात्रा का विकल्प दिया, लेकिन इन हादसों से लगे घावों पर ऐसे मरहम ज्यादा राहत नहीं देते। ये घटनाएं लाखों बेरोजगारों को अत्यधिक आक्रोश से भर देती हैं। हालांकि योग्य छात्रों-उम्मीदवारों को यह बर्दाश्त नहीं कि सिस्टम की खामियों का नतीजा वे भुगतें, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर नहीं होंगी-ऐसा आश्वासन कहीं से नहीं मिलता था।

समस्या की जड़ कहीं और : असल में पिछले एक दशक में पर्चे लीक होने की घटनाओं का सिलसिला इतना बढ़ा है कि शायद ही कोई प्रतिष्ठित परीक्षा इसकी चपेट में आने से बच पाई हो। शिक्षक भर्ती के अलावा यूपी-पीसीएस, यूपी कंबाइड प्री-मेडिकल टेस्ट, यूपी-सीपीएमटी, एसएससी, ओएनजीसी और रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर हाल के कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर लीक हुए हैं। यह भी संभव है कि जो मामले उजागर नहीं हुए, वहां ऐसे चोर रास्तों से शायद सैकड़ों लोग नौकरी या प्रतिष्ठित कोर्सों में दाखिला पा गए हों। चूंकि ये हादसे लाख इंतजामों और इनके गिरोहों के भंडाफोड़ और धरपकड़ के बाद भी थमे नहीं हैं, इसलिए एक बड़ा सवाल यह है कि इस समस्या की जड़ कहीं और तो नहीं है? पेपर लीक कांडों का नहीं रुक पाना साबित करता है कि योग्यता का मापदंड तय करने वाली परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था पूरी तरह लुंजपुंज हो गई है। सरकारी व्यवस्था पर्चा लीक वाली घटनाओं को बहुत हल्के में लेती रही है, इसीलिए यह मर्ज लाइलाज बनता चला गया। यही कारण है कि जिन परीक्षाओं को हर योग्यता का मानक बनाया गया है, वे परीक्षाएं ही बेमानी प्रतीत होने लगीं।

इच्छाशक्ति से मिलेगा समाधान : तंत्र की नाकामी और अधिकारियों की सुस्ती एवं पर्चा लीक कराने वाले अपराधियों पर कोई अंकुश लगाना नामुमकिन नहीं है, बशर्ते सरकारें और संबंधित विभाग ऐसा करना चाहें। इस समस्या का एक पहलू बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों की बढ़ती चाहत से भी जुड़ा है। ऐसी ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ सौ या हजार पदों के लिए आवेदकों की संख्या लाखों में होती है। शिक्षक भर्ती जैसी नौकरियों के लिए योग्यता हासिल करने वाली टीईटी और सीटीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं तो एक कदम आगे बढ़ गई हैं। ये परीक्षाएं न तो कोई शैक्षिक योग्यता प्रदान करती हैं और न ही नौकरी दिलाती हैं, लेकिन नौकरी के लिए योग्य होने की ऐसी सीढ़ी बन गई हैं, जिसके माध्यम से नौकरी का कोरा आश्वासन ही मिलता है। फिर भी आलम यह है कि इनके आवेदकों की संख्या लाखों में होती है। इसी तरह अन्य सरकारी नौकरियों और मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेजों की प्रवेश परीक्षाओं में तो दसियों लाख परीक्षार्थियों का शामिल होना अब आम हो गया है। मांग ज्यादा और आपूर्ति कम होने की इन्हीं वजहों से सिस्टम में भ्रष्टाचार और अवैध हथकंडों की भूमिका बढ़ गई है। दूसरी तरफ समाज का एक खतरनाक रवैया भी सामने आया है, जिसमें लोग अपने बच्चों को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाली सरकारी नौकरियों आदि की तरफ ठेलना चाहते हैं। इस मामले में वे यदि वैध तरीकों से सफल नहीं हो पाते हैं तो इसके गैरकानूनी रास्तों को आजमाते हैं। ऐसे ही लोगों में बहुत से ऐसे हैं, जो डोनेशन देकर अच्छे संस्थानों की सीटें अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं। यही वे लोग हैं, जो किसी भी प्रवेश या भर्ती परीक्षा का पर्चा हासिल करने के हथकंडों को आजमाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से उन लाखों युवाओं की मेहनत और प्रतिभा व्यर्थ हो जाती है, जो अपनी काबिलियत के बल पर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।

हालांकि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 के प्रारूप और सुझावों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ईमानदार और योग्य युवाओं की राह रोकने वाले भ्रष्ट तंत्र पर पहरा बैठाना और संगठित गिरोह के रूप में नकल आदि कदाचार को बढ़ावा देने वाले लोगों पर लगाम लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यह काम राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ कड़े कानून बनाने और उस पर अमल सुनिश्चित करने से हो सकता है। यहां यह समझने की जरूरत है कि परीक्षाओं को आनलाइन कर देने या पर्चों को परीक्षा से पहले लाकरों में बंद कर देने भर से इंसान के अवगुणों पर पहरा नहीं बैठ जाता है। इसके लिए जरूरी है कि दोषियों की धरपकड़ हो और उन्हें सख्त सजा दी जाए। उम्मीद है कि परीक्षाओं में कदाचार रोकने संबंधी ताजा कानूनी पहल सिस्टम के दोषों को दूर करेगी और बेरोजगारी से बुरी तरह त्रस्त इस देश और इसके योग्य एवं प्रतिभावान युवाओं के सपनों को आकार देने संबंधी माहौल का सृजन करेगी।

प्रस्तावित विधेयक के उपयोगी सुझाव

पिछले कुछ दशकों में देश में पेपर लीक और नकल जैसे नैतिक पतन के मामले काफी देखे जा रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अर्से से हमारे शिक्षाविद् जिस नैतिक शिक्षा की बात देश में करते रहे हैं, उसे अपनाने की दिशा में कोई काम हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा को सिर्फ रोजगार से जोड़कर न देखा जाए, बल्कि उसे समाज से भी जोड़ा जाए, लेकिन ऐसी सकारात्मक स्थिति आने तक वे कानूनी उपाय करने ही होंगे, जिनके सुझाव प्रस्तावित परीक्षा विधेयक में दिए गए हैं। इसमें उल्लेखनीय सुझाव यह है कि उन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए, जो तय अभ्यर्थी के स्थान पर किसी और को परीक्षा दिलाने, पर्चा हल कराने में मदद करते हैं। परीक्षा केंद्रों के अलावा कहीं और परीक्षा आयोजित करने या परीक्षा से जुड़ी धोखेबाजी की जानकारी नहीं देने जैसे कार्य करते हैं। परीक्षा तंत्र पर पैसे अथवा किसी अन्य लाभ के लिए दबाव डालते हैं। इस विधेयक में उन व्यक्तियों और संगठित समूहों या संस्थानों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई के प्रविधान किए गए हैं, जो परीक्षा प्रणाली पर विभिन्न अनुचित साधनों के जरिये दबाव डालने की कोशिश करते हैं।

इसके अलावा विधेयक में दंड की मात्रा भी बढ़ाई गई है। जैसे मौजूदा समय में पेपर लीक करने के लिए तीन लाख से पांच लाख जुर्माना और एक से तीन साल की सजा या दोनों का प्रविधान है, लेकिन नया कानून बनने पर इस अपराध में जुर्माना एक करोड़ रुपये तथा सजा दस साल तक की हो सकती है। यही नहीं, अगर कोई सर्विस प्रदाता संगठन खुद इस तरह के अवैध तरीकों में शामिल पाया जाता है तो उसे चार साल तक परीक्षा आयोजित कराने से वंचित किया जाएगा और साथ ही उस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

-अभिषेक कुमार सिंह

खरी-खरी

जब नेताजी का ईडी से हुआ सामना

डा. प्रदीप मिश्र

महान नेताजी ईडी की पूछताछ के बाद बिना गिरफ्तार हुए लौटे तो हमने उनका साक्षात्कार लिया, ''ईडी वालों ने क्या पूछा?'' सबसे पहले तो यही पूछा कि ''बीस साल पहले हुई एक चोरी में आपका हाथ था या नहीं?'' ''हम बोल की श्रीमान! वह वाली चोरी जब हुई थी, तब हमारे दोनों हाथों में फ्रेक्चर था। यह देखिए डाक्टर का सर्टिफिकेट।'' फिर पूछा कि ''नेताजी यह बताइए कि चोरी को कानूनी रूप से मान्यता देने के आदेश पर यह सिग्नेचर आपका है या नहीं?'' ''बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस समय का यह आर्डर है, उस समय तक हम साक्षर नहीं हुए थे। तब हम अंगूठा लगाते थे।''

इसके बाद पूछा कि ''यह वाला पैसा आपको कहां से मिला?'' हम चुप रहे। कुछ बोलना, खतरे में पड़ना था, लेकिन ईडी वाले भी उस्ताद थे। बोले, ''माउंटेन सरीखा अमाउंट आपके घर से मिला। कुछ तो बोलिए। इतना पैसा हजम करेंगे तो आपकी हेल्थ प्राब्लम में फंस जाएगी। कम से कम डकार तो लीजिए।'' ''क्या है महोदय कि हमको स्मृति-लोप की व्याधि है, कुछ याद नहीं रहता। अब ऐसे में हम क्या बताएं कहां से आया।'' ''आपका विदेश में जो खाता है, उसके बारे में कुछ बताइए?'' ईडी वाले नया सवाल पूछे। फिर वही हमारा मास्टर जवाब, ''हम गरीब-गुरबा हैं, विदेश में कहां से खाता खुलवाएंगे?''

''और क्या पूछा?'' ''जो शापिंग माल है, वह कब बना? उसमें लगे पैसों का क्या हिसाब है?'' मैंने कहा कि ''वह हमारा नहीं हमारे बेटे का है। हमने एक पैसा नहीं लगाया है उसके निर्माण में। सारा माल उसने अपने पुरुषार्थ से खड़ा किया है।'' ''आपके बेटे ने जब यह प्रापर्टी खड़ी की थी, तब उसकी क्या उम्र रही होगी?'' ''यही कोई डेढ़-दो साल।'' ''इतना पुरुषार्थी बच्चा तो सिर्फ आपके घर में ही जन्म ले सकता है।'' इतना सुन हमें अपनी गलती समझ आ चुकी थी, इसलिए हम फटाक से बेहोश हो गए। इसी अवस्था में हमने दस घंटे बिता दिए। ईडी वालों ने थककर हमें पूछताछ की अगली तारीख दे दी। हम तुरंत उठे और शान से बाहर आ गए।

पोस्ट

इंग्लैंड के टेस्ट कोच ब्रैंडन मैकुलम शानदार प्रशिक्षक हैं। वह खिलाड़ी का कौशल निखारते हैं और सही नजरिया एवं तेवर अपनाना सिखाते हैं।
रमेश श्रीवत्स@rameshsrivats

हाल के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए लगता है कि विपक्षी मोर्चे आइएनडीआइए के घटक दल अब मोदी को हराने के बजाय अपना किला बचाने में जुटे हैं।
मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

प्रधानमंत्री मोदी से विपक्ष इतना ही सीख ले कि संसद में हंगामा करके पूरा सत्र अमूमन बर्बाद करने के बजाय उस मौके का इस्तेमाल करके अपनी बातों को देश तक कैसे कुशलता से पहुंचाया जा सकता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने हर आरोप का जवाब भी दे दिया और काम भी गिना दिया।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

उत्तराखंड सरकार की पहल पर नागरिक संहिता विधेयक नारी शक्ति के लिए बनेगा वरदान। इससे सभी धर्मों की बहनों के लिए विवाह की आयु एक होगी। तलाक के लिए भी एकसमान अधिकार होंगे। बहुविवाह और बाल विवाह पर भी पूर्ण प्रतिबंध होगा।
आतिफ रशीद@AtifRasheed80

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या उत्तराखंड की तरह अन्य राज्यों को भी समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करना चाहिए?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या संप्रग शासन के समय की आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र लाया जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बाबा साहब लिख गए कहां, कौन अध्याय,
किमत भ्रष्टाचार पर करिए ठोस उपाय।
करिए ठोस उपाय जायं जब पकड़े भाई,
ले बाबा का नाम लोग दे रहे दुहाई!
सरकारी भूखंड लिये नेता जी ताबा,
जब होती है जांच याद आते हैं बाबा!!
- ओमप्रकाश तिवारी

उत्तराखंड डायरी

भाजपा के मातृशक्ति वंदन से दुविधा में कांग्रेस

विकास धूलिया
स्टेट ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड

पौड़ी में आयोजित मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जागरण

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय किए गए वादे को पूरा करने के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया। समान नागरिक संहिता राज्य ही नहीं, अपितु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें नारी शक्ति को सशक्त बनाने और उन्हें समान अधिकार देने की भावना निहित है। यही नहीं, केंद्र की ही तरह राज्य सरकार भी महिला सशक्तीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और इस कड़ी में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं जिलों में जाकर महिलाओं के लिए आयोजित किए जाने वाले मातृशक्ति वंदन कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं। भाजपा सरकार के इन कदमों ने कांग्रेस के लिए दुविधा और चुनौतियां बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में यहां की मातृशक्ति ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्यमशीलता और विकास में भूमिका के कारण महिलाओं को इस पर्वतीय राज्य की आर्थिकी की रीढ़ भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण यह कि लोकतंत्र के महोत्सव यानी चुनावों में भी महिलाएं आगे रहती आई हैं। वर्ष 2014 एवं 2019 के पिछले दो लोकसभा चुनावों में महिलाओं की मतदान में भागीदारी पर नजर डालें तो उनका मत प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है। ऐसा ही परिदृश्य राज्य विधानसभा के पिछले चार चुनावों में भी दिखा है। ऐसे में यहां की मातृशक्ति को कोई भी दल कम आंककर नहीं चल सकता।

धामी सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रविधान किया है। बात नौकरशाही की करें तो जिलों में महिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर आसीन करने में सरकार पीछे नहीं है। सात से ज्यादा जिलों में डीएम, एसएसपी, एसपी, सीडीओ जैसे पदों की जिम्मेदारी महिला अधिकारी संभाल रही हैं। हाल में सरकार ने राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक पद यानी मुख्य सचिव पद पर आइएएस अधिकारी राधा रतूड़ी की नियुक्ति करके भी बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। बात यहीं तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के उत्थान को लेकर कई योजनाएं संचालित की गई हैं, जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है। इसमें आजीविका की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन। राष्ट्रीय और राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेशभर में अभी तक 65 हजार से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं, जिनसे 5.04 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। समूहों के गठन का क्रम निरंतर बना हुआ है। ये समूह कृषि-बागवानी के साथ ही हस्तशिल्प से जुड़े उत्पाद तैयार कर रहे हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी भी प्राप्त हो रही है। समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित किए जाने के बाद इसके बेहतर परिणाम आए हैं।

महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना को 2022 में सबसे पहले लांच किया। इसके अंतर्गत राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर समूहों से जुड़ी सवा लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक समूहों से जुड़ी 70 हजार से ज्यादा महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो गई है। प्रयास यह किया जा रहा है कि अगले पांच-छह माह के भीतर सवा लाख के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। वैसे भी केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में देश में लखपति दीदी का लक्ष्य तीन करोड़ रखा है। ऐसे में उत्तराखंड को भी इसका और अधिक लाभ मिलना तय है।

अब सरकार ने जिला स्तर पर मातृशक्ति वंदन के कार्यक्रमों की शृंखला भी प्रारंभ की है। इनमें मुख्यमंत्री धामी स्वयं प्रतिभाग कर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम महिला समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री का बड़ा माध्यम बन रहे हैं। इन कार्यक्रमों में महिलाओं की उमड़ रही भीड़ से सरकार और भाजपा, दोनों ही उत्साहित हैं। यही नहीं, सरकार जल्द ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है। समान नागरिक संहिता में भी महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। धामी सरकार द्वारा महिला उत्थान के दृष्टिगत उठाए जा रहे कदमों को लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। सरकार की इस कसरत को आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं को साधने से जोड़कर देखा जा रहा है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन सरकार के इन प्रयासों का लाभ राज्य की महिलाओं को ही मिल रहा है। यह अवश्य है कि इससे धामी सरकार ने कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती भी पेश कर दी है।

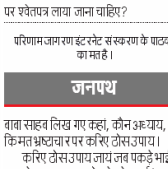

हरियाणा डायरी

बंद हो विदेश जाने का अवैध मार्ग

अनुराग अग्रवाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख, हरियाणा

अवैध तरीके से विदेश जाने वालों के प्रति सरकार का रवैया सख्त। फाइल

हरियाणा के जींद जिले में एक गांव है धतरथ। उस गांव में एक दुकान ऐसी है, जिस पर पूरे साल पटाखे मिलते हैं। धतरथ गांव के साथ आसपास के गांवों का कोई भी युवक जब सुरक्षित तरीके से विदेश पहुंच जाता है, तब उस दुकान पर पटाखों की अच्छी-खासी बिक्री होती है। गांवों में पटाखे चलाकर आस-पड़ोस के लोगों को संदेश दिया जाता है कि हमारा बेटा सुरक्षित विदेश पहुंच गया। यह मुद्दा अलग है कि बेटे को अवैध तरीके से विदेश भेजा गया था या फिर वह पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुए वैध तरीके से विदेश गया था। पंजाब के बाद हरियाणा देश का ऐसा दूसरा बड़ा राज्य बन चुका है, जहां के ज्यादा से ज्यादा युवा विदेश जाना चाहते हैं और जा भी रहे हैं। राज्य के कोचिंग सेंटर और इमिग्रेशन सेंटर खचाखच भरे रहते हैं। ट्रैवल एजेंटों ने बाकायदा अपनी दुकानों एवं कार्यालयों के बाहर बोर्ड लगा रखे हैं कि विदेश जाने के लिए उनसे संपर्क करें। कई मां-बाप अपने घर-बार, जमीन-जायदाद और सोना बेचकर अपने बेटे-बेटियों को विदेश भेजने का सपना पूरा करते हैं। लाखों रुपये ट्रैवल एजेंटों की भेंट चढ़ाते हैं। इसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि उनका लाड़ला सुरक्षित तरीके से विदेश पहुंच गया होगा।

हरियाणा सरकार के मंत्रियों द्वारा लगाए जाने वाले खुले दरबारों में सबसे अधिक मामले जब इस बात के आने लगे कि उनका बेटा विदेश गया था और वह सुरक्षित नहीं पहुंचा अथवा उससे वहां संपर्क नहीं हो रहा है तो सरकार की चिंता बढ़ी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा करने के उपरांत गृह मंत्री अनिल विज ने एक एसआइटी बनाई। जून 2020 से अब तक इमिग्रेशन में धोखाधड़ी के 1,008 मामले दर्ज किए गए और 662 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पांच करोड़ रुपये की राशि बरामद की गई है, जो लोगों से उनके बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर ली गई थी। पिछले साल दिसंबर में हरियाणा से अवैध इमिग्रेशन तब सुर्खियों में आया, जब फ्रांसीसी अधिकारियों ने निकारागुआ जाने वाली एक फ्लाइट को रोक दिया, जिसमें भारतीय थे, जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचने की योजना बना रहे थे। इस पूरे खेल में हरियाणा के ट्रैवल एजेंटों की अहम भूमिका रही थी।

समस्या की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार अब अवैध इमिग्रेशन पर स्थायी रोक लगाने के लिए विधानसभा के बजट सत्र में हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक लाने जा रही है, जिसमें लोगों से धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंटों को 10 साल की जेल तथा दो से पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रविधान किया जा रहा है। विधेयक में ट्रैवल एजेंटों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। फर्जी दस्तावेजों पर लोगों को विदेश भेजना भी इस कानून के तहत अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। साथ ही सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से स्वयं भी राज्य के कुशल युवाओं को विदेश भेजने की पहल की है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब सरकार अपने स्तर पर किसी युवा को विदेश में काम करने के लिए भेजेगी तो उसके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी।

फलस्तीन के साथ युद्ध के बाद इजरायल में निर्माण श्रमिकों की बेहद जरूरत आन पड़ी है। इजरायल ने भारत से करीब 50 हजार कुशल श्रमिकों की मांग की है। अकेले हरियाणा से करीब 10 हजार निर्माण श्रमिकों के इजरायल भेजे जाने का प्रस्ताव है। कई युवा तो ऐसे हैं, जो संबंधित देश की भाषा को सीखकर वहां जा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी तरह के व्यवधान का शिकार न होना पड़े। अब मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार और हिमाचल प्रदेश ने भी इजरायल द्वारा चलाए जा रहे भर्ती अभियान में शामिल होने की इच्छा जताई है। इन पांच राज्यों ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल से अपने युवाओं के लिए भर्ती अभियान चलाने का अनुरोध किया है। नेशनल स्तर पर इजरायल के लिए भर्ती अभियान की कमान राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल के हाथों में है। हरियाणा में यह भर्ती अभियान 16 से 20 जनवरी तक रोहतक में आयोजित किया गया था, जिसमें तब 1,370 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कंपनी सेक्रेटरी पल्लवी संधीर के अनुसार अगर भारत से पांच हजार उम्मीदवार इजरायल में पांच साल तक काम करते हैं तो भारतीय परिवारों के पास वेतन के रूप में पांच हजार करोड़ रुपये पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवर्तमान राजनीतिक सचिव अजय गौड़ का मानना है कि हमें भविष्य में माइंड एक्सचेंज का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। हमारे देश और प्रदेश के प्रतिभावान युवा जब बाहर जाएंगे तो वे आगे हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। इससे परिवार भी मजबूत होंगे। भारत एवं हरियाणा की इकोनमी मजबूत होगी। सुरक्षा की गारंटी अलग से है। प्रतिभावान युवाओं के पास अपना अलग हुनर होगा तो वे अधिक धन कमा सकेंगे।

****

156 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का कार्य जारी

नई दिल्ली : केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि देश में करीब 156 गीगावाट उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए कार्य जारी है। इसमें 103 गीगावाट क्षमता रिन्यूएबल्स, 26 गीगावाट थर्मल, 18 गीगावाट हाइड्रो और आठ गीगावाट परमाणु ऊर्जा शामिल है। केंद्रीय मंत्री के हवाले से मंत्रालय ने कहा कि 2031-32 तक देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 479 गीगावाट पर पहुंच जाएगी। (प्रेट्र)

भारत में समग्र कार उद्योग आगे बढ़ रहा है। इसका लाभ लक्जरी सेगमेंट को भी मिल रहा है। पिछले वर्ष कार उद्योग में बड़ी वृद्धि रही है, जो देश के विकास के अनुरूप है।

– बलबीर सिंह ढिल्लन, प्रमुख, आडी इंडिया

सेंसेक्स	72,186.09	454.67
निफ्टी	21,929.40	157.70
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 63,200	₹150
चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 74,900	₹600
डालर	₹ 83.05	₹ 0.02
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 77.92	

एक नजर में

आरबीआइ एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक शुरू

नई दिल्ली : आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक मंगलवार को शुरू हो गई। इस तीन दिवसीय बैठक में नीतिगत दरों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी गवर्नर शक्तिकांत दास आठ फरवरी को देंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई के मौजूदा स्तर को देखते हुए आरबीआइ इस बार भी रेपो दर को स्थिर रख सकता है। (प्रेट्र)

छह बैंकों में हिस्सेदारी खरीदेगा एचडीएफसी बैंक

नई दिल्ली : एचडीएफसी बैंक ने मंगलवार को बताया कि एचडीएफसी बैंक ने उसे छह बैंकों में 9.5 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दे दी है। जिन बैंकों में हिस्सेदारी खरीदी जानी है उनमें आइसीआइसीआइ बैंक, एक्सिस बैंक, सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। एचडीएफसी बैंक को एक वर्ष के अंदर यह हिस्सेदारी खरीदनी होगी। (प्रेट्र)

2024 में एशिया प्रशांत में कम रहेगी आर्थिक वृद्धि

नई दिल्ली : क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में कमी के चलते 2024 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि कम रहेगी। इससे क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पर असर होगा। लेकिन मजबूत घरेलू मांग से भारत इस चुनौती से पार पाने में सक्षम होगा। मूडीज ने पिछले वर्ष नवंबर में कहा था कि 2024 में भारत की विकास दर 6.1 प्रतिशत रहेगी। (प्रेट्र)

आर्थिकी में निवेशकों का भरोसा लौटा : सीईए

नई दिल्ली : मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा लौटा है। निजी निवेश में आ रही तेजी से यह बात पता चलती है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे सात प्रतिशत से ऊंची दर से वृद्धि हासिल करती। सीईए ने कहा कि मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के पीएमआइ इंडेक्स और शेयर बाजारों से भी इसका संकेत मिलता है। (प्रेट्र)

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर के साथ निर्यातक भी बनेगा भारत : मोदी

प्रधानमंत्री ने गोवा में किया दूसरे इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन, कहा– भविष्य की जरूरतों को देखते हुए हम अभी से कर रहे हैं तैयारी

जयप्रकाश रंजन ● पणजी

भारत अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए भले ही कच्चे तेल व गैस का बड़े पैमाने पर आयात करता है। लेकिन भारत अब ऊर्जा क्षेत्र के एक बड़े निर्यातक के तौर पर भी स्थापित होने लगा है। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जिस पैमाने पर निवेश की योजना बनाई है, उससे ऊर्जा क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, बायोमास, पेट्रोरसायन के एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता के तौर पर भी स्थापित होगा। दक्षिण गोवा के बेतुल में दूसरे इंडिया एनर्जी वीक (आइईडब्ल्यू) का उद्घाटन करते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी ने यही संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय इकोनमी में गैस क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ही अगले 6-7 वर्षों में 67 अरब डालर का निवेश होगा। इससे देश में प्राकृतिक गैस का हिस्सा मौजूदा 6 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो जाएगा।

पीएम मोदी ने बताया कि भारत पहले ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। साथ ही यह तेल व एलपीजी का भी तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक, चौथा बड़ा रिफाइनर, चौथा सबसे बड़ा आटोमोबाइल बाजार भी है। भारत में दोपहिया व चार पहिया वाहनों के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अनुमान है कि 2045 तक भारत में एनर्जी की मांग दोगुनी हो जाएगी। यानी आज अगर हमें हर रोज 1.9 करोड़ बैरल तेल की जरूरत है तो वह 2045 तक 3.8 करोड़ बैरल तक पहुंच जाएगी। भविष्य की इन जरूरतों को देखते हुए भारत अभी से तैयारी कर रहा है। देश के हर कोने में किफायती कीमत पर ऊर्जा दी जा रही है। भारत ऐसा देश है जहां वैश्विक संकट के बावजूद बीते 2 सालों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि ऊर्जा सेक्टर में विश्व के विकास की दिशा भी तय कर रहा है। पीएम ने बताया कि आज पूरी दुनिया के विशेषज्ञ भारत के जल्द तीसरी सबसे बड़ी इकोनमी बनने की बात कह रहे हैं।

11.11 लाख करोड़ के इंफ्रा निवेश से ऊर्जा क्षेत्र को लाभ मिलेगा : पीएम ने कहा कि अगले वर्ष के दौरान इन्फ्रा क्षेत्र में होने वाले 11.11 लाख करोड़ के नए निवेश का बड़ा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र में जाना तय है। इस राशि से रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज या हाउसिंग जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर में बनेगा, उसकी ऊर्जा की जरूरत होगी। भारत इस समय ऊर्जा में इतना निवेश कर रहा है, जितना पहले कभी नहीं हुआ था। यही वजह है कि भारत के आयल, गैस व ऊर्जा क्षेत्र में हर वैश्विक कंपनी निवेश करना चाहती है। पीएम ने यह भी बताया कि देश में रिफाइनिंग क्षमता को मौजूदा 25.4 करोड़ मीट्रिक टन सालाना से बढ़ाकर 45 करोड़ मीट्रिक टन बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

वैश्विक सीईओ से तेल-गैस क्षेत्र में निवेश की अपील : प्रेट्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आइईडब्ल्यू से इतर तेल व गैस क्षेत्र की शीर्ष-10 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत में मौजूद अवसरों और सरकार की ओर से तेल की खोज व उत्पादन में किए गए सुधारों की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, पीएम ने दिग्गज कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से भारत में इस क्षेत्र में निवेश की भी अपील की।

कार्बन उत्सर्जन में हमारी केवल चार प्रतिशत हिस्सेदारी

पीएम ने ग्रीन एनर्जी अपनाने में हो रहे प्रयासों का भी विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पेट्रोरसायन व पेट्रोलियम उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक बनने के बाद भारत जल्द ही हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनने वाला है। उन्होंने बताया कि दुनिया की 17 प्रतिशत आबादी भारत में रहती है फिर भी कार्बन उत्सर्जन में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ चार प्रतिशत है। सौर ऊर्जा क्षमता पिछले एक दशक में 20 गुना बढ़ी है। देश के नौ हजार पेट्रोल पंपों पर 20 प्रतिशत एथनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री शुरू हो चुकी है।

कतर के साथ एलएनजी खरीद समझौता बढ़ाया

आइईडब्ल्यू में कतर और भारत के बीच मौजूदा गैस समझौते को नए सिरे से लागू करने की सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच मंगलवार को गैस खरीद का नया समझौता हुआ है, जो वर्ष 2028 से वर्ष 2048 तक के लिए लागू होगा। इस समझौते का आकार 78 अरब डालर का होगा। पेट्रोनेट एलएनजी ने बताया कि उसने कतर एनर्जी के साथ सालाना 75 लाख टन एलएनजी आयात करने के लिए समझौता किया है। नए समझौते के मुताबिक, मौजूदा दर के मुकाबले एलएनजी की नई दर 0.8 डालर प्रति एमएमबीटीयू (प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट- गैस मापने का मापक) कम होगी और 20 वर्षों में भारत को कुल 6 अरब डालर की बचत होगी। पेट्रोनेट कतर से कुल 85 लाख टन एलएनजी हर वर्ष आयात करता है।

साउथ गोवा में मंगलवार को इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ● प्रेट्र

09 हजार पेट्रोल पंपों पर 20% एथनाल मिश्रित पेट्रोल की शुरू हुई बिक्री

67 अरब डालर का निवेश किया जाएगा गैस क्षेत्र में अगले 6-7 वर्षों के दौरान

15 प्रतिशत हो जाएगी इकोनमी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी इस निवेश से

चार अरब डालर का निवेश करेगा वेदांत समूह

बेतुल, प्रेट्र : दिग्गज खनन समूह वेदांत लिमिटेड ने अगले तीन वर्षों के दौरान तेल उत्पादन को दोगुना करने के लिए चार अरब डालर के निवेश की घोषणा की है। कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने आइईडब्ल्यू से इतर मंगलवार को कहा कि तेल और गैस विस्तार कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि भारत में संसाधनों के साथ बाजार भी है लेकिन दुर्भाग्य से यहां अपनी जरूरत का केवल 15 प्रतिशत तेल उत्पादित किया जाता है। शेष पूर्ति आयात से होती है।

सस्ती दरों पर भारत चावल की बिक्री शुरू

केंद्रीय सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने लांच किए चावल के पांच और दस किलो वाले पैकेट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण की कोशिशों के तहत केंद्र सरकार ने भारत चना दाल और आटा के बाद अब भारत चावल भी बाजार में उतार दिया है। केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को पांच एवं दस किलो के पैक में 29 रुपये प्रति किलो वाला 'भारत राइस' ब्रांड चावल लांच किया। इसकी बिक्री नैफेड एवं एनसीसीएफ (भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ) के साथ केंद्रीय भंडार के आउटलेट एवं प्रमुख ई-कामर्स प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने दावा किया है कि यह चावल औसत खुदरा कीमत से लगभग 34 प्रतिशत सस्ता है।

पीयूष गोयल ने इसकी सांकेतिक बिक्री की शुरुआत पांच लाभार्थियों को पांच-पांच किलो के पैक के जरिये की। साथ ही भारत चावल से लदी 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। पहले चरण में खुदरा बाजार में बिक्री के लिए पांच लाख टन चावल उतारा गया है। गोयल ने कहा कि सरकार की इस पहल से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रयासों से टमाटर और प्याज के मूल्यों को तेजी से नीचे लाने में मदद मिली है। गोयल ने कहा कि भारत आटा को लांचिंग के बाद आटे की महंगाई दर पिछले छह महीने से शून्य बनी हुई है। भारत राइस से चावल की महंगाई में भी यही असर दिखेगा। सरकार दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों को किफायती बनाने के लिए सक्रिय है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार चावल के मूल्य में 13.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग अनुसार, चावल का औसत खुदरा मूल्य मंगलवार को 43.98 रुपये किलो रहा, जबकि पिछले वर्ष समान तिथि में यह 38.7 रुपये किलो था।

नई दिल्ली में मंगलवार को लाभार्थी को भारत चावल का पैकेट देते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ● प्रेट्र

कंपनी व पर्सनल गारंटर के लिए एक ही पेशेवर

नई दिल्ली, प्रेट्र : अब कंपनी और उसके पर्सनल गारंटर्स की दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एक ही दिवाला पेशेवर काम कर सकेगा। भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आइबीबीआइ) ने इस पर लगी रोक हटा ली है। साथ ही स्वैच्छिक दिवालिया प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निदेशकों की ओर से लंबित कार्यवाही की जानकारी देना अनिवार्य बनाया गया है। यह बदलाव 31 जनवरी 2024 से प्रभावी हो गए हैं।

आइबीबीआइ ने पर्सनल गारंटर्स के दिवाला मामलों में कर्जदाताओं की समिति की बैठक संबंधी प्रविधानों में भी संशोधन किया है। ऐसे मामलों में कर्जदाताओं की समिति की बैठक को अनिवार्य बना दिया है। पहले पर्सनल गारंटर की पुनर्भुगतान योजना के मूल्यांकन के बाद दिवाला पेशेवर बैठक बुलाए जाने को लेकर रिपोर्ट देता था।

386.83 लाख करोड़ के नए स्तर पर बीएसई का पूंजीकरण

नई दिल्ली, प्रेट्र : घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को रही तेजी से बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 4.21 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इससे बीएसई का कुल पूंजीकरण 386.83 लाख करोड़ रुपये के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मंगलवार को बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 454.67 अंक की तेजी के साथ 72,186.09 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। इसी प्रकार, एनएसई का निफ्टी 157.70 अंकों की तेजी के साथ 21,929.40 अंक पर बंद हुआ।

बाजार विश्लेषकों ने कहा कि टीसीएस और इन्फोसिस जैसी दिग्गज आइटी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी, विदेशी निवेश के प्रवाह और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते घरेलू बाजारों में तेजी का माहौल रहा। चीन के बाजारों में सुधार से भी निवेशक उत्साहित दिखे हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि एमपीसी की बैठक के फैसलों से निवेशक बिकवाली से बचते दिख रहे हैं।

टीसीएस का पूंजीकरण 15 लाख करोड़ रुपये के पार

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के शेयर मंगलवार को बीएसई में 4.05 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,133.45 के स्तर पर जाकर बंद हुए। इस तेजी से कंपनी के पूंजीकरण में 59,074.88 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसके साथ कुल पूंजीकरण 15 लाख करोड़ के पार पहुंचते हुए 15.12 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

विदेश व्यापार करने वालों की दिक्कतें दूर करें बैंक

जासं, नई दिल्ली : वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी ने बैंक व इंश्योरेंस कंपनियों को निर्यातकों व आयातकों की बैंकिंग संबंधी सभी दिक्कतों को दूर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बैंकों से कहा कि वे व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मिलकर काम करें।

सोमवार देर शाम आरबीआइ, इंश्योरेंस प्राधिकरण, एसबीआइ व अन्य सरकारी बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के साथ विदेश व्यापार में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से कारोबार के लिए वित्तीय व्यवस्था, बैंकिंग व इंश्योरेंस सुविधा के साथ ई-बैंकिंग सर्टिफिकेट मिलने में देरी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा में सामने आया कि कुछ बैंकों में व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाने में समस्या आती है।

राष्ट्रीय फलक

पेटीएम ने रोक के संबंध में आरबीआइ से मांगा और समय

मुंबई, रायटर : डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने आरबीआइ के अधिकारियों से मिलकर नियामकीय चिंताओं को लेकर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार, पेटीएम ने आरबीआइ से 29 फरवरी को रोक संबंधी समयसीमा को बढ़ाने की मांग की है। साथ ही केंद्रीय बैंक से वालेट कारोबार व फास्टैग सेवा के लिए अपने लाइसेंस के हस्तांतरण के संबंध में और स्पष्टता की मांग की है।

सूत्रों के अनुसार,आरबीआइ ने पेटीएम की बात सुनी लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया है। इस संबंध में पेटीएम, आरबीआइ और वित्त मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को विजय शेखर शर्मा ने वित्त मंत्री से भी मुलाकात की और आरबीआइ की ओर से हाल में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ उठाए गए कदमों और उनके अनुपालन पर चर्चा की। बता दें कि आरबीआइ ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद बचत या चालू खातों में किसी भी प्रकार की जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। साथ ही वालेट, फास्टैग समेत सभी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में भी जमा पर रोक लगाई गई है। आरबीआइ के इस कदम के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद होने का संकट भी खड़ा हो गया है।

दूसरी ओर, लगातार तीन दिनों तक गिरावट के बाद पेटीएम के शेयरों में मंगलवार को तेजी दिखी। कारोबार के दौरान बीएसई में यह 7.79 प्रतिशत की तेजी के साथ 472.50 रुपये प्रति इकाई के उच्च स्तर तक पहुंचे। अंत में यह 3.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 451.60 रुपये प्रति इकाई पर बंद हुए। इस तेजी से कंपनी का बाजार पूंजीकरण 852.78 करोड़ रुपये बढ़कर 28,680.23 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। तीन दिनों में कंपनी के शेयरों में 42 प्रतिशत की गिरावट रही है।

पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने वित्त मंत्री से भी मुलाकात की

तीन दिन की गिरावट के बाद कंपनी के शेयरों में आई तीन प्रतिशत की तेजी

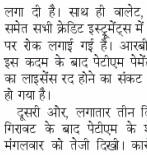

विजय शेखर शर्मा। फाइल फोटो

पेटीएम के साथ बातचीत कर रहा एचडीएफसी बैंक

नई दिल्ली : आरबीआइ की पाबंदी के बाद पेटीएम ने इन मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए कई बड़े बैंकों से संपर्क साधा है। इसी सिलसिले में पेटीएम की एचडीएफसी बैंक से साथ भी बातचीत चल रही है। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट पेमेंट प्रमुख पराग राव ने कहा कि बैंक अपनी साझेदारी को देखते हुए भी पेटीएम के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक इस मामले में इंतजार करो और देखो की नीति पर चल रहा है। राव ने कहा कि पेटीएम पर आरबीआइ की सख्ती के बाद एचडीएफसी बैंक के भुगतान एप और दुकानदार व्यवसाय को लेकर आकर्षण बढ़ा है।

ईडी और एफआइयू ने आरबीआइ से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : ईडी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआइयू) ने आरबीआइ से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संबंध में की गई कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट साझा करने के लिए कहा है। ईडी और एफआइयू धन शोधन रोधक कानून के तहत पेमेंट्स प्लेटफार्म्स के खिलाफ पहले से ही कई मामलों की जांच कर रही हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने से कहा कि ईडी ने आरबीआइ से ताजा रिपोर्ट साझा करने को कहा है ताकि यह विश्लेषण कर सके कि क्या उसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ जांच शुरू करने की जरूरत है। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

बांबे हाई कोर्ट ने चंदा व दीपक कोचर की गिरफ्तारी को बताया अवैध

मुंबई, आइएएनएस : बांबे हाई कोर्ट ने मंगलवार को आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व सीईओ एवं एमडी चंदा कोचर और उनके कारोबारी पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। साथ ही 2023 के अंतरिम जमानत आदेश की पुष्टि कर दी। कोचर दंपती को आइसीआइसीआइ बैंक-वीडियोकान कर्ज धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था। जनवरी, 2023 में जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे की पीठ ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान कर दी थी। जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और नितिन आर. बोरकर की खंडपीठ ने पिछले माह मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गत वर्ष जस्टिस मोहिते-डेरे ने कोचर दंपती को अंतरिम जमानत प्रदान करते हुए सीबीआइ से सवाल किया था कि जब एफआइआर 2019 में दर्ज की गई थी तो जांच में इतना वक्त क्यों लगा। कोचर दंपती को 23 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा, कोचर दंपती की गिरफ्तारियां प्रासंगिक कानूनों के मुताबिक नहीं थीं। जांच शुरू होने के चार वर्षों बाद उन्हें गिरफ्तार करने का कारण नहीं बताया गया था। उस समय कोचर दंपती के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में कहा था कि उनके मुवक्किल ने सीबीआइ के साथ पूरा सहयोग किया, पर तीन वर्ष कोई जांच नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। चंदा कोचर की गिरफ्तारी के वक्त कोई महिला पुलिस अधिकारी भी मौजूद नहीं थी। उनके पति स्वतंत्र कारोबारी हैं और चंदा ने उनके साथ बैंक से जुड़ा कोई विवरण साझा नहीं किया था। ज्ञात हो, सीबीआइ ने अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, पर शीर्ष कोर्ट ने बांबे हाई कोर्ट के समक्ष दलीलें रखने का निर्देश दिया था।

आइसीआइसीआइ बैंक-वीडियोकान कर्ज धोखाधड़ी मामला

संसदीय समिति ने कहा, बीमा कंपनियों को मिले समग्र लाइसेंस

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने मंगलवार को सुझाव दिया कि बीमा कंपनियों को सभी तरह के बीमा के लिए समग्र लाइसेंस दिया जाना चाहिए। इससे एक ही कंपनी जीवन, साधारण व स्वास्थ्य बीमा पेश कर सकेगी और देश में बीमा का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इंश्योरेंस अधिनियम 1938 के अनुसार, एक ही कंपनी को जीवन, साधारण व स्वास्थ्य बीमा सेवाओं के लिए समग्र लाइसेंस देने की अनुमति नहीं है। समिति का कहना है कि समग्र लाइसेंस से बीमा कंपनियों की लागत में कमी आएगी और उनको नियमों के अनुपालन में भी आसानी होगी। साथ ही बीमा उत्पादों खासतौर पर स्वास्थ्य व टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी दर घटाने का सुझाव दिया है। ज्यादा जीएसटी दर से प्रीमियम का बोझ बढ़ जाता है।

अवैध बालू खनन में जदयू एमएलसी की 26 करोड़ की संपत्ति जब्त

राज्य ब्यूरो, पटना

ईडी ने बिहार में अवैध बालू खनन मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मंगलवार को जदयू एमएलसी राधा चरण साह की करीब 26 करोड़ रुपये और ब्राडसन कंपनी के दो निदेशकों जगनारायण सिंह और सतीश कुमार की 12.96 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली। जब्त संपत्ति में 7.82 करोड़ की फिक्स्ड डिपाजिट (एफडी) भी शामिल है।

ईडी ने यह कार्रवाई बिहार पुलिस द्वारा ब्राडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो दर्जन से अधिक प्राथमिकियों के आधार पर की है। बता दें कि ईडी ने पिछले वर्ष राधा चरण साह, उनके बेटे कन्हैया प्रसाद और ब्राडसन कंपनी के निदेशकों में शामिल मिथिलेश सिंह, बबन सिंह व सुरेंद्र जिंदल को गिरफ्तार किया था। सभी जेल में हैं। जगनारायण सिंह और सतीश सिंह भी पिछले नवंबर माह से जेल में ही हैं।

ईडी के अनुसार, जांच में पाया गया था कि ब्राडसन कंपनी बालू के अवैध खनन व बिक्री को एक सिंडिकेट बनाकर नियंत्रित कर रही थी। राधा चरण साह इस सिंडिकेट के सदस्य थे। इस धंधे में जगनारायण और सतीश कुमार भी शामिल थे। इन लोगों ने सरकारी राजस्व को चूना लगाया, वहीं अवैध कमाई से देश के अलग-अलग हिस्सों में काफी संपत्ति अर्जित की। ब्राडसन ने खनन प्राधिकरण की ओर से जारी प्री-पेड परिवहन ई-चालान का उपयोग नहीं किया, जिससे सरकार को 161.15 करोड़ से अधिक के राजस्व की क्षति हुई। वहीं, अवैध बालू खनन व बिक्री से भी करीब 249.63 करोड़ का नुकसान हुआ।

ब्राडसन कंपनी के दो निदेशकों की 12.96 करोड़ की संपत्ति भी जब्त

बुजुर्ग दंपती ने टूटी सीटों पर किया सफर, एअर इंडिया को देना होगा 50 हजार रुपये हर्जाना

अंकेश ठाकुर, चंडीगढ़

आठ लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर बिजनेस क्लास के टिकट खरीदने के बावजूद 14 घंटे की यात्रा टूटी सीटों पर करने के मामले में पीड़ित बुजुर्ग दंपती को एअर इंडिया 50 हजार रुपये हर्जाना देना होगा। दरअसल, चंडीगढ़ निवासी राजेश चोपड़ा और उनकी पत्नी गामिनी ने जनवरी, 2023 में न्यूयार्क से दिल्ली की यात्रा की थी। फ्लाइट में टूटी सीटों पर यात्रा के दौरान उन्हें परेशानी हुई। उन्होंने एअर इंडिया के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत की। आयोग ने एअर इंडिया को शिकायतकर्ताओं को हुई परेशानी का जिम्मेदार मानते हुए विमानन कंपनी पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही कंपनी को मुकदमा खर्च के तौर पर 10 हजार रुपये भी देने का निर्देश दिया।

चंडीगढ़ के दंपती ने आठ लाख से अधिक रुपयों में खरीदे थे बिजनेस क्लास के दो टिकट

आयोग को दी शिकायत में राजेश व गामिनी ने बताया कि उन्होंने बिजनेस क्लास की दो सीटें बुक की थीं, जिसके लिए 8,24,964 रुपये का भुगतान किया था। वे दोनों लोग 20 जनवरी, 2023 को फ्लाइट पर सवार हुए और दूसरे दिन दिल्ली पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्लाइट में उन्हें जो सीटें दी गईं, वे टूटी हुई थीं। उन्हें 14 घंटे की यात्रा टूटी हुई सीटों पर बैठकर करनी पड़ी। यहां तक कि पैर रखने के लिए स्टूल दिए गए थे। इस वजह से उनके पैरों में सूजन और दर्द हुआ। राजेश ने कहा,वह कार्डियक मरीज हैं। ब्रेन स्ट्रोक के मरीज और दिव्यांग हैं। उन्होंने यह सोचकर बिजनेस क्लास की टिकट बुक किए थे कि वह बिना किसी परेशानी के आराम से यात्रा कर सकते हैं।

एयरलाइंस का कृत्य उसकी सेवा में कमी : आयोग

एअर इंडिया की तरफ से आयोग में कोई पेश नहीं हुआ। इस पर आयोग ने कहा कि स्पष्ट रूप से साबित होता है कि शिकायतकर्ता बुजुर्ग दंपती को फ्लाइट में जो सीटें उपलब्ध कराई गई थीं, वे खराब थीं। इस वजह से शिकायतकर्ता राजेश चोपड़ा के पैर में सूजन के कारण शारीरिक दर्द और परेशानी का सामना करना पड़ा। बुजुर्ग दंपती को लंबी हवाई यात्रा के लिए दोषपूर्ण सीटों के कारण मानसिक पीड़ा से भी गुजरना पड़ा। एयरलाइंस का कृत्य उसकी सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के समान है।

कच्चे माल के शाकाहारी-मांसाहारी श्रेणी में वर्गीकरण पर हाई कोर्ट ने मांगा सुझाव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बहुराष्ट्रीय कंपनी पतंजलि के विरुद्ध दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उन मानदंडों को तय करने के लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय से सुझाव मांगी है, जिनसे दवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल को शाकाहारी-मांसाहारी या अधिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने आयुर्वेदिक, सिद्ध व यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (एएसयूडीटीएबी) द्वारा गठित समिति को 10 सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें देने का निर्देश दिया।

अदालत ने यह निर्देश अधिवक्ता व याचिकाकर्ता यतिन शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। यतिन ने याचिका में पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उनका आरोप था कि पतंजलि द्वारा तैयार दिव्य मंजन में मांसाहारी तत्व होता है, पर इस शाकाहार उत्पाद होने का संकेत देने के लिए हरे बिंदु के साथ बेचा जाता है। अतः ग्राहकों को धोखा देने व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पतंजलि के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस संबंध में जुलाई 2023 में आयुष मंत्रालय से शिकायत की गई थी।

वहीं, मंत्रालय ने कहा, एएसयूडीटीएबी ने 25 मई, 2023 को हुई बैठक में दवाओं में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को शाकाहारी-मांसाहारी या अधिक श्रेणियों में वर्गीकृत करने के मानदंड तय करने के लिए समिति गठित करने की सिफारिश की थी। मंत्रालय ने कहा कि शाकाहारी या मांसाहारी को वर्गीकृत करने की व्याख्या विभिन्न धार्मिक, नैतिक और क्षेत्रीय विचारों पर निर्भर करती है।

याचिका में बहुराष्ट्रीय कंपनी पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी

न्यूज गैलरी

सुपर 30 संस्थापक आनंद कुमार को यूएई का गोल्डन वीजा

दुबई : सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार मंगलवार को भारत की उन प्रसिद्ध हस्तियों में शामिल हो गए जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। इस सूची में अभिनेता शाह रुख खान व संजय दत्त भी शामिल हैं। यूएई ने 2019 में गोल्डन वीजा शुरू किया जिसके तहत दीर्घकाल तक निवास, काम करने और अध्ययन करने की अनुमति दी जाती है। (प्रेट)

संघर्ष तेज होने के बीच म्यांमार के सैनिको ने बांग्लादेश में शरण ली

ढाका : म्यांमार में सैनिकों और विद्रोही अराकान आर्मी के बीच संघर्ष तेज होने के बाद अर्धसैनिक सीमारक्षकों के साथ म्यांमार के सैकड़ों सैनिकों ने मंगलवार को बांग्लादेश में शरण ली है। बांग्लादेश बार्डर गार्ड के अधिकारियों ने कहा, म्यांमार के 116 सैनिक अपनी चौकी से भाग खड़े हुए और बांग्लादेश आ गए। यह पहला मौका है जब म्यांमार की सेना सीमांत काक्स बाजार जिले में शरण लेने पहुंची है। (प्रेट्र)

गिरफ्तारी के बाद श्रीलंका के पर्यावरण मंत्री का इस्तीफा

कोलंबो : श्रीलंका के पर्यावरण मंत्री केहेलिया रांबुक्वेला ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इम्युनोग्लोबलिन खरीदारी घोटाला मामले में पुलिस के अपराध जांच विभाग ने दो जनवरी को रांबुक्वेला को 10 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि मंत्री का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। (प्रेट्र)

भारतवंशी अमेरिकी ने जालसाजी का दोष स्वीकारा

वाशिंगटन : भारतवंशी अमेरिकी जयप्रकाश गुलवाडी ने जालसाजी से नागरिकता प्राप्त करने व पासपोर्ट आवेदन में झूठा बयान देने का दोष स्वीकार कर लिया है। अस्थायी बिजनेस वीजा पर 2001 में अमेरिका आए जयप्रकाश ने नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक महिला से शादी की। 2008 में उसे तलाक देकर दूसरी महिला से शादी की। जून 2009 में वह अमेरिका का स्थायी निवासी बन गया। अगस्त 2009 में भारत गया और भारतीय महिला से शादी कर ली। नागरिकता और पासपोर्ट जालसाजी के अपराध के लिए जयप्रकाश को 10 वर्ष जेल की सजा हो सकती है। अमेरिका की नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। (प्रेट्र)

कनाडा में भारतवंशी पर मंदिर की दान पेटी से पैसे चुराने का आरोप

ओटावा : कनाडा के ब्रांप्टन क्षेत्र के निवासी 41 वर्षीय भारतवंशी जगदीश पंधेर पर मंदिर में ताला तोड़ कर घुसने और दान पेटी से पैसे चुराने का आरोप लगा है। पुलिस ने ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र में जांच की और संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा, गत वर्ष मार्च और अगस्त के बीच तीन मंदिरों में ताला तोड़कर प्रवेश करने और दान पेटी से पैसे निकालने की घटनाएं सीसीटीवी में कैद हुई। (प्रेट्र)

अमेरिका में तलवार से धमकी देने वाला गिरफ्तार

वैंकूवर : समुराई तलवार लहराकर लोगों को धमकी देने वाले व्यक्ति को वैंकूवर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा, रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे दक्षिण पश्चिम वाशिंगटन प्रांत के कई लोगों ने फोन पर इसकी जानकारी दी। पुलिस के पहुंचने से पहले वह व्यक्ति वालमार्ट में प्रवेश कर गया। पुलिस ने 43 वर्षीय व्यक्ति को दबोच लिया। उसकी जेब में पांच इंच का चाकू भी मिला है। (एपी)

अफगानिस्तान में 4.3 तीव्रता का भूकंप

काबुल : अफगानिस्तान में मंगलवार दोपहर बाद 4.3 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार, दिन के 3 :17 बजे के आसपास भूकंप के झटके लगे। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। (एएनआइ)

कजाखस्तान के राष्ट्रपति ने नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया

अस्ताना : कजाखस्तान के राष्ट्रपति कासयम जोमरात तोकायेव ने सरकार को बर्खास्त करने के एक दिन बाद मंगलवार को अपने चीफ आफ स्टाफ 43 वर्षीय ओल्झास बेक्तेनोव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। सोमवार को राष्ट्रपति के आदेश में मंत्रिमंडल के त्यागपत्र की घोषणा में इसका कारण नहीं बताया गया था। राष्ट्रपति ने गत वर्ष मंत्रियों की आलोचना की थी और मंत्रिमंडल को महंगाई रोकने के साथ ही देश के पुराने बुनियादी ढांचे को सुधारने में विफल रहने का दोषी ठहराया था। (एपी)

तुर्किये में अदालत पर हमले का प्रयास कर रहे दो हमलावर ढेर

इस्तांबुल : तुर्किये में अदालत पर हमले का प्रयास कर रहे दो लोगों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। गृह मंत्री अली येर्लिकाया ने कहा, कागलायान अदालत की सुरक्षा चौकी पर एक पुरुष व महिला ने हमले का प्रयास किया, जिसमें तीन पुलिसकर्मियों समेत छह लोग घायल हो गए। येर्लिकाया ने कहा, हमलावरों की पहचान रिवोल्यूशनरी पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के सदस्य के रूप में की गई है। (एपी)

नवाज के विरुद्ध लड़ने वाली पीटीआइ की नेता पर आतंकवाद का मुकदमा

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान में आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। इस दौरान जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआइ को कई बाधाओं से जूझना पड़ रहा है। ताजा झटके के रूप में पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ के विरुद्ध लड़ रहीं पीटीआइ समर्थित महिला प्रत्याशी डा. यास्मिन राशिद को कोर्ट ने मंगलवार को आतंकवाद के मामले में आरोपित बनाया है। पीटीआइ नेताओं ने कहा कि इन कदमों से पार्टी हतोत्साहित नहीं होगी।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी के उम्मीदवारों को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसका चिह्न क्रिकेट का बल्ला जब्त कर लिया है। पिछले साल नौ मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के चलते पीटीआइ को सेना का भी कोपभाजन बनना पड़ रहा है। इसके चलते पीटीआइ उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। इससे सेना की आंखों का तारा बनी पीएमएल-एन का रास्ता आसान हो गया है।

लाहौर की नेशनल असेंबली की सीट नंबर 130 से तीन बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ का मुकाबला पीटीआइ समर्थित मजबूत उम्मीदवार डा. यास्मिन राशिद से है। हालांकि, आतंकवाद निरोधी कोर्ट ने यास्मिन पर नौ मई की हिंसा के दौरान पुलिस थाने पर हमला करने के आरोप में मंगलवार को अभियोग दर्ज कर दिया है। पीटीआइ नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी के नेताओं और समर्थकों के घरों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। महिला कार्यकर्ताओं को भी परेशान किया जा रहा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि इन कदमों से पीटीआइ हतोत्साहित नहीं हो सकती।

पाकिस्तान में आम चुनाव कल, पीटीआइ ने कहा, इस प्रकार के कदमों से नहीं होंगे हतोत्साहित

पाकिस्तान के कसूर में मंगलवार को चुनावी रैली के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके छोटे भाई एवं पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तथा पुत्री मरयम नवाज। एएफपी

पाकिस्तान के चुनाव पर करीबी नजर रख रहा अमेरिका

वाशिंगटन, प्रेट्र : पाकिस्तान की चुनाव प्रक्रिया पर अमेरिका करीबी नजर रखे है। विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, पाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा और संपर्क के संबंध में उल्लंघन को लेकर अमेरिका चिंतित है। उन्होंने कहा, हम लोग आम चुनाव में लोगों की व्यापक भागीदारी की अपेक्षा करते हैं। इस बीच, न्यूयार्क टाइम्स ने कहा है कि पाक में गत वर्षों की तुलना में इस बार राजनीतिक प्रतिशोध ज्यादा दिख रहा है, जिससे होने वाले चुनाव की विश्वसनीयता धूमिल लग रही है। चुनाव के लिए 100 से ज्यादा विदेशी पर्यवेक्षक पाक में मौजूद हैं।

मतदान के दिन इंटरनेट बंद रख सकता है पाकिस्तान

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार में गृह मंत्री डा. गौहर एजाज ने कहा है कि गुरुवार को मतदान के दिन यदि किसी जिले या प्रांत ने आग्रह किया तो इंटरनेट सेवा बंद रखने पर विचार किया जाएगा। एजाज ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, अभी तक किसी स्थान पर इंटरनेट सेवा निलंबित रखने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। उनके साथ कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी भी मौजूद थे। एक दिन पहले सोलांगी ने आठ फरवरी को इंटरनेट बंद रखने की संभावना खारिज कर दी थी।

सिंध और बलूचिस्तान में हिंसा बढ़ी : पाकिस्तान के सिंध व बलूचिस्तान प्रांत में चुनाव से पहले हिंसा बढ़ जाने के कारण कई इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। दोनों प्रांत में प्रत्याशियों के साथ ही निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर हमले बढ़ गए हैं। रविवार रात तक चुनावी हिंसा में कराची, नुशकी और सिबी में सात लोगों की जान जा चुकी थी। बलूचिस्तान के औद्योगिक कस्बे हुब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) प्रत्याशी के कार्यालय पर बम से हुए हमले में तीन बच्चे घायल हो गए।

खैबर पख्तूनख्वा में दो आतंकी मारे गए : खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। कबायली क्षेत्र में बम विस्फोट में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए।

संयुक्त राष्ट्र ने इमरान को अयोग्य ठहराए जाने पर चिंता जताई : संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने पाकिस्तान में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं व प्रत्याशियों के विरुद्ध हो रही हिंसा की निंदा की है। उच्चायुक्त ने अधिकारियों से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध कई मामले पंजीकृत किए जाने और उन्हें अयोग्य करार दिए जाने पर भी चिंता जताई है।

पाकिस्तानी आम चुनाव से पहले मंगलवार को पेशावर में बैलट बाक्स सहित विभिन्न सामग्री व्यवस्थित करते कर्मचारी। एपी

अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे के बीच गाजा पर इजरायली हमले जारी

सऊदी अरब के बाद मिस्र पहुंचे ब्लिंकन, इसके बाद कतर व इजरायल जाएंगे

स्थायी संघर्ष विराम, बंधकों की रिहाई व मानवीय मदद मुहैया कराने का प्रयास

काहिरा, रायटर : पश्चिम एशिया में जारी तनाव का हल निकालने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के दौरे के बीच गाजा में इजरायली बलों के हमले जारी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब से वार्ता के बाद मिस्र पहुंच गए हैं। इस दौरान मंगलवार को गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 14 फलस्तीनी मारे गए हैं। इस तरह इजरायली हमले में अब तक मारे जाने वाले कुल फलस्तीनियों की संख्या बढ़कर 27, 585 हो गई। वहीं, इजरायल ने दावा किया है कि उसने 24 घंटे के दौरान पूरे गाजा में हथियारों से लैस दर्जनों फलस्तीनियों को मार गिराया है। इजरायली बलों के निशाने पर इन दिनों खान यूनिस और उसके पास विस्थापित फलस्तीनी हैं।

गाजा में स्थायी संघर्ष विराम के लिए अमेरिका समझौते की कोशिशों में जुटा है। पिछले साल सात अक्टूबर से गाजा में छिड़े युद्ध के बाद से अमेरिकी विदेश मंत्री का पश्चिम एशिया क्षेत्र में यह पांचवां दौरा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को कहा कि रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्षेत्र में शांति के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर चर्चा की है। इसमें स्थायी संघर्ष विराम, बंधकों की रिहाई और मानवीय मदद मुहैया कराना शामिल है। इसके बाद वह मिस्र पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से बातचीत शुरू की। मिस्र के बाद वह कतर और इजरायल जाएंगे। पिछले सप्ताह कतर और मिस्र के मध्यस्तों ने हमास को समझौता प्रस्ताव दिया था। इस पर वे हमास के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वहीं हमास का कहना है कि वह गाजा से इजरायल की वापसी को लेकर और गारंटी चाहता है।

यूएनआरडब्ल्यूए ने कहा, इजरायल के दावों पर जांच रिपोर्ट मार्च की शुरुआत में : फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट की एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए ने मंगलवार को कहा कि इजरायल के दावों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मार्च की शुरुआत में आने की उम्मीद है। यूएनआरडब्ल्यूए के लेबनानी प्रतिनिधि डोरोथी क्लाउस ने संवाददाताओं से बातीचत में यह जानकारी दी। इजरायल ने आरोप लगाया था कि यूएनआरडब्ल्यूए के एक दर्जन कर्मचारी सात अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमले में शामिल थे।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से भेंट की। एएफपी

लाल सागर में हाउती ने किए दो और जहाजों पर हमले

मध्य पूर्व के जल क्षेत्र में मंगलवार तड़के यमन के हाउती विद्रोहियों ने दो और जहाजों पर हमला किया, इसमें से एक अमेरिका से भारत की ओर जाने वाला जहाज शामिल है। दूसरी ओर, अमेरिकी-ब्रिटिश गठबंधन ने यमन के उत्तरी प्रांत सादा पर तीन हवाई हमले किए। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड आपरेशंस ने कहा, हाउती का पहला हमला होदेइदा के यमनी बंदरगाह के पश्चिम में लाल सागर के दक्षिणी हिस्से में हुआ। जिसमें पुल पर जहाज की खिड़कियों को मामूली क्षति हुई। यह ब्रिटेन के स्वामित्व वाला मालवाहक जहाज था। इसी तरह यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन के पास एक दूसरे जहाज पर हमला हुआ। एंब्रे ने इसकी पहचान मार्शल आइलैंड्स-ध्वजांकित, ग्रीक स्वामित्व वाले जहाज के रूप में की जो अमेरिका से भारत की ओर आ रहा था।

रूस के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार अकुनिन की गिरफ्तारी का आदेश

मास्को, एपी : मास्को की अदालत ने मंगलवार को चर्चित जासूसी उपन्यासकार बोरिस अकुनिन को आतंकवाद का महिमामंडन करने के लिए गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। उन पर दो माह पहले प्रैंक काल पर यूक्रेन का समर्थन करने का आरोप है।

मास्को की बासमेनी डिस्ट्रक्ट कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि बोरिस अकुनिन के नाम से मशहूर ग्रिगोरी चखरतिश्विल को गिरफ्तार कर लिया जाए। बीते दिसंबर में रूसी प्राधिकारियों ने रूसी-जार्जियन लेखक को अतिवादी और आतंकवादी के रूप में पंजीकृत किया गया था। अकुनिन पर सेना का अपमान कर आतंकवाद को उचित ठहराने का आरोप है। इसके साथ ही उन पर रूसी सेना के बारे में अफवाह फैलाने का भी आरोप है। फरवरी, 2020 में रूसी सेना के यूक्रेन पर हमले के बाद सेना का मजाक बनाना आपराधिक मामला जाता है। रूसी प्राधिकारियों द्वारा अकुनिन पर प्रतिबंध लगाने के बाद रूस के प्रमुख प्रकाशन एएसटी ने उनकी किताबों के प्रकाशन व बिक्री पर रोक लगा दी थी।

जपोरीजिया परमाणु संयंत्र की सुरक्षा पर यूएन एजेंसी ने उठाए सवाल : रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के जपोरीजिया परमाणु संयत्र की सुरक्षा को लेकर यूएन न्यूक्लियर वाचडाग प्रमुख ने मंगलवार को सवाल उठाया। रूस ने हाल ही में परमाणु संयंत्र के स्टाफ में कटौती की है। यह विश्व के दस बड़े संयंत्रों में से एक है। कीव पहुंचे अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा, उनका परमाणु संयंत्र का दौरा करने का उद्देश्य इसकी सुरक्षा में कटौती को लेकर है। इसकी सुरक्षा में 12 हजार कर्मी थे, जिसे रूस ने तीन हजार के बीच कर दिया है।

राष्ट्रपति चुनाव में लाभ के लिए हस्तक्षेप कर रहा बाइडन प्रशासन : संयुक्त राष्ट्र में रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि बाइडन प्रशासन राष्ट्रपति चुनाव में राजनीति चमकाने के लिए पश्चिम एशिया में हस्तक्षेप कर रहा है। रूस द्वारा बुलाई गई सुरक्षा परिषद की बैठक में भी अमेरिका-रूस में वाकयुद्ध हुआ। रूसी राजदूत ने कहा, अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानूनों को उल्लंघन कर रहा है।

आतंकवाद व यूक्रेन का समर्थन करने के आरोप में रूसी कोर्ट का फैसला

बोरिस अकुनिन। फाइल

एमक्यू-9बी ड्रोन से मजबूत होगी भारत की समुद्री सुरक्षा : अमेरिका

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका ने कहा है कि 31 सशस्त्र एमक्यू-9बी ड्रोन मिलने से भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी, यह उसे भविष्य के खतरों से निपटने में सक्षम बनाएगी। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ होगी। पिछले हफ्ते अमेरिका ने 3.99 अरब डालर के अनुमानित लागत वाले सशस्त्र ड्रोनों की बिक्री को मंजूरी दी है।

अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने सोमवार को नियमित प्रेसवार्ता में कहा, इन ड्रोनों की बिक्री की मंजूरी से भारतीय साझेदार के साथ हमारे संबंध और मजबूत होंगे। ये सशस्त्र ड्रोन समुद्री अभियानों के दौरान भारत की निगरानी क्षमता बढ़ाने में सहायक होंगे। इस मेगा सौदे का एलान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछले साल जून में अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान की गई थी। सौदे के तहत भारत को 31 हाई एल्टीट्यूड लांग एंड्यूरेंस (एचएएलई) ड्रोन मिलेंगे। ये ड्रोन 40 हजार फीट की ऊंचाई पर लगातार 40 घंटे तक उड़ सकते हैं। इससे ये दुश्मन की निगरानी रख सकेंगे। ये हवा से सतह पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम हैं। सौदे को मंजूरी की घोषणा के समय डिफेंस सिक्योरिटी कोआपरेशन एजेंसी (डीएससीए) ने कहा था कि भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंध मजबूत होने से अमेरिकी विदेश नीति को भी समर्थन मिलेगा। इसके जरिये हिंद-प्रशांत दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा स्थापित करने में मदद मिलेगी।

कहा, 31 ड्रोन सौदे से भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी भी होगी प्रगाढ़

अमेरिका के जनरल एटामिक्स एयरोनाटिकल सिस्टम्स इंक का एमक्यू-9बी ड्रोन। प्रेट्र

भारतवंशी वकील बना आस्ट्रेलिया का नया नस्ल भेदभाव आयुक्त

मेलबर्न, प्रेट्र : आस्ट्रेलिया में प्रमुख भारतवंशी वकील गिरिधरन शिवरामन को मानवाधिकार आयोग का नया नस्ल भेदभाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नस्ल भेदभाव आयुक्त सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव से निपटने और आस्ट्रेलियाई समाज के सभी वर्गों में समझ, सहिष्णुता और सौहार्द्र बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। वर्तमान में शिवरामन मल्टीकल्चरल आस्ट्रेलिया के अध्यक्ष और मौरिस ब्लैकबर्न में प्रमुख वकील है, जहां वह फर्म के क्वींसलैंड रोजगार कानून विभाग के प्रमुख हैं। अटार्नी जनरल मार्क ड्रेफस ने सोमवार को शिवरामन को नियुक्ति पर बधाई दी और कहा कि नस्ल भेदभाव और मानवाधिकार क्षेत्र में उनकी व्यापक समझ व प्रदर्शित जुनून आस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग के लिए बहुमूल्य साबित होगा। शिवरामन ने भी एक्स पोस्ट कर राष्ट्रमंडल नस्ल भेदभाव आयुक्त बनाए जाने पर आभार जताया।

चुनाव अभियान में भारतवंशी हेली को मिल रहीं धमकियां, मांगी सुरक्षा

वाशिंगटन, प्रेट्र : रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की दौड़ में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अंतिम चुनौती भारतवंशी निक्की हेली ने लगातार मिल रही धमकियों का हवाला देते हुए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस से सुरक्षा की मांग की है। हालांकि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद ही संबंधित को सुरक्षा प्रदान करती है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक चुनावी अभियान के दौरान हेली ने कहा, उन्होंने सुरक्षा के लिए सीक्रेट सर्विस में आवेदन किया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने आवेदन कब किया। निक्की ने यह भी नहीं बताया कि उन्होंने कब और किस तरह की धमकी मिली। दक्षिण कैरोलिना की गवर्नर 52 वर्षीय हेली के घर पर हाल के महीनों में मारपीट की दो घटनाएं हुईं थी। चुनाव प्रचार के दौरान हेली निजी सुरक्षा का इस्तेमाल करती हैं।

बाइडन से बहस करना चाहते हैं ट्रंप : रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नामित अपने प्रतिद्वंद्वियों से बहस करने से इन्कार कर चुके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से बहस करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, हमें देश की भलाई के लिए बहस करनी चाहिए। लास वेगास की यात्रा के दौरान ट्रंप द्वारा बहस के लिए बुलाए जाने के सवाल पर बाइडन बोले, मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है।

वर्तमान में प्रचार के दौरान निजी सुरक्षा का करती हैं इस्तेमाल

साउथ कैरोलिना में चुनावी अभियान के दौरान भारतवंशी निक्की हेली, जो रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति प्रत्याशी बनने की दौड़ में सम्मिलित हैं। एपी

इमरान की पत्नी बुशरा अपने घर को सब-जेल बनाने के विरुद्ध हाई कोर्ट पहुंची

इस्लामाबाद, प्रेट्र : जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने अधिकारियों द्वारा उनके आवास को सब-जेल घोषित करने के कदम के विरुद्ध मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। साथ ही संभावित सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए रावलपिंडी की अदियाला जेल भेजने का आग्रह किया।

जवाबदेही अदालत ने पिछले हफ्ते इमरान व उनकी पत्नी को सरकारी उपहारों को अवैध तरीके से बेचने से संबंधित तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 14 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। इसके बाद 49 वर्षीया बुशरा को इमरान के बानी गाला निवास में कैद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी संस्थापक इमरान अदियाला जेल में ही बंद हैं। जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना मामले में इमरान व बुशरा पर 1.57 अरब रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही इमरान को 10 वर्ष के लिए सार्वजनिक पद पर बैठने के लिए अयोग्य करार दिया है।

चिली में जंगल की आग में सैकड़ों लोग लापता

सैंटियागो, एपी : चिली के जंगल में लगी आग के कारण मरने वालों की संख्या 123 हो गई है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। मध्य चिली में बचावकर्मी राहत कार्य में जुटे हैं। वीना डेल मार शहर के पूर्वी छोर पर शुक्रवार को लगी आग सोमवार सुबह कम होने लगी थी। आग से वालपराइसो क्षेत्र के दो अन्य शहर क्विल्पे और विला एलेमाना भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

चिली फोरेंसिक मेडिकल सेवा के निदेशक मैरिसोल प्राडो ने कहा, कई शवों की पहचान कठिन है। जिन लोगों ने अपने रिश्तेदार के लापता होने की सूचना दी है, उनके जेनेटिक नमूने लिए जाएंगे। जबकि विना डेल मार के मेयर माकारेना रिपामोंटी ने कहा, शहर के लगभग तीन लाख निवासियों में से 370 लापता हैं। अधिकारियों का मानना है कि जानबूझकर आग भड़काई गई। शुष्क मौसम, तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है और चिली की मदद करने की बात कही है।

डीपफेक का शिकार बनीं एमएनएसी, 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी

जेएनएन, नई दिल्ली

वीडियो कान्फ्रेंसिंग काल कर बनाया निशाना, डीपफेक तकनीक से बनाया सीएफओ का एआइ अवतार

फर्जी सीएफओ ने रकम को ट्रांसफर करने को कहा, कर्मचारी ने असली समझ किया आदेश का पालन

हांगकांग की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को डीपफेक तकनीक का शिकार बनाया गया है। एआइ के जरिये कंपनी से 20 करोड़ हांगकांग डालर की ठगी की गई है। यह राशि 200 करोड़ रुपये से भी अधिक है। माना जा रहा है कि यह डीपफेक तकनीक से की गई सबसे बड़ी ठगी है। हांगकांग पुलिस ने यह नहीं बताया कि किस कंपनी के साथ ठगी की गई है। मामले की जांच चल रही है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। डीपफेक तकनीक में नकली वीडियो या आडियो रिकार्डिंग बनाने के लिए एआइ टूल का उपयोग किया जाता है।

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रविवार की रिपोर्ट के मुताबिक, साइबर अपराधियों ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग काल करके कंपनी को निशाना बनाया। इस दौरान डीपफेक तकनीक से कंपनी के सीएफओ के साथ अन्य कर्मियों का एआइ अवतार तैयार किया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान डीपफेक टेक्नोलाजी की मदद से मौजूद सीएफओ समेत सभी अधिकारी व कर्मचारी फर्जी थे। इसी दौरान फर्जी सीएफओ ने कंपनी की हांगकांग शाखा के वित्त विभाग के एक कर्मचारी को हांगकांग के पांच अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने को कहा।

कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि इस कंपनी का सीएफओ ब्रिटेन में था। जब डीपफेक वीडियो काल की गई तो वह झांसे में आ गया और बैंक खातों में 15 बार में 20 करोड़ हांगकांग डालर ट्रांसफर किए। अधिकारियों को लगभग एक सप्ताह बाद ठगी का अहसास हुआ, जिसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई।

आस्ट्रेलिया में भारतवंशी सीनेटर घोष ने भगवद् गीता पर ली शपथ

कैनबरा, एएनआइ : भारतवंशी बैरिस्टर वरुण घोष मंगलवार को भगवद् गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले आस्ट्रेलियाई संसद के पहले सदस्य बन गए। पश्चिमी आस्ट्रेलिया से वरुण घोष को नए सीनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है और विधान परिषद ने उन्हें संघीय संसद की सीनेट में आस्ट्रेलियाई राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है।

1985 में भारत में जन्मे वरुण ने पश्चिमी आस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय से कला व कानून में डिग्री प्राप्त की। वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून में राष्ट्रमंडल स्कालर थे। उन्होंने न्यूयार्क में एक वित्तीय मामलों के वकील और वाशिंगटन में विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में काम किया है। पर्थ में लेबर पार्टी में शामिल होने के बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 2019 के संघीय चुनाव में पश्चिमी आस्ट्रेलिया में घोष को लेबर पार्टी के लिए सीनेट टिकट में पांचवें स्थान पर रखा गया था लेकिन वह निर्वाचित नहीं हुए।

पीएम मोदी ने की किंग चार्ल्स के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय कैंसर से पीड़ित होने का पता चलने के बाद मंगलवार को लंदन में पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखे। वह क्लेरेंस हाउस से कार से बकिंघम पैलेस जा रहे थे। क्वीन कैमिला भी साथ थीं। रायटर

लंदन, रायटर : ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के कैंसर से पीड़ित होने की जानकारी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत दुनियाभर के नेताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बकिंघम पैलेस ने सोमवार को बयान जारी कर बताया था कि हाल ही में प्रोस्टेट के इलाज के दौरान की गई जांच में किंग को कैंसर की पुष्टि हुई। हालांकि यह नहीं बताया गया कि उन्हें कौन सा कैंसर हुआ है लेकिन उनका उपचार जारी है और वह स्वस्थ हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने एक्स पोस्ट कर कहा कि मैं भारत के लोगों के साथ मिलकर महामहिम किंग चार्ल्स तृतीय के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि किंग चार्ल्स का कैंसर शुरुआती चरण में पकड़ में आ चुका है और पूरे देश को उम्मीद है कि वह जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। उन्होंने कहा कि वह यह खबर सुनकर सदमे में हैं। हम सभी उनके और उनके परिवार के साथ हैं और जल्द ही सब पहले जैसा बेहतर होगा।

****

भारतीय टीम लगातार पांचवीं बार फाइनल में

रोमांचक सेमीफाइनल में द. अफ्रीका को दो विकेट से हराया कप्तान उदय और सचिन धास बने जीत के नायक

अंडर-19 विश्व कप

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : भारत की युवा टीम ने अंडर-19 विश्व कप में अपना अजेय सफर जारी रखते हुए मंगलवार को खेले गए सेमीफाइनल में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में दो विकेट से हरा दिया। उदय सहारन की कप्तानी वाली भारतीय टीम को जीत के लिए 245 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने आठ विकेट खोकर सात गेंद शेष रहते प्राप्त कर लिया। पांच बार की चैंपियन भारतीय टीम रिकार्ड नौवीं और लगातार पांचवीं बार अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल में उसका सामना आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता से होगा। अब भारतीय टीम अपने छठे खिताब से केवल एक कदम दूर है।

भारत के विरुद्ध पहली बार किसी टीम ने 200 से ऊपर का स्कोर बनाया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम शुरुआत में लड़खड़ा गई, लेकिन सहरान (81) और धास (96) ने पांचवें विकेट के लिए 171 रन की साझेदारी कर टीम को जीत तक पहुंचाया। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक अपना दबदबा बनाया था, लेकिन पहली बार उसे इतनी कड़ी टक्कर मिली। प्लेयर आफ द मैच चुने गए भारतीय कप्तान सहारन ने कहा, एक समय हम लक्ष्य से काफी पीछे थे। मैं बस खुद से कह रहा था कि मुझे अंत तक बल्लेबाजी करनी है और जीत बस एक साझेदारी दूर है। मैंने मैच को गहराई में ले जाना अपने पिता से सीखा है। हम ड्रेसिंग रूम में मनोबल कम नहीं होने देते हैं। टीम का माहौल और कोच शानदार हैं। फाइनल में पहुंचने पर बेहद अच्छा लग रहा है।

संक्षिप्त स्कोरबोर्ड

द. अफ्रीका : 244/7 (50 ओवर)
प्रिटोरियस : 76, सेलेट्सवेन : 64
राज लिंबानी : 3/60
भारत : 248/8 (48.5)
उदय सहारन : 81, सचिन धास : 96, मफाका 3/32, ट्रिस्टन लूस 3/37

सचिन-उदय की लाजवाब जोड़ी : लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही और उसने पहली ही गेंद पर आदर्श सिंह का विकेट गंवा दिया था। टूर्नामेंट में दो शतक लगाकर प्रचंड फार्म में चल रहे मुशीर खान केवल चार रन बनाकर आउट हो गए। एक समय भारत ने केवल 32 के स्कोर पर चार विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उदय सहारन और सचिन धास ने एक बार फिर टीम के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को संकट से निकाला। पिछले मैच में नेपाल के विरुद्ध भी इन दोनों बल्लेबाजों ने शतक जड़े थे और चौथे विकेट के लिए 215 रनों की रिकार्ड साझेदारी की थी।

लिंबानी की अगुआई में गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन : राज लिंबानी (3/60) की अगुआई में गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। शुरुआती 10 ओवर में ही दक्षिण अफ्रीकी टीम स्टीव स्टाक और डेविड टीगर के विकेट गंवा दिए। दोनों को लिंबानी ने चलता किया। प्रिटोरियस और सेलेट्सवेन ने 72 रन जोड़कर पारी को संभाला। दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम को भारत के तेज गेंदबाजों लिंबानी और नमन तिवारी ने विलोमूर पार्क की पिच से मिल रही गति और उछाल से काफी परेशान किया। प्रिटोरियस और सेलेट्सवेन भी तेज गति से रन बनाने में विफल रहे, जिससे अधिकांश समय रन गति चार रन प्रति ओवर से कम रही। बाएं हाथ के स्पिनरों स्वामी पांडे (1/38) व मुशीर खान (2/43) ने आफ स्पिनर प्रियांशु के साथ सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए रन गति पर अंकुश लगाया।

उदय और सचिन ● बीसीसीआइ

कब-कब फाइनल में पहुंचा भारत

वर्ष	कप्तान	बनाम	परिणाम
2000	मोहम्मद कैफ	श्रीलंका	छह विकेट से जीत
2006	रविकांत शुक्ला	पाकिस्तान	38 रन से हार
2008	विराट कोहली	द. अफ्रीका	12 रन से विजयी
2012	उन्मुक्त चंद	आस्ट्रेलिया	छह विकेट से जीता
2016	इशान किशन	वेस्टइंडीज	पांच विकेट से हार
2018	पृथ्वी शा	आस्ट्रेलिया	आठ विकेट से विजयी
2020	प्रियम गर्ग	बांग्लादेश	तीन विकेट से हार
2022	यश ढुल	इंग्लैंड	चार विकेट से जीता

पिता संजीव बोले- विश्वास था जब तक बेटा उदय क्रीज पर है, मैच हम ही जीतेंगे

सुभाष चंद्र, बठिंडा : भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के विश्व कप फाइनल में पहुंचने पर कप्तान उदय सहारन के पिता डा. संजीव सहारन भी बेहद खुश दिखे। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर मिली जीत के बाद उन्होंने कहा, एक पिता इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। बेटे ने कप्तानी पारी खेलकर टीम को फाइनल में पहुंचाया। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। उसकी यह पारी याद रखी जाएगी। 32 रन पर टीम के चार खिलाड़ी आउट हो गए थे। उदय ने सचिन धास के साथ टीम को फाइनल में पहुंचाने के लिए पूरा दम लगा दिया। मैच के दौरान उसके चाचा भी मुझसे कह रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन मैंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। जब तक उदय क्रीज पर खड़ा है, मैच हमारा ही है। आज बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। उदय की मैच जिताऊ पारी के बाद बठिंडा जिला क्रिकेट संघ (बीसीए) और एसएसडी कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज में खुशी का माहौल है। उदय एसएसडी कालेज में बीए फाइनल के विद्यार्थी है और बीसीए की टीम के कप्तान भी हैं। बीसीए के अध्यक्ष अरुण वधावन ने कहा कि उदय में विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनने के सभी गुण हैं। वह एक दिन जरूर भारतीय टीम में खेलेगा। उदय की पारी की जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। उदय के कालेज के निदेशक प्रो. एनके गोसाई ने कहा कि उदय ने बेमिसाल पारी खेली। उसने स्वजनों, संस्थान और बठिंडा शहर का नाम रोशन किया है। इस बार विश्व कप भारत की झोली में आएगा।

राजकोट से पहले टीम भारत को कई कमियां करनी होंगी दूर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : इंग्लैंड के विरुद्ध विशाखापत्तनम में बड़ी जीत के साथ भले ही भारतीय टीम ने सीरीज में वापसी कर ली हो, लेकिन इस टेस्ट में टीम की कई कमियां उजागर हुईं। पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट में 15 फरवरी से खेला जाएगा और टीम के पास 10 दिनों का समय है। इंग्लैंड की टीम पलटवार में माहिर है और अगर भारत को टेस्ट सीरीज जीतनी है तो उसे इन कमियों को दूर करना होगा।

बल्लेबाजों का दिखाना होगा दम : अगर दोनों मैच देखें तो भारतीय टीम एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में प्रदर्शन नहीं कर सकी है। बल्लेबाजों के व्यक्तिगत प्रदर्शन से टीम दूसरा मैच जीतने में सफल रही। युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल लगातार रन बना रहे हैं, लेकिन उनके जोड़ीदार रोहित शर्मा अब तक अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। यशस्वी जहां पहले टेस्ट में शतक से चूके तो दूसरे टेस्ट में उन्होंने दोहरा शतक जड़ा है। अब तक वह सीरीज में 321 रन बना चुके हैं, लेकिन रोहित कुल चार पारियों में 22.50 की औसत से केवल 90 रन ही बना पाए हैं। ये ओपनिंग जोड़ी अब तक एक भी बार 100 रन की साझेदारी नहीं कर पाई है। वहीं शुभमन गिल ने भले ही दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में शतक जड़ा है, लेकिन उनकी फार्म में भी निरंतरता का अभाव रहा है। विराट कोहली की अनुपस्थिति में मध्यक्रम टीम की सबसे बड़ी चिंता है। श्रेयस अय्यर अब तक चार पारियों में विफल रहे हैं और केवल 104 रन ही बना पाए हैं। पिछले मैच में पदार्पण करने वाले रजत पाटीदार भी छाप छोड़ने में विफल रहे और दो पारियों में केवल 41 रन बना पाए।

रोहित शर्मा ● फाइल फोटो, प्रेट्र

बुमराह के भरोसे गेंदबाजी : अगर गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह 15 विकेट लेकर टीम के सबसे सफल गेंदबाज हैं, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिला है। पहले टेस्ट में प्रबंधन ने बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज को अंतिम एकादश में जगह दी, लेकिन सिराज एक भी विकेट नहीं ले पाए थे। दूसरे टेस्ट में सिराज की जगह मुकेश कुमार को उतारा गया, लेकिन वह भी केवल एक ही विकेट ले पाए।

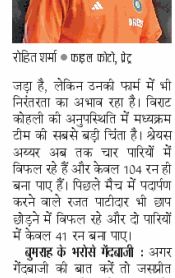

एक नजर में

भारतीय दिव्यांग टीम को पांचवें टी-20 में मिली हार

अहमदाबाद : कैलम फ्लिन के आलराउंड खेल से इंग्लैंड की दिव्यांग क्रिकेट टीम ने पांच मैचों की सीरीज के अंतिम मुकाबले में मंगलवार को यहां भारत को 22 रन से शिकस्त दी। इस हार के बावजूद सीरीज 3-2 से भारत के नाम रही। फ्लिन ने 43 गेंद में 53 रन की पारी खेलने के बाद 13 रन देकर दो विकेट चटकाए। इंग्लैंड ने 20 ओवर में छह विकेट पर 152 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम सात विकेट पर 130 रन ही बना सकी। (प्रेट्र)

भारतीय टीम फाइनल में

ढाका : नेहा के दो गोल की मदद से भारत ने मंगलवार को यहां अपने आखिरी लीग मैच में नेपाल को 4-0 से हराकर सैफ अंडर-19 महिला फुटबाल चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया। मैच का पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद नेहा ने 54वें और 80वें मिनट में गोल कर भारत को 2-0 से आगे कर दिया। टीम के लिए सुलांजना राउल (85वां मिनट) और रेमरौटपुई कोल्ने (90+3 मिनट) ने दो अन्य गोल किए। (प्रेट्र)

सचिन, सागर जीते

सोफिया : पूर्व विश्व युवा चैंपियन सचिन और सागर ने मंगलवार को यहां 75वें स्ट्रेंड्जा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सचिन (57 किग्रा) ने प्री क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के फेजोव खुदोनजर को 3-2 से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया जहां उनका सामना शुक्रवार को जार्जिया के केपेनाड्जे जियार्जी से होगा। सागर (92 किग्रा से अधिक) ने सर्वसम्मत फैसले में लिथुआनिया के जेजेविसियस योनास को 5-0 से हराया। वह क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के जोकिरोव जाखोनगिर से भिड़ेंगे। (प्रेट्र)

मोहसिन पीसीबी के पूर्णकालिक अध्यक्ष बने

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने मंगलवार को सर्वसम्मति से अनुभवी प्रशासक सैयद मोहसिन रजा नकवी को तीन साल के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। अध्यक्ष का चुनाव लाहौर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में बोर्ड आफ गवर्नर्स की एक विशेष बैठक में हुआ। नकवी ने कहा, 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर मैं बेहद सम्मानित और आभारी महसूस कर रहा हूं। मुझ पर दिखाए गए भरोसे और आत्मविश्वास के लिए मैं आभारी हूं। मैं देश में खेल के स्तर को सुधारने और पाकिस्तान में क्रिकेट प्रशासन में पेशेवरपन लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं।' 45 वर्षीय नकवी पीसीबी के 37वें पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। पाकिस्तान की टीम इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है।

रोहित को लेकर मार्क बाउचर के बयान पर रितिका का पलटवार

केपटाउन, प्रेट्र : मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच मार्क बाउचर ने माना कि रोहित शर्मा को बल्लेबाज के तौर पर स्वछंद होकर खेलने की आजादी देने के लिए टीम की कप्तानी से हटाने का कठिन निर्णय लेना पड़ा, लेकिन उनके इस बयान पर रोहित की पत्नी रितिका सजदेह ने पलटवार किया।

मार्क बाउचर ●

रितिका ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो में कमेंट करते हुए लिखा कि इसमें बहुत सी चीजें गलत हुईं।

मुंबई ने आइपीएल के इस सत्र में रोहित की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था। बाउचर ने कहा कि हमने हार्दिक को एक खिलाड़ी के रूप में वापस लाने के लिए एक विंडो देखी। हमें खिलाड़ी के तौर पर रोहित की आवश्यकता है। वह टीम के लिए काफी अहम खिलाड़ी है और हम चाहते हैं कि वह कप्तानी का बोझ लिए बिना अपने खेल का लुत्फ उठाए। पिछले कुछ सत्र से बल्ले से और कप्तान के तौर पर उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। हमने मुंबई इंडियंस समूह में सबसे चर्चा करने के बाद यह सोचा कि उन्हें अपने करियर के आखिरी कुछ वर्षों में स्वच्छंद होकर खेलने की आजादी दी जाए। बाउचर ने कहा कि वह अब भी भारत की कप्तानी कर रहे है ऐसे में आइपीएल में आने के बाद उनसे कप्तान वाला दबाव कम होगा। इससे शायद हम उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल कर पाए।

आइपीएल के आगामी सत्र में मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हटाने पर कोच मार्क बाउचर ने दी थी सफाई

जुलाई में जिंबाब्वे के साथ टी-20 सीरीज खेलेगी भारतीय टीम

क्रिकेट डायरी

हरारे, प्रेट्र : भारतीय टीम युवा खिलाड़ियों के साथ छह जुलाई से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी-20 सीरीज के लिए जिंबाब्वे का दौरा करेगी। जिंबाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को यह घोषणा की।

इस सीरीज का आयोजन वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप के तुरंत बाद होगा। इस सीरीज में हालांकि भारत के मुख्य खिलाड़ियों की भागीदारी की संभावना काफी कम है। सीरीज के सभी पांच मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में छह, सात, 10, 13 और 14 जुलाई को खेले जाएंगे। बीसीसीआइ सचिव जय शाह ने कहा, 'बीसीसीआइ ने वैश्विक क्रिकेट समुदाय में योगदान देने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। इस समय जिंबाब्वे क्रिकेट को हमारे समर्थन की जरूरत है।'

विलियमसन के 31वें टेस्ट शतक से कीवियों को विशाल बढ़त

माउंट मोंगानुई, प्रेट्र : पूर्व कप्तान केन विलियमसन की मैच में दूसरी शतकीय पारी से न्यूजीलैंड ने दो मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका पर 528 रन की बड़ी बढ़त प्राप्त कर ली है। विलियमसन (ने टेस्ट में 31वां शतक जड़ते हुए टीम को मजबूत स्थित में पहुंचाया। पहली पारी में भी विलियसन ने 118 रन की पारी खेली थी। दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम चार विकेट पर 179 रन बना चुकी थी और डेरेल मिशेल (11) व टाम ब्लंडेल (पांच) क्रीज पर मौजूद हैं। विलियमसन टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले पांचवें कीवी बल्लेबाज है। उनसे पहले ग्लेन टर्नर, ज्योफ हावर्थ, एंड्रयू जोन्स और पीटर फुल्टन ने यह किया है। विलियमसन ने में 12 चौके और एक छक्का की मदद से 109 रन बनाए।

केन विलियमसन ● एपी

सबसे कम पारियों में 31 टेस्ट शतक

पारी	बल्लेबाज
165	सचिन तेंदुलकर
170	स्टीवन स्मिथ
170	केन विलियमसन

आइपीएल में मुंबई चैंपियंस की कप्तानी करेंगे सहवाग

नई दिल्ली, जेएनएन : पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग वेटरन प्रीमियर लीग (आइवीपीएल) में मुंबई चैंपियंस लीग की कप्तानी करेंगे। आइवीपीएल के पहले संस्करण का आयोजन 23 फरवरी से तीन मार्च तक देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा। सहवाग ने कहा, 'मैं आइवीपीएल का हिस्सा बनकर काफी उत्साहित हूं। मैं इस लीग में मुंबई चैंपियंस के लिए खेलूंगा। सभी से देहरादून में मुलाकात होगी।' वहीं, पूर्व आइपीएल खिलाड़ी इकबाल अब्दुल्लाह भी सहवाग के साथ इस लीग का हिस्सा होंगे। इस लीग का आयोजन भारतीय वेटरन क्रिकेट बोर्ड (बीवीसीआइ) कर रहा है।

गेंदबाजों ने गल्फ को दिलाई जीत

आइएलटी-20

नई दिल्ली, जेएनएन : गत चैंपियन गल्फ जायंट्स के लिए गेंदबाजों ने दुबई कैपिटल्स के विरुद्ध कमाल का प्रदर्शन करते हुए टीम की आइएलटी-20 के प्लेआफ चरण में पहुंचने की उम्मीदों को जीवित रखा है। जी फाइव व एंड पिक्चर्स पर प्रसारित मुकाबले में मंगलवार को गल्फ जायंट्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 126 रन ही बना पाई थी। लेकिन उसके गेंदबाजों ने इस छोटे लक्ष्य का भी बखूबी बचाव करते हुए दुबई कैपिटल्स की टीम को 18.3 ओवर में 107 रन पर ढेर कर दिया। टूर्नामेंट में गल्फ की सात मैचों में यह तीसरी जीत है और वह अब अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। अब तक केवल एमआइ एमिरेट्स की अगले दौर में जगह बना पाई है।

टास जीतकर दुबई ने गल्फ को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गल्फ की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पावरप्ले में ही 17 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद शिमरन हेटमायर (34) और कप्तान जेम्स विंस (32) ने टीम को संभाला और पांचवें विकेट के लिए 51 रन जोड़े। इस साझेदारी के टूटने के बाद टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए और 126 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दुबई के बल्लेबाजों की हालत तो और भी खराब रही। उसकी ओर से दासुन शनाका ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए।

पहली महिला हैंडबाल लीग भारत में होगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : भारत में मंगलवार को यहां दक्षिण एशिया की पहली पेशेवर महिला हैंडबाल लीग (डब्ल्यूएचएल) का अनावरण किया गया जिसमें छह टीम हिस्सा लेंगी। इसमें मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व, यूरोप और अफ्रीका के प्रमुख खिलाड़ी शामिल होंगे। एक कार्यक्रम में इस लीग के लोगो का अनावरण भी किया गया।

भारतीय हैंडबाल संघ के चेयरमैन और दक्षिण एशियाई हैंडबाल महासंघ के महासचिव आंदेश्वर पांडे ने कहा, 'यह लीग भारत में महिला हैंडबाल के लिए गेम-चेंजर बनेगी। हमारा उद्देश्य भारत में महिला हैंडबाल के मानक को ऊपर उठाना और खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए विश्व स्तरीय मंच प्रदान करना है।' पावना स्पोर्ट्स वेंचर की चेयरपर्सन प्रिया जैन ने कहा, 'लीग की अवधारणा का उद्देश्य न केवल महिलाओं में मौजूदा अंतर को पाटना है बल्कि पूरे भारत में महिला खेलों में भी बदलाव लाना है। हम अगले वर्ष जनवरी तक लीग की शुरुआत करने का लक्ष्य रख रहे हैं।' इस मौके पर एशियाई हैंडबाल संघ के टेक्निकल निदेशक अबदुल्ला जासेम अल-थेयब, भारतीय हैंडबाल संघ के कोषाध्यक्ष तेजराज सिंह और भारतीय टीम की कप्तान ज्योति शुक्ला मौजूद रहे।

महिला हैंडबाल लीग के लोगो का अनावरण करते एशियाई हैंडबाल संघ के निदेशक अबदुल्ला जासेम अल-थेयब, भारतीय हैंडबाल एसोसिएशन के लीग चेयरमैन आनंदेश्वर पांडे, पावना स्पोर्ट्स वेंचर की चेयरपर्सन प्रिया जैन व अन्य ● सौजन्य- आयोजक

बिम्सटेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के पहले संस्करण की शुरुआत

नई दिल्ली, जेएनएन : केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को यहां बिम्सटेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत की। पहली बार आयोजित होन वाली यह चैंपियनशिप नौ फरवरी तक चलेगी।

इस अवसर पर अनुराग ने कहा, 'दुनिया की 25 प्रतिशत आबादी दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में रहती है। सात बिम्सटेक देशों के एक साथ आने से, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र न केवल यात्रा और परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र बनेगा। इससे न केवल घनिष्ठ दोस्ती में मदद मिलेगी, बल्कि एक मजबूत खेल संस्कृति का निर्माण भी होगा, जो एथलीटों के बीच दोस्ती को मजबूत करने में भी मदद करेगा। इसी विचार के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल में शिखर सम्मेलन में इस खेल आयोजन की परिकल्पना की थी।' इस चैंपियनशिप में तैराकी, वाटर पोलो और डाइविंग स्पर्धाओं में 20 से कम आयु वर्ग के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

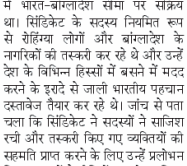

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ● साई

राष्ट्रीय फलक

केरल हाईकोर्ट का डा.वंदना हत्याकांड की सीबीआइ जांच का आदेश देने से इन्कार

केरल हाई कोर्ट ने आरोपित को जमानत देने से भी किया इन्कार

कोच्चि, प्रेट्र : केरल हाई कोर्ट ने युवा हाउस सर्जन डा. वंदना दास की हत्या की जांच सीबीआइ को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी। साथ ही हत्यारोपित जी.संदीप को जमानत देने से भी इन्कार कर दिया। डा. दास के माता-पिता ने सीबीआइ जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।

जस्टिस बेचू कुरियन थामस ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, जब डा.दास की मृत्यु हुई, तब मौजूद पुलिस अफसरों पर कोई आपराधिक इरादा रखने का आरोप नहीं लगाया गया था। थामस ने कहा, डाक्टर की जान बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई नहीं करने को लेकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है।

23 वर्षीय डा. दास के माता-पिता ने चिंता जताई थी कि हत्या मामले की जांच में राज्य पुलिस की ओर से चूक हुई है। जिन अधिकारियों ने आरोपित को चिकित्सा जांच के लिए एस्कार्ट किया था, और जिनकी उपस्थिति में डा. दास की मृत्यु हुई,उन पर भी हमले से बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया था। जब डा. दास आरोपित संदीप की चिकित्सकीय जांच कर रही थीं, तभी उसकी सर्जिकल सीजर से अनगिनत वार कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस संदीप को अस्पताल लेकर आई थी। माता-पिता का कहना है कि पुलिस इन अफसरों को बचाने के लिए मामले की जांच लापरवाही से कर रही थी। ऐसे में उन्होंने कोर्ट से मामले को सीबीआइ को ट्रांसफर करने का आग्रह किया था।

10 मई, 2023 को डा. दास की एक स्कूल शिक्षक संदीप ने कैंची से मारकर हत्या कर दी थी, जिसे एक झगड़े में घायल होने के बाद पुलिस द्वारा चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल लाया गया था। इस बीच, डाक्टर की हत्या के आरोपित ने जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए याचिका दायर की। उसने दावा किया कि वह निर्दोष था और उसे पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। याचिका में यह भी कहा गया कि घटना के समय संदीप मानसिक रूप से विक्षिप्त था। जस्टिस बेचू कुरियन थामस ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया।

अर्जुन पुरस्कार विजेता हाकी खिलाड़ी वरुण कुमार पर दुष्कर्म का आरोप,पाक्सो में केस दर्ज

महिला का आरोप, जब वह नाबालिग थी तब शादी का वादा कर उसका यौन उत्पीड़न किया

वरुण को हाल ही में पंजाब पुलिस में उपाधीक्षक पद पर किया गया है पदोन्नत

बेंगलुरु, प्रेट्र : अर्जुन पुरस्कार विजेता भारतीय हाकी खिलाड़ी वरुण कुमार के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने पाक्सो (यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया है। एक महिला का आरोप है कि जब वह नाबालिग थी, तब खिलाड़ी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। आरोप लगाने वाली महिला की उम्र अब बाइस साल है।

महिला ने सोमवार को दर्ज कराई गई शिकायत में कहा है कि वर्ष 2018 में इंस्टाग्राम के जरिये वरुण के संपर्क में आई। जब वह 17 साल की थी, वरुण ने शादी का वादा कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। उस समय वरुण भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) में ट्रेनिंग कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वरुण को हाल में पंजाब पुलिस में उपाधीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, महिला की शिकायत के आधार पर खिलाड़ी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की उचित धारा और भारतीय दंड संहिता की धारा- 376 (दुष्कर्म) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) के तहत मामला दर्ज किया है।

वरुण कुमार फाइल

टाक्यो ओलंपिक के लिए भारत की स्टैंडबाई सूची में शामिल वरुण अभी आगामी एफआइएच प्रो लीग के लिए भुवनेश्वर में राष्ट्रीय टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। भारत को अपने पहले मैच में 10 फरवरी को स्पेन का सामना करना है। ऐसी अटकलें थीं कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता भारतीय टीम में शामिल वरुण फरार हैं, लेकिन हाकी इंडिया ने इस अफवाह को खारिज कर दिया। हाकी इंडिया के एक सूत्र ने बताया, वह फरार नहीं हैं। वह टीम के साथ भुवनेश्वर में हैं। हिमाचल प्रदेश के वरुण ने 2017 में भारत की ओर से पदार्पण किया।

महिला के अनुसार, जुलाई 2019 में वह उसे बेंगलुरु के जयनगर के होटल में ले गए। वह नाबालिग है, यह जानते हुए भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब रोकने का प्रयास किया तो उसने शादी करने का वादा किया। एफआइआर में कहा गया कि महिला के पिता के निधन के बाद वरुण उससे मिलने गए लेकिन इसके बाद बातचीत करना बंद कर दिया। महिला ने कहा कि जब पिछली बार वह पुलिस के पास गई तो वरुण ने बातचीत शुरू कर दी। शादी के लिए जोर देने पर उसने फिर दूरी बना ली।

मानव तस्करी में पांच विदेशियों समेत 24 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट

एनआइए ने विशेष अदालत में दाखिल की चार्जशीट

आरोपितों ने तस्करी कर लाई गई महिलाओं को बेचा

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने पांच विदेशियों समेत 24 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा, असम में मानव तस्करी से संबंधित मामले में गुवाहाटी में एनआइए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है। आरोपितों में म्यांमार का एक और बांग्लादेश के चार नागरिक शामिल हैं।

संघीय एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा,जाली दस्तावेज के जरिये बांग्लादेश के नागरिकों और म्यांमार के रोहिंग्या लोगों की भारत में तस्करी करने वाले अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट में शामिल आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम के विभिन्न प्रविधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। पिछले साल नवंबर में राज्य पुलिस एजेंसियों के साथ मिलकर एनआइए ने त्रिपुरा, असम, जम्मू-कश्मीर व बंगाल में 39 स्थानों पर छापेमारी की थी और 25 लोगों को गिरफ्तार किया था। छापेमारी में बड़ी संख्या में दस्तावेज, जाली भारतीय पहचान दस्तावेज, बैंक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे। इसके बाद दिसंबर में त्रिपुरा से चार और आरोपितों को पकड़ा गया। प्रवक्ता ने कहा, जांच से पता चला है कि अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी सिंडिकेट त्रिपुरा, असम, बंगाल और अन्य क्षेत्रों में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सक्रिय था। सिंडिकेट के सदस्य नियमित रूप से रोहिंग्या लोगों और बांग्लादेश के नागरिकों की तस्करी कर रहे थे और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में बसने में मदद करने के इरादे से जाली भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कर रहे थे। जांच से पता चला कि सिंडिकेट ने सदस्यों ने साजिश रची और तस्करी किए गए व्यक्तियों की सहमति प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रलोभन दिया। तस्करों ने पीड़ितों का शोषण किया और बेहद कम पैसे पर नौकरी करवाई। तस्करी कर लाई गईं लड़कियों और महिलाओं का कई तरीके से शोषण किया गया। कुछ रोहिंग्या महिलाओं को बेच दिया गया।

****

त्वचा को नुकसान तो नहीं!

डा. कीर्ति मांडर देव
आयुर्वेद कास्मेटोलाजिस्ट

गोरा होने के चक्कर में कहीं आप अपनी त्वचा न बिगाड़ लें...। फेयरनेस क्रीम के प्रयोग में थोड़ा विचार की जरूरत है। दरअसल, इसमें रेटिन-ए आयल होता है जो स्किन को गोरा तो करता है लेकिन पतला भी बनाता है। इससे त्वचा में सूखापन, खुजली या अन्य समस्याएं होने लगती हैं। त्वचा भी

प्रकृति पर आधारित होती है। बिना अपनी त्वचा की प्रकृति जाने अगर कुछ भी प्रयोग करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। प्रकृति के हिसाब से उबटन के प्रयोग की परंपरा रही है।

फेशियल करवाने से चेहरे पर अक्सर चकत्ते पड़ जाते हैं। इसका कारण क्रीम नकली या खराब होना नहीं है, बल्कि बड़ा कारण यह है कि फेशियल करते हुए स्किन का टोन ही नहीं जाना जाता। सभी को एक ही तरह का फेशियल कर दिया जाता है। अब ब्राइडल फेशियल भी आयुर्वेद पर आधारित होने लगे हैं।

जानें त्वचा की प्रकृति : सर्दियों में तो ज्यादातर लोगों की त्वचा ड्राइ हो जाती है लेकिन किसी की त्वचा अगर गर्मियों में धोने के बाद भी ड्राइ हो रही है तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह वात प्रकृति का है। ऐसे में उसे खाने से लेकर लगाने तक में आयल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए।

- पित्त प्रकृति वाले लोगों की स्किन बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। उनका रंग पहले से गोरा होता है। इन्हें अपनी स्किन पर ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि गर्मियों में खस, गुलाब पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं।
- कफ प्रकृति वाले लोगों की स्किन काफी कुछ सहन करने वाली होती है।

बातचीत : विनीश गौड़

जीवनशैली

सेहत का सार पारंपरिक उपचार

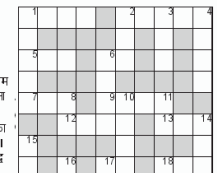

हाल में दिल्ली में पूर्णचंद्र गुप्त स्मारक ट्रस्ट और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेले में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी जैसी पारंपरिक उपचार विधाओं के विशेषज्ञों ने संपूर्ण सेहत और खुशहाल जीवन के कुछ ऐसे सूत्र बताए, जिनके जरिए हम स्वस्थ जीवन का आधार तैयार कर सकते हैं। यहां प्रस्तुत है आयुर्वेद, सिद्ध और होम्योपैथी विशेषज्ञों की कुछ सलाह, जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है...

फोटो: फ्रीपिक

आयुर्वेद

आरोग्य के लिए अपनाएं ये नियम

प्रो. तनुजा नेसारी
निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली

दिनचर्या ही नहीं ऋतुओं के साथ भी आरोग्य का गहन संबंध है। इसलिए हमें प्रतिदिन के साथ-साथ ऋतुओं के अनुसार भी रहन-सहन, खानपान और दिनचर्या को अपनाने की जरूरत है। आयुर्वेद में आहार-व्यवहार जैसी इन बातों का विशेष महत्व है। उदाहरण के तौर पर हम इस मौसम की बात करें तो यह उपवास करने और वजन कम करने के लिए सबसे उत्तम समय है। यदि इस मौसम में शरीर से गंदे और विषाक्त पदार्थों को नहीं निकालते हैं तो खांसी, जुकाम, एलर्जी से जुड़ी बीमारियों के होने की प्रबल आशंका रहती है। ऐसे में हमें कई स्तरों पर सतर्कता बरतने की जरूरत होती है।

कुछ नियमों का ध्यान रखें

- ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करें। यदि इस समय नहीं उठ पा रहे हों तो प्रयास करें कि सूर्योदय से पहले उठें।
- सुबह जागने के बाद अपने हर अंग पर विचार करें। ध्यान करें कि शरीर के किस अंग में कहां कैसी कठिनाई महसूस हो रही है। सुबह बिस्तर से उठने में जल्दबाजी न करें।
- व्यायाम ऐसा करें कि उसमें शरीर की कुल क्षमता की आधी ऊर्जा लगे। यदि आप एक किमी. टहलने में थक जाते हैं तो एक किलोमीटर ही चलें।
- गरम पानी से कुल्ला करें। ठंड के मौसम में गर्म पानी लाभदायक है।
- अभ्यंग यानी तेल मालिश से रक्तसंचार बढ़ेगा और मन को आराम मिलेगा।
- आयुर्वेद के अनुसार भोजन में छह रस का संतुलन होना चाहिए। ये हैं- मधुर (मीठा), लवण (नमकीन), अम्ल (खट्टा), कटु (कड़वा), तिक्त (तीखा) और कषाय (कसैला)।
- भोजन के समय ध्यान रखें कि पेट के आधे भाग में ठोस भोजन, एक चौथाई में द्रव और एक चौथाई भाग खाली रहे।
- नींद पर्याप्त नहीं लेने से पाचन क्रिया बिगड़ती है। दिन में देर तक सोने, रात में देर तक जागने से शरीर में पित्तदोष बढ़ जाता है। इसे संतुलित रखने का प्रयास करें।

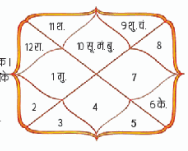

बातचीत : सीमा झा

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

सिद्ध से जीवनशैली को करें बेहतर

सिद्ध चिकित्सा

वैद्य जयंत देवपुजारी
चेयरमैन, नेशनल कमीशन फार इंडियन सिस्टम आफ मेडिसिन

सिद्ध चिकित्सा दक्षिण भारत की एक प्रचलित प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। लेकिन प्रभावी और सहज विधा होने के चलते अब इसकी उपयोगिता और आकर्षण बढ़ रहा है। दरअसल, सिद्ध चिकित्सा से संबंधित सामग्री तमिल में होने के कारण भारत के अन्य हिस्सों व विदेश में इलाज कराने में परेशानी होती थी। पर अब कई भाषाओं में अनुवाद होने से व्यापकता बढ़ रही है।

सुरक्षित और प्रभावशाली प्रणाली : सिद्ध चिकित्सा में अठारह सिद्धों को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगस्त्य ऋषि को सिद्ध चिकित्सा का संस्थापक माना जाता है। सिद्ध औषधियां बीमारी के कारण निष्क्रिय अंगों को पुनर्जीवित करती हैं और त्रिदोष को भी संतुलित बनाए रखने में मदद करती हैं। कायकर्पम (चिकित्सा और जीवनशैली का विशेष संयोजन) और मुप्पु (सार्वभौमिक नमक) सिद्ध की विशेषता है। कोरोना के इलाज में भी सिद्ध चिकित्सा सुरक्षित और प्रभावशाली रही। इससे कोरोना के लक्षणों में सुधार हुआ।

अनेक बीमारियों का उपचार : इसमें हर्बल औषधियों से सोरायसिस, एक्जिमा, एलोपेसिया, डायबिटीज, अल्सर, मस्से, विटिलिगो, पेम्फिगस, पोम्फालीक्स, कुष्ठ रोग और कई अन्य बीमारियों का सुरक्षित व कारगर उपचार होता है। सिद्ध चिकित्सा में व्यक्ति विशेष की प्रकृति के आधार पर औषधियों का निर्धारण किया जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि इसकी दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाती हैं।

प्रस्तुति : रोहित कुमार

चिकित्सक की सलाह से ही लें दवा

होम्योपैथी

डा. संगीता दुग्गल
सलाहकार, आयुष मंत्रालय

इन दिनों मोटापा, रक्तचाप, दिल की बीमारी, कैंसर, अवसाद जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। भारत में भी संक्रामक बीमारियों से ज्यादा बड़ी समस्या ये गैर-संक्रामक बीमारियां हैं। होम्योपैथी में इन सभी बीमारियों का इलाज संभव है। यह उपचार अधिक कारगर हो, इसके लिए एलोपैथ के साथ मिलकर भी काम किया जा रहा है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से उपचार में इन बातों का विशेष ध्यान रखें :

- होम्योपैथी में सैद्धांतिक रूप से हर व्यक्ति को अलग माना गया है। उसकी पसंद-नापसंद, आहार-व्यवहार को देखकर ही दवाइयां दी जाती हैं। ऐसे में चिकित्सक से इसकी चर्चा करें और उनकी सलाह पर ही कोई दवा लें।
- एक ही बीमारी के लिए कई दवाइयां हैं। चिकित्सक ही बता सकते हैं कि आपके लिए कौन-सी दवा उचित होगी।
- यदि रक्तचाप या शुगर की दवा ले रहे हैं तो लंबे समय तक सेवन न करें। दवा का प्रभाव कैसा है कितना सुधार है, इन सबकी जांच होती रहनी चाहिए।
- यदि दवा के समय व मात्रा का ध्यान न रखा जाए तो होम्योपैथी दवा का भी दुष्प्रभाव होता है।
- होम्योपैथी ले रहे हैं तो किसी विशिष्ट खानपान का त्याग करें, यह एक भ्रम है। आपको खाने के आधे घंटे पहले या बाद में दवा का सेवन करना चाहिए।
- खाना खाने के तुरंत बाद दवा खाने से भोजन में मौजूद तत्व दवा का असर कम या कोई दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। समय लेकर दवा का सेवन करने से यह जोखिम दूर हो जाता है।
- कुछ लोग दवा के प्रति संवेदनशील होते हैं। उन्हें एलर्जी हो सकती है।

वर्ग पहेली-2537

बाएं से दाएं

1. मनमुटाव, फूट, दरार (4)। 2. पारिश्रमिक, मजदूरी (5)। 5. मुग्ध (3)। 6. अवसर (2)। 7. दोष, अपराध, एक फिल्म का नाम (3)। 9. अंग्रेजी वर्ष का नौवां महीना (4)। 12. शरीर सहित (4)। 13. भांति, किस्म (3)। 17. वृक्ष का धड़ (2)। 18. जो अच्छा न हो (3)। 19. परमेश्वर (5)। 20. गंगा, बुद्ध की माता का नाम (4)।

ऊपर से नीचे

1. समर्थन करने वाला (5)। 2. पार्वती की माता का नाम, एक अप्सरा (3)। 3. दिखावटी अस्वीकृति, नाज-अदा (3)। 4. अज्ञात, अपरिचित (4)। 6. इस सदाबहार वृक्ष में छोटे-छोटे फूल खिलते हैं (4)। 8. आनंद, जल या कोई तरल पदार्थ (2)। 10. लालायित चीज की पूर्ति न होने देना (4)। 11. मग्न, प्रेम आदि में डूबा हुआ (2)। 14. उतावला, जल्दी मचाने वाला (5)। 15. कभी, किसी हालत में (4)। 16. फुटपाथ पर बिकने वाले साहित्य को ...साहित्य कहते हैं (3)। 17. रांगा, अंधकार (3)।

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

	आ1	मू2	ल		स3	रो	का4	र	
आ5		र्च्छि					र		का6
ज7	ब	त	क8		फ9		खा10	ति	र
त			ज		ह11	टा	ना		ग
क		ह12	रा	भ13	रा				
				ट14	ना	ट15	न		स16
आ17		क18	न	क		ह			हा
सु19	क	र्म		ना		नी20	ले21	गा	य
र		ही					ड़		ता
	ख22	न	क	ना		ले23	की	र	

जागरण सुडोकू-2537

5		3		1		6		2
	7					4	5	
8		2	5		6		1	
7			1			9		6
	3	6			5		2	
	1		6	9				5
2			9				3	7
1	8	7				2		9
3			2		8		4	1

कल का हल

1	6	7	3	9	5	8	4	2
3	4	2	8	6	7	1	9	5
5	9	8	2	4	1	7	6	3
7	1	3	9	2	4	5	8	6
2	8	9	5	1	6	3	7	4
4	5	6	7	3	8	2	1	9
6	7	4	1	5	2	9	3	8
9	2	1	6	8	3	4	5	7
8	3	5	4	7	9	6	2	1

आज का भविष्यफल- 07 फरवरी, 2024 बुधवार

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : माघ मास कृष्ण पक्ष द्वादशी।
आज का राहुकाल : दोपहर 12:00 बजे से 01 बजकर 30 मिनट तक।
आज का दिशाशूल : उत्तर। आज का पर्व एवं त्योहार : प्रदोषव्रत, तिल द्वादशी

कल 08 फरवरी, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : दक्षिण
पर्व एवं त्योहार : रटंती कालिका पूजन
भद्रा : प्रातः 11:18 से रात्रि के 9:41 बजे तक।
विशेष : बुध अस्त पूर्व में। वि. सं. 2080 शके 1945 उत्तरायण, माघ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तत्पश्चात चतुर्दशी उत्तराआषाढ़ा नक्षत्र तत्पश्चात व्यतिपात योग धनु में चंद्रमा तत्पश्चात मकर में।

- **मेष** : पिता या संबंधित अधिकारी से सहयोग मिल सकता है।
- **वृष** : शिक्षा प्रतियोगिता में श्रम सार्थक होगा। जीवन सुखमय होगा।
- **मिथुन** : स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। आर्थिक जोखिम न उठाएं।
- **कर्क** : दांपत्य जीवन सुखमय होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
- **सिंह** : आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा।
- **कन्या** : रचनात्मकता में सफलता मिलेगी। प्रयास फलीभूत होगा।
- **तुला** : निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
- **वृश्चिक** : जीविका में प्रगति होगी। यद्यपि पारिवारिक समस्या रहेगी।
- **धनु** : धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। पारिवारिक रिश्तों में वृद्धि आएगी।
- **मकर** : बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
- **कुंभ** : जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। रिश्तों में निकटता आएगी।
- **मीन** : उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

भारत ने हैजा पीड़ित जांबिया को मानवीय सहायता भेजी

नई दिल्ली : जांबिया में हैजा फैलने के बाद भारत ने मंगलवार को एक कार्गो विमान से मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 3.5 टन भेजी गई सहायता में जल शोधन आपूर्ति, क्लोरीन टैबलेट और ओआरएस पाउच के रूप में हाईड्रेशन शामिल हैं। इस बीच यूरोपीय संघ ने कहा है कि वह जांबिया को 10 लाख यूरो भेजकर मदद करेगा। हैजा से 35 लाख लोगों का जीवन खतरे में है। (एएनआइ)

बांग्लादेश के विदेश मंत्री की भारत यात्रा आज से

नई दिल्ली : बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद बुधवार को भारत पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महमूद को आमंत्रित किया है। शेख हसीना की चुनाव में जीत के बाद गठित बांग्लादेश की नई सरकार में विदेश मंत्री बनने के बाद महमूद की यह पहली भारत यात्रा होगी। हसीना चौथी बार देश की प्रधानमंत्री बनी हैं। सात से नौ फरवरी तक यात्रा के दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंध के विस्तृत क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करेंगे। (एएनआइ)

चेन्नई पहुंचे श्रीलंका से रिहा हुए 12 भारतीय मछुआरे

चेन्नई : श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 13 जनवरी को गिरफ्तार किए गए 12 भारतीय मछुआरे मंगलवार को चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंच गए। हालांकि कई भारतीय मछुआरे अभी तक श्रीलंका की हिरासत में हैं। मछुआरों की बार-बार गिरफ्तारी न केवल केंद्र सरकार के लिए, बल्कि तमिलनाडु सरकार के लिए भी चिंता का कारण है। सोमवार को रामेश्वरम में मछुआरों ने सांकेतिक हड़ताल कर समस्या का समाधान करने की मांग की। मछुआरों ने अपने मतदाता पहचान कार्ड लौटाने की घोषणा की है। (एएनआइ)

12 घुसपैठिए एक वर्ष बाद वापस भेजे गए

अगरतला : रोजगार की तलाश में भारत में घुसपैठ करने वाले 12 बांग्लादेशी नागरिकों को मंगलवार को स्वदेश भेज दिया गया। वापस भेजे गए लोगों में छह महिलाएं हैं। अगरतला स्थित बांग्लादेश सहायक उच्चायोग ने इनकी वापसी के लिए भारत से संपर्क साधा था। वे 2022 और 2023 के बीच अलग-अलग समय पर त्रिपुरा पहुंचे थे। (आइएएनएस)

लाक्षागृह की बढ़ाई गई सुरक्षा, खुफिया विभाग भी सतर्क

- अदालत ने सोमवार को हिंदुओं के पक्ष में दिया था फैसला
- सोमवार रात ही एसपी ने लिया था सुरक्षा व्यवस्था का जायजा

जागरण संवाददाता, बागपत

उप्र के बागपत जिले के बरनावा गांव के प्राचीन टीले को लेकर 53 वर्ष बाद हिंदुओं के पक्ष में आए फैसले के दूसरे दिन महाभारतकालीन लाक्षागृह पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। पुलिस और पीएसी के जवान जांच के बाद ही लोगों को लाक्षागृह पर जाने दे रहे हैं। खुफिया विभाग भी सतर्क है। क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखी जा रही, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

बागपत की जिला अदालत ने एएसआइ की रिपोर्ट और राजस्व रिकार्ड को आधार मानते हुए प्राचीन टीले को महाभारतकालीन लाक्षागृह (लाखामंडप) माना और मुस्लिम पक्ष के प्राचीन टीले पर दरगाह और कब्रिस्तान होने के दावे को खारिज कर दिया। अदालत के फैसले के बाद सोमवार देर रात एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने लाक्षागृह का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस को निर्देश दिए। सुरक्षा-व्यवस्था की दृष्टि से लाक्षागृह और आसपास पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं।

यह है पूरा मामला : बरनावा गांव निवासी मुकीम खां ने 31 मार्च 1970 में मेरठ की अदालत में वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने ब्रह्मचारी कृष्णदत्त को प्रतिवादी बनाया था। मुकीम खां ने दावा किया था कि बरनावा में प्राचीन टीले पर शेख बदरुद्दीन की दरगाह और बड़ा कब्रिस्तान है, जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड यूपी में बतौर वक्फ दर्ज व रजिस्टर है। ब्रह्मचारी कृष्णदत्त कब्रिस्तान को खत्म कर इसको हिंदुओं का तीर्थ बनाना चाहते हैं। मेरठ के बाद यह वाद 1997 में बागपत की अदालत में ट्रांसफर हो गया था। प्रतिवादी कृष्णदत्त की ओर से प्राचीन टीले पर शिव मंदिर और लाखामंडप होने का दावा करते हुए इसे महाभारत काल का लाक्षागृह बताया गया था। पांच फरवरी को सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम शिवम द्विवेदी ने प्राचीन टीले पर फैसला सुनाया, जिसमें प्राचीन टीले को महाभारत काल का लाक्षागृह ही माना है।

बागपत के बरनावा गांव में लाक्षागृह पर तैनात पुलिसकर्मी। जागरण

गुरुकुल परिसर में आचार्यों व छात्रों ने किया यज्ञ

श्री महानंद संस्कृत विद्यालय गुरुकुल परिसर में सुबह आचार्यों व छात्रों ने वेद मंत्रों के साथ यज्ञ किया और अदालत के फैसले को वैदिक संस्कृति की जीत बताया। गांधी धाम समिति के पदाधिकारी भी लाक्षागृह पहुंचे और लड्डू बांटकर खुशी मनाई।

प्राचीन टीले पर शेख बदरुद्दीन की दरगाह और कब्रिस्तान होने के तमाम साक्ष्य पेश किए, लेकिन फैसला हमारे पक्ष में नहीं आ सका। ऊपर की अदालत में इसे चुनौती देंगे।
- इरशाद खां, पक्षकार, मुस्लिम पक्ष

यह सत्य की जीत हुई है, यह महाभारतकालीन लाक्षागृह ही है। यदि कोई फैसले को चुनौती देता है तो हम ठोस साक्ष्यों के साथ पैरोकारी करेंगे।
- राजपाल त्यागी, पक्षकार, हिंदू पक्ष

कोविन्द से मिले विपक्षी नेता, एक देश, एक चुनाव का विरोध

- संसदीय लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने का छिपा हुआ एजेंडा : तृणमूल
- विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने लिखित रूप में अपने सुझाव भी सौंपे

नई दिल्ली, एएनआइ : विपक्षी दलों के नेताओं ने मंगलवार को 'एक देश, एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द से मुलाकात की। बाद में तृकां नेता कल्याण बनर्जी ने कहा, हमने पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष 'एक देश, एक चुनाव' के विचार का विरोध किया। हमें लगता है कि इस कदम के पीछे भारत को तानाशाही में बदलने का छिपा हुआ एजेंडा है। हमारे संवैधानिक प्रविधानों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए।

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, राज्यसभा के पूर्व सदस्य नीलोत्पल बसु ने भी उच्च स्तरीय समिति के साथ बैठक के बाद कहा, 'एक देश, एक चुनाव' संविधान की भावना के विपरीत है। यह लोकतंत्र और संघवाद विरोधी है। इस बीच सपा के प्रतिनिधियों केके श्रीवास्तव और डा. हरीश चंदर यादव ने भी कोविन्द को लिखित सुझाव दिया, जिसमें कहा गया कि 'एक देश, एक चुनाव' से राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा हो सकता है, जबकि राज्य स्तरीय पार्टियों को नुकसान होने की आशंका है। 'एक देश, एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति का गठन गत वर्ष सितंबर में किया गया था। समिति का उद्देश्य भारत के संविधान और अन्य वैधानिक प्रविधानों के तहत मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निकायों व पंचायतों के चुनाव साथ कराने के बारे में सिफारिश करना है।

कल्याण बनर्जी। फाइल

मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु

- सवा साल पुराने प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने दी स्वीकृति

राज्य ब्यूरो, भोपाल

मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। करीब सवा साल पुराने प्रस्ताव को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति दे दी गई है। यह प्रस्ताव जब तैयार किया गया था, उस समय शिवराज सरकार में डा. मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने आठ दिसंबर, 2022 को राजभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 100वीं बैठक में कुलपति का पदनाम कुलगुरु किए जाने का निर्देश दिया था। उस बैठक में डा. मोहन यादव भी उपस्थित थे। कुलाधिपति और राज्यपाल डा. मंगुभाई पटेल से मिली सहमति के बाद मोहन यादव ने शिवराज सरकार में भी प्रस्ताव स्वीकृत कराने के प्रयास किए थे, पर सहमति नहीं बन सकी थी। अब सीएम बनने के बाद मोहन यादव ने कैबिनेट में यह निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव। फाइल फोटो

विचारों की घर वापसी : द्विवेदी : भारतीय जन संचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने सरकार के निर्णय को सार्थक बदलाव बताया है। उन्होंने कहा, जिंदगी में शब्द की सत्ता बहुत बड़ी है। शब्द ब्रह्म है। हम जो बोलते हैं, वैसा ही बनते व अपेक्षा करते हैं। जो बदलाव इन दिनों शिक्षा और समाज में हो रहे हैं, उसे मैं 'विचारों की घर वापसी' मानता हूं। इससे कुलपति का पद गौरवान्वित होगा। विश्वविद्यालय ज्ञान परंपरा के केंद्र बनेंगे।

ईसाई धर्म की किताबें पढ़ाने का विरोध किया तो प्राचार्य को बना दिया शिक्षक

- मप्र में दमोह के पथरिया में गुड शेफर्ड स्कूल का मामला
- नैतिक शिक्षा की आड़ में दी जा रही थीं ईसाई धर्म की किताबें

नईदुनिया, दमोह

मध्य प्रदेश में दमोह जिले के गुड शेफर्ड स्कूल में बच्चों को नैतिक शिक्षा के नाम पर ईसाई धर्म की किताबें देने और पढ़ाने का प्राचार्य ने विरोध किया तो उन्हें पदावनत कर शिक्षक बना दिया गया। प्राचार्य रविशंकर भारती ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराई है।

आयोग ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देशित किया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर डीएम मयंक अग्रवाल ने जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) महेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में टीम बनाई और जांच के लिए स्कूल भेजा। इस दौरान स्कूल में 30 पुस्तकें बरामद की गईं, जो ईसाई धर्म से जुड़ी थीं। उन्हें जब्त कर लिया गया है। उधर, पथरिया के एकांत में संचालित स्कूल की बड़ी गड़बड़ी पकड़े जाने के दूसरे दिन भी प्रबंधन सामने नहीं आया। स्कूल की नई प्रभारी प्राचार्य शोभा रानी पिछले छह माह से स्कूल नहीं आ रही हैं। स्कूल में चार-पांच शिक्षक ही हैं। जांच दल के सवालों का जवाब देने से सभी बच रहे हैं।

अभी धर्मांतरण का मामला सामने नहीं आया : डीपीसी मुकेश द्विवेदी ने बताया कि स्कूल हैदराबाद की एक संस्था संचालित करती है। यहां 700 बच्चों का नामांकन है। पड़ताल में यह बात सामने आई है कि स्कूल के पुस्तकालय में पांच प्रकार की किताबें हैं, जो ईसाई धर्म से जुड़ी हैं। इनकी संख्या अधिक है। अभी धर्मांतरण का मामला सामने नहीं आया है। ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें बच्चों को क्यों दी गईं, यह जांच का विषय है।

छग में सरकारी भूमि पर बन रहे चर्च पर चला बुलडोजर

नईदुनिया, अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर किए जा रहे चर्च निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिले के गोधनपुर क्षेत्र में बन रहे चर्च पर प्रशासन ने मंगलवार को बुलडोजर चला दिया।

बताया जाता है कि कार्रवाई से पहले प्रशासन ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया था, लेकिन संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। इसके बाद प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा तो चर्च से जुड़े लोग विरोध करने लगे। लेकिन, प्रशासन ने पूरी कड़ाई के साथ उन्हें वहां से हटा दिया। बताया जा रहा है कि चर्च निर्माण को लेकर क्षेत्र में विरोध तेज होने लगा था। लोग कलेक्टर से शिकायत की तैयारी कर रहे थे। उससे पहले ही स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई कर दी।

एटीएस की पूछताछ के बाद भी सतेंद्र ने पूजा से किया था संपर्क

सुशील कुमार, मेरठ : मास्को स्थित भारतीय दूतावास में तैनात सतेंद्र सिवाल लगातार आइएसआइ एजेंट पूजा मेहरा के संपर्क में था। गिरफ्तारी से दो दिन पहले हापुड़ का सतेंद्र मेरठ में एक रिश्तेदारी में शादी में आया था। छह माह से उस पर नजर रख रही एटीएस ने उसे यहां से उठाकर पूछताछ की थी। इसके बाद छोड़ दिया था। इसके अगले दिन सतेंद्र ने फिर से पूजा से संपर्क किया और कई जानकारी साझा की थीं। इसके बाद ही एटीएस ने उसे मेरठ कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

जांच में पता चला कि सतेंद्र पूजा के अलावा भी कई अन्य जासूसों के संपर्क में था। पूजा ने ही सतेंद्र की उनसे दोस्ती कराई थी। छह माह से सेना इंटेलीजेंस व एटीएस सतेंद्र के खिलाफ सबूत जुटा रही थी। सतेंद्र को रिमांड पर लेने के लिए एटीएस ने कोर्ट में अर्जी लगाई है। रिमांड पर आने के बाद ही अन्य जानकारियां सामने आएंगी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक, सतेंद्र 2021 में पूजा के संपर्क में आ गया था। दोस्ती ऐसी थी कि पूजा को सतेंद्र ने शादी का प्रस्ताव भी दिया था।

****

12 वर्षों तक प्लास्टिक बबल में रहने के बाद बाहर आया डेविड

1984 में आज ही के दिन अमेरिका में 12 वर्षीय डेविड वेटर ने पहली बार अपनी मां को स्पर्श किया था। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बिना पैदा हुआ डेविड जन्म के बाद से ही रोगाणु-मुक्त प्लास्टिक बबल के भीतर रह रहा था। बाहर आने के दो सप्ताह बाद उसकी मृत्यु हो गई।

देश में बनी पहली सबमरीन आइएनएस शाल्की नेवी में शामिल हुई

1992 में आज ही के दिन स्वदेश में निर्मित पहली पनडुब्बी 'आइएनएस शाल्की' को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसका निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड ने किया था। आइएनएस शाल्की के जलावतरण के साथ, भारत पनडुब्बी निर्माण करने वाले देशों के विशिष्ट समूह का हिस्सा बन गया।

भोजपुरी फिल्मों के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं सुजीत कुमार

अभिनेता सुजीत कुमार का जन्म 1934 में आज ही के दिन वाराणसी में हुआ था। कालेज के दौरान अभिनय में रुचि जगी। 1963 में भोजपुरी फिल्म विदेसिया से बतौर अभिनेता अपनी शुरुआत की। 1965 में दूर गगन की छांव फिल्म से बालीवुड में डेब्यू किया। भोजपुरी की पहली रंगीन फिल्म दंगल ने उन्हें भोजपुरी फिल्मों का पहला सुपरस्टार बना दिया। आराधना, इत्तेफाक, रोटी, आंखें, मेरे जीवन साथी जैसी बालीवुड फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाकर अलग पहचान बनाई। पांच फरवरी, 2010 को उनका निधन हो गया।

तो अब शरीर के अंदर ही विकसित होंगे वाल्व

शोध ▶ विज्ञानियों ने हृदय के उपचार का नया तरीका ढूंढा, वाल्व रिप्लेसमेंट होगा वास्तविकता के करीब

शोध कम्युनिकेशंस बायोलाजी जर्नल में प्रकाशित

शरीर के अंदर विकसित होने वाले हृदय वाल्वों का रिप्लेसमेंट वास्तविकता के करीब एक कदम हो सकता है। इंपीरियल कालेज लंदन और यूके के हेयरफील्ड अस्पताल के शोधकर्ताओं ने हृदय के उपचार का एक नया तरीका विकसित किया है, जो शरीर में मौजूद प्राकृतिक मरम्मत तंत्र का उपयोग करता है।

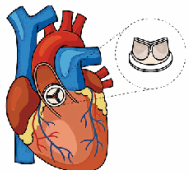

इंपीरियल के नेशनल हार्ट एंड लंग में काम करने वाले बायोमेटेरियल्स विज्ञानी डा. युआन-त्सान त्सेंग ने कहा कि हमने जो अवधारणा विकसित की है, उसका उद्देश्य शरीर में एक लाइव (स्वाभाविक) वाल्व का उत्पादन करना है, जो रोगी के साथ विकसित हो सकेगा।" हृदय वाल्व प्रतिस्थापन एक जीवन रक्षक उपचार है, लेकिन यह शायद ही कोई दीर्घकालिक समाधान है। यांत्रिक और जैविक दोनों वाल्वों की अपनी-अपनी कमियां हैं। मैकेनिकल वाल्व वाले मरीजों को रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए जीवन भर दवाएं लेनी पड़ती हैं। दूसरी ओर, जैविक वाल्व केवल 10 से 15 साल के बीच ही चलते हैं। जन्मजात हृदय दोष वाले बच्चों के लिए उपचार विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वाल्व उनके शरीर के साथ नहीं बढ़ते हैं और वयस्क होने से पहले उन्हें कई बार बदलना पड़ता है।

नई प्रक्रिया एक नैनोफाइबर पालिमरिक वाल्व से शुरू होती है, लेकिन टिकाऊ प्लास्टिक के बजाय बायोडिग्रेडेबल पालिमर से बनाई जाती है।" डा. त्सेंग ने बताया, 'एक बार जब यह शरीर के अंदर होता है, तो मचान कोशिकाओं को भर्ती करता है और उनके विकास का निर्देश देता है, ताकि शरीर नए ऊतकों को विकसित करने के लिए बायोरिएक्टर के रूप में काम करे।' 'मचान धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है और उसकी जगह हमारे शरीर के अपने ऊतक ले लेते हैं। वाल्व बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मचान सामग्री प्रमुख नवाचार है। 'इसमें रोगी के शरीर से उपयुक्त कोशिकाओं को आकर्षित करने, रखने और निर्देश देने की क्षमता है, जिससे ऊतक निर्माण और वाल्व कार्य को बनाए रखने में सुविधा होती है।' टीम ने वाल्व को भेड़ में प्रत्यारोपित किया और छह महीने तक निगरानी की। डा. त्सेंग ने कहा कि 'वाल्वों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। परीक्षण के छह महीनों तक काम करना जारी रखा और अच्छा सेलुलर पुनर्जनन भी दिखाया। हमने तंत्रिकाओं और वसायुक्त ऊतकों को मचान में बढ़ते हुए भी देखा है, जैसा कि सामान्य वाल्व में उम्मीद कर सकते हैं।' इस बीच, नए ऊतक के लिए रास्ता बनाने के लिए पालिमर को नष्ट होते देखा जा सकता है।

खून के प्रवाह को नियंत्रित करता है वाल्व। फाइल

अगले पांच सालों में उपलब्ध होगी बाजार में

डा. त्सेंग के अनुसार यदि कोई पुनर्जनन नहीं होता, तो पालिमर के क्षरण के कारण वाल्व टूट कर गिर जाता, लेकिन हम जो देखते हैं वह निरंतर कार्यक्षमता है। इसका मतलब है कि सेल पुनर्जनन समय के साथ हो रहा है। ह्यूमन ट्रायल और अनुमति के बाद यह तकनीक अगले पांच सालों में बाजार में उपलब्ध होगी।

एक्वेरियम में ड्रैगन डांस

आगामी 10 फरवरी से चंद्र नववर्ष आरंभ हो रहा है। इसको लेकर विभिन्न देशों में उल्लास छाया हुआ है। अनेक प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। मंगलवार को थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में 'सी लाइफ बैंकाक ओसियन वर्ल्ड' एक्वेरियम में डाइवर्स ने ड्रैगन डांस प्रस्तुत किया। जिसे ध्यानपूर्वक देखती बच्ची। रायटर

कोविड महामारी के दौरान कम वजन वाले बच्चों में 14% की वृद्धि

नई दिल्ली: कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य प्रणालियों में व्यवधान की वजह से कुपोषित बच्चों की संख्या में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लाक-डाउन ने उनकी पोषण स्थिति को प्रभावित किया। यह तथ्य तब सामने आया, जब नई दिल्ली में टाटा-कार्नेल इंस्टीट्यूट फार एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन (टीसीआइ) के शोधकर्ताओं ने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर महामारी से पहले और बाद के सर्वेक्षण डाटा का विश्लेषण किया। शोध इकोनामिक एंड पालिटिकल वीकली जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इनमें आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, मूल्य मुद्रास्फीति, काम की हानि और सरकारी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में रुकावट शामिल है।

कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य कीमतों में वृद्धि की वजह से महिलाओं की आहार विविधता में कमी आई। उन्हें पूर्ण मात्रा में पोषण नहीं मिला। टीसीआइ के निदेशक प्रोफेसर प्रभु पिंगली ने कहा, "शोधकर्ताओं को लंबे समय से संदेह था कि भारत की खाद्य प्रणालियों में महामारी से संबंधित व्यवधानों ने स्वस्थ, पौष्टिक आहार तक पहुंच को कम कर दिया है, खासकर सरकारी कार्यक्रमों पर निर्भर हाशिए पर रहने वाली आबादी इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। अध्ययन से इन बातों की पुष्टि होती है। इसमें मध्याह्न भोजन या आंगनवाड़ी योजना के तहत जो भोजन दिया जाता है, वह सबसे अहम है।

4 साल, यानी 2017 जून और जुलाई 2021 के बीच बिहार और ओडिशा का डाटा एकत्र किया

511 घरों से डाटा एकत्र कर की जांच, कम वजन वाले बच्चों की संख्या बढ़ी

2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ा, कोविड महामारी का प्रभाव

31% से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया कुपोषण

ओडिशा, बिहार सहित पांच राज्यों में सबसे ज्यादा कुपोषण। फाइल

अध्ययन से पता चलता है कि उम्र के हिसाब से बच्चे का वजन बिगड़ने के पीछे कई कारक थे।

- एकीकृत वाल विकास सेवाओं (आइसीडीएस) और पोषण के लिए अवसर (पोशन) प्रदान करने वाली भोजन योजना कम पहुंच शामिल है।
- सर्वेक्षण में शामिल कुछ बच्चों ने महामारी के दौरान वजन में सुधार का अनुभव किया। शोधकर्ताओं ने कहा कि उन बच्चों की आइसीडीएस तक पहुंच अधिक थी और उन्होंने 2017 की तुलना में 2021 में दालों और सब्जियों की खेती की।

सुझाव

- नीति निर्माता विविध, पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कृषि के विविधीकरण को प्रोत्साहित करें
- घरेलू उत्पादन में विविधता हो, यानी एक किसान परिवार द्वारा उगाई जाने वाली फसलों की संख्या में सुधार हो
- सेवाओं की भौतिक डिलीवरी मुश्किल होने पर सीधे नकद हस्तांतरण कैसे पर हो जोर
- भविष्य में बुनियादी मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाओं की बहाली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए
- मां का बाडी मास इंडेक्स (बीएमआइ) का बच्चे के वजन से सीधा जुड़ाव। यही वजह है कि दो साल तक के बच्चों पर असर पड़ा।

इधर-उधर की

..जब वर्जीनिया नदी में पानी की जगह बहने लगा दूध

वाशिंगटन, एजेंसी: अमेरिका की वर्जीनिया नदी में अचानक पानी की जगह दूध बहता देख आस-पास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने 911 पर काल कर इसकी जानकारी दी। लिंचबर्ग फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि लगभग पूरी तरह से सफेद रंग में बदल गई नदी देखकर हर कोई हैरान था। जांच करने पर पाया गया कि नदी ने दूध की वजह से रंग बदल दिया है। पता चला कि वेस्टओवर डेयरी संयंत्र से निकले अपशिष्ट दूध के कारण यह घटना हुई है। विभाग ने कहा कि संयंत्र में नाली की लाइन जाम होने के कारण दूध सीवर में बहकर नदी में चला गया। राज्य जल संसाधन विभाग ने बताया कि दूध से सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा नहीं है।

डेयरी संयंत्र से निकले दूध के कारण हुई घटना ● इंटरनेट मीडिया

अवसाद में अधिक रहता है शरीर का तापमान

अनुसंधान

अवसाद। फाइल

शोधकर्ताओं ने शरीर के तापमान और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध का पता लगाया है। विज्ञानियों ने अपने अध्ययन में पाया कि अवसादग्रस्त लोगों के शरीर का तापमान अधिक होता है। कहा, यह अध्ययन अवसादग्रस्त लोगों के शरीर का तापमान कम कर उपचार विकसित करने की दिशा में अहम सुझाव हो सकता है। हालांकि, अध्ययन में यह स्पष्ट नहीं है कि अवसाद के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है या अधिक तापमान अवसाद का कारण होता है। अध्ययन का निष्कर्ष साइंटिफिक रिपोर्ट जनरल में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एसोशिएट प्रोफेसर व अध्ययन के प्रमुख लेखक एशले मेसोन ने कहा है कि यह अध्ययन अवसाद को कैसे कम किया जाए, इस उपचार को विकसित करने पर प्रकाश डालता है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान 106 देशों के 20 हजार प्रतिभागियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिनके शरीर में तापमान मापने वाले उपकरण लगे थे। उन्होंने प्रतिदिन खुद शरीर के तापमान और अवसाद की स्थिति की रिपोर्ट दी। परिणाम से पता चला कि अवसाद के हर स्तर पर तापमान बढ़ा हुआ था। शरीर के तापमान के विश्लेषण से एक और प्रवृत्ति का पता चला कि अवसादग्रस्त लोगों के शरीर के तापमान में 24 घंटे में कम उतार चढ़ाव पाया गया। हालांकि अभी और शोध की जरूरत है। (आइएएनएस)

स्क्रीन शाट

अलग हुई ईशा और भरत की राहें

साल 2012 में ईशा और भरत बंधे थे शादी के बंधन में। (इंस्टाग्राम)@imeshadeol

कई बार सालों से जुड़े रिश्ते ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें एक मुकाम पर छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। अभिनेत्री ईशा देओल और बिजनेसमैन भरत तख्तानी ने भी अपनी शादी के 11 साल बाद अलग होने का फैसला ले लिया है। दो बेटियों की मां ईशा ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वह और भरत अब साथ नहीं हैं। ईशा ने कहा कि हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। हमारे जीवन में होने वाला यह बदलाव हमारे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। आप हमारी निजता का ध्यान रखें। दोनों के अलगाव के कारण क्या हैं, वह फिलहाल सामने नहीं आए हैं। पिछले साल ही जून में अपनी शादी की सालगिरह पर ईशा ने भरत के साथ कई तस्वीरें पोस्ट करते हुए शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी थीं। ईशा और भरत ने साल 2012 में एकदूसरे से शादी की थी। दोनों दो बेटियों छह साल की राध्या और चार साल की मिराया हैं। ईशा फिलहाल अपनी मां हेमा मालिनी के साथ रह रही हैं।

पोचर में दिखेगी हाथी दांत के अवैध कारोबार की कहानी

अब अभिनेत्रियां खुद को अभिनय तक सीमित नहीं रख रही हैं। वह अभिनय के साथ फिल्म निर्माण में भी दिलचस्पी ले रही हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी अभिनेत्री आलिया भट्ट ने पिछले साल डार्लिंग्स से फिल्म निर्माण में कदम रखा था। दैनिक जागरण साथ बातचीत में उन्होंने बताया था कि वह एक वेब सीरीज का निर्माण करने की प्रक्रिया में हैं। अब सीरीज को लेकर आधिकारिक घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आलिया पोचर सीरीज से बतौर कार्यकारी निर्माता जुड़ी हैं। इसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर दी। इस सीरीज का निर्देशन रिची मेहता करेंगे, जो इससे पहले डेल्ही क्राइम वेब सीरीज का निर्देशन करके सुर्खियां बटोर चुके हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित पोचर देश के इतिहास के सबसे बड़े अवैध कारोबार हाथी दांत की जानकारी देगा। मेहता द्वारा निर्मित, लिखित और निर्देशित इस सीरीज में निमिषा सजयन, रोशन मैथ्यू और दिव्येंदु भट्टाचार्य सहित अन्य कलाकार होंगे। पोचर 23 फरवरी से अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी, मलयालम और अंग्रेजी में उपलब्ध होगा। वहीं आलिया आगामी दिनों में संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वार में रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी।

शो से बतौर कार्यकारी निर्माता जुड़ी हैं आलिया भट्ट। फाइल

'दबंग' की दुनिया में हो सकती है एटली की एंट्री, हो चुकी है मुलाकात

भारत और मालदीव के बीच रिश्ते सही न होने के कारण अभिनेता सलमान खान की आगामी फिल्म द बुल की शूटिंग रुकी हुई है। उस वजह से अब वह अपनी बाकी की फिल्मों पर ध्यान दे रहे हैं। इस कड़ी में साल 2010 में प्रदर्शित फिल्म 'दबंग' में पुलिस अधिकारी की भूमिका में उन्हें खासी लोकप्रियता मिली थी। लोकप्रियता का आलम यह था कि उन्हें हिंदी सिनेमा का दबंग अभिनेता बुलाया जाने लगा। उसके बाद इस फिल्म की कहानी को दबंग 2 (2012) और दबंग 3 (2019) में आगे बढ़ाई गई। इस फ्रैंचाइजी की चौथी फिल्म दबंग 4 की चर्चा समय-समय पर होती रहती है। फिल्म के निर्माता और सलमान के भाई अरबाज खान दैनिक जागरण से बातचीत में स्पष्ट कर चुके हैं कि दबंग 4 की तैयारी चल रही है। अब खबरें हैं कि दबंग की इस दुनिया में फिल्म जवान के निर्देशक एटली कुमार जुड़ सकते हैं। इसके लिए सलमान और अरबाज की बातचीत एटली से चल रही है। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान और अरबाज की योजना दबंग की स्पिन आफ फिल्म बनाने की है। इसके लिए दोनों एटली से लगातार बात कर रहे हैं। इस सिलसिले में एटली की दोनों भाइयों से उनके मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में तीन-चार बार मुलाकात भी हो चुकी है। हालांकि, सलमान और एटली के बीच यह बातचीत फिल्म को निर्देशित करने के लिए नहीं हो रही है। सलमान चाहते हैं कि एटली उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी करने में मदद करें और रचनात्मक तौर पर फिल्म से जुड़े। हालांकि, अभी तक एटली ने इस फिल्म को स्वीकृति नहीं दी है।

फिर चुलबुल पांडे की भूमिका की तैयारी में हैं सलमान। फाइल

वेब सीरीज आर्या का चौथा सीजन भी आ सकता है लेकिन यह तीसरे सीजन की सफलता पर निर्भर करेगा। इसके आधार पर ही चीजें तय होंगी।

जनता की मांग पर कुछ भी हो सकता है

साल 2020 में प्रदर्शित हुई सुष्मिता सेन अभिनीत वेब सीरीज आर्या के अब तक तीन सीजन आ चुके हैं। तीसरे सीजन को निर्माता दो भाग में प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका पहला भाग पिछले साल आ चुका है, वहीं दूसरा भाग आर्या : अंतिम वार नौ फरवरी से डिज्नी प्लस हाटस्टार पर प्रदर्शित होगा। इसे शो का अंतिम सीजन माना जा रहा था, हालांकि शो के निर्देशक राम माधवानी ने इसके बाद अगले सीजन को लेकर भी संकेत दिया है। उनका कहना है, 'जो खत्म होता है, उसकी नई शुरुआत भी होती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हर रात की नई सुबह होती है। देखते हैं आगे क्या होता है..।' क्या इसके आगे भी कोई सीजन आ सकता है? इस पर राम कहते हैं, 'जनता की मांग पर कुछ भी हो सकता है। मैं पहले लोगों से यह कहना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने पहले के सीजन को प्यार दिया है, इस सीजन को भी प्यार दें। उम्मीद है कि यह सीजन भी पसंद आएगा।

वेब सीरीज आर्या के निर्देशक हैं राम माधवानी ● टीम राम

शो करना सुष्मिता का रिस्क था

इस शो को करने से पहले सुष्मिता करीब दस साल अभिनय से दूर रहीं। ऐसे में उनके साथ शो बनाने का जोखिम लेने को लेकर राम कहते हैं, 'मैं यह जानकर चकित रह जाता हूं कि लोगों को लगता है, मैं तय करूंगा कि सुष्मिता मेरा शो करेंगी। उनका शो करना मेरा नहीं, उनका रिस्क था। उन्होंने निर्णय लिया था कि वह 10 साल काम नहीं करेंगी। वो मुझे हां बोलेंगी या नहीं यह निर्णय उनके हाथों में था। जब मैंने सुष्मिता से पूछा था कि क्या आप यह रोल करोगी? तब मुझे अंदर से लगा था कि वो ना बोलेंगी। जब उन्होंने हां कहा तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगा कि हां, एक्टर हैं, झूठ बोलते रहते हैं। दो दिन बाद उनकी टीम से कोई आएगा और बोलेगा कि सारी उनका मूड नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि वह वर्षों से इस तरह के मौके का इंतजार कर रही थीं।'

सुष्मिता के लिए रखी थी ये शर्तें

भले ही आर्या के लिए सुष्मिता ने राम को अपनी स्वीकृति दी थी लेकिन राम ने शो करने से पहले सुष्मिता के लिए कुछ शर्तें भी रखी थीं। वह बताते हैं, 'मैंने बहुत साल पहले सुष्मिता के साथ एक विज्ञापन फिल्म की थी। मैंने मैं हूं ना, समय समेत उनकी कई फिल्में देखी हैं, तो मैं उनका एक तरह से फैन था। मुलाकात होने पर उन्हें बताया कि मैं अपने सेट पर तीन-चार कैमरों के साथ शूट करता हूं। मैं रिहर्सल नहीं वर्कशाप करता हूं। मैं 360 डिग्री में (चारों तरफ कैमरे लगाकर) शूट करता हूं। अगर आप इन चीजों के लिए तैयार हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं।'

एक और सीरीज पर चल रहा काम

2022 में प्रदर्शित फिल्म धमाका के बाद राम ने दूसरी फिल्म की घोषणा नहीं की है। आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में वह बताते हैं, 'मैं एक और सीरीज बना रहा हूं, उसका नाम है वेकिंग आफ द नेशन। फिलहाल हमारी नजरें उसे खत्म करने पर हैं। अभी उसकी एडिटिंग चल रही है। इसके अलावा एक फीचर फिल्म की भी स्क्रिप्ट है, जिस पर मैं काम कर रहा हूं। जब वो तैयार होगी, तब मैं उसके बारे में बात करूंगा।'

अभिनेत्री सुष्मिता सेन

रोमान के साथ शादी नहीं कर रही हैं सुष्मिता

अभिनेत्री सुष्मिता सेन को पिछले साल दिल का दौरा पड़ने के बाद से पूर्व ब्वायफ्रेंड रोमान शाह के साथ लगातार देखा जा रहा है। अपने से 15 साल छोटे रोमान के साथ वह अपनी तस्वीरें भी साझा करती हैं। ऐसे में उनकी शादी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। शादी की इन अटकलों को सुष्मिता ने खारिज किया है। पूर्व मिस यूनिवर्स ने एक इंटरव्यू में कहा, 'मुझे पता है कि पूरी दुनिया सोचती है कि मुझे कम से कम इस स्तर पर घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। मैं इसकी परवाह नहीं करती। मैं विवाह में यकीन करती हूं और उसका सम्मान करती हूं। आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करती हैं, लेकिन जब विश्वास करती हैं तो सौ खून माफ होते हैं।'

इमरान ने बताया कि क्यों हो गए थे वो फिल्मों से दूर

जल्द अभिनय में वापसी कर सकते हैं इमरान। (इंस्टाग्राम)@imrankhan

करीब आठ साल तक कैमरे से दूर रहने के बाद अभिनेता इमरान खान कैमरे के सामने वापसी करने को तैयार हैं। वह धीरे-धीरे इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। वह इंस्टाग्राम पर भी काफी सक्रिय हो गए हैं। वहां पर मिल रही प्रतिक्रियाओं से उन्हें समझ आ रहा है कि दर्शक उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में इमरान ने साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म कट्टी बट्टी के बाद फिल्मों से दूर होने की वजह बताई। एक साक्षात्कार में इमरान ने कहा कि साल 2016 में मैं अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। सौभाग्य से, मैं एक ऐसे उद्योग (फिल्म इंडस्ट्री) में काम कर रहा था, जिसने मुझे आर्थिक रूप से समृद्ध किया था। इसलिए जब मैं 30 वर्ष का हुआ, तो मुझे पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उस समय मैं करियर को लेकर इतना उत्साहित नहीं था कि उसके लिए कड़ी मेहनत करूं। धीरे-धीरे, जो कुछ भी आवश्यक नहीं था, वह रास्ते से किनारे करता गया। मैं उस वक्त पिता बना था। मैंने सोचा, यह ज्यादा मूल्यवान है। यह कुछ ऐसा है, जिसे मैं गंभीरता से लूंगा। मैं इमारा (इमरान की बेटी) के लिए खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना चाहता था। अचानक मेरा लक्ष्य बदल गया था। मैंने तय कर लिया कि अभिनेता बनना मेरा काम नहीं है। मुझे खुद को अपनी मेरी बेटी के लिए सबसे स्वस्थ और मजबूत रहना है। हालांकि इमरान किस फिल्म से वापसी कर रहे हैं उसे रहस्य बनाकर रखा है।

संदीप के साथ फिल्म नहीं करेंगी कंगना

कंगना ने एनिमल फिल्म पर दी थी तीखी प्रतिक्रिया ● मिडडे आर्काइव

यूं तो कलाकार अक्सर अच्छे काम की तलाश में रहते हैं। बात करें अभिनेत्री कंगना रनोट की, तो उन्होंने एनिमल फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा के साथ काम करने से मना कर दिया है। कंगना तब बिफर पड़ी, जब संदीप ने एक इंटरव्यू में कहा कि भले ही कंगना ने उनकी फिल्म एनिमल को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अगर कोई रोल हुआ, जिसमें वह फिट होती हैं, तो वह उन्हें फिल्म की कहानी सुनाना चाहेंगे। कंगना ने एक्स पर लिखा, 'समीक्षा और निंदा एक नहीं होते। संदीप जी ने जिस तरह से मेरी समीक्षा पर मेरे प्रति आदर का भाव दिखाया है, उससे ये कहा जा सकता है कि वो सिर्फ मर्दाना फिल्में ही नहीं बनाते हैं। उनके तेवर भी मर्दाना हैं। धन्यवाद सर। लेकिन कृपा करके मुझे कभी कोई रोल मत देना नहीं तो आपके अल्फा मेल हीरोज फेमिनिस्ट हो जाएंगे और फिर आपकी फिल्में भी पिट जाएंगी।'

स्मार्टफोन ने बदली पढ़ने की आदत

कोरोना काल के बाद माना जा रहा है कि जीवन में काफी बदलाव आया है। सिनेमा के लिए ओटीटी (ओवर द टाप) बड़ी चुनौती के तौर पर आया। हालांकि आमिर का मानना है कि बदलाव इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उनके मुताबिक कोरोना काल के बाद स्मार्टफोन की वजह से बहुत सारी चीजें बदली हैं। इनमें उनकी किताबों को पढ़ने की आदत भी बदली है। स्मार्टफोन के आने से पहले वह काफी पढ़ा करते थे, लेकिन अब उसमें 50 प्रतिशत की गिरावट आई है। साथ ही स्वीकारते हैं कि भले ही वह इंटरनेट मीडिया पर नहीं हैं, लेकिन हर खबर उन तक पहुंच जाती है। बहरहाल आमिर ने अपनी अगली फिल्म सितारे जमीं पर की शूटिंग शुरू कर दी है। 'रंग दे बसंती' अभिनेता बता चुके हैं कि इस फिल्म में दस प्रमुख किरदार हैं। सभी पात्रों में किसी न किसी प्रकार की कोई शारीरिक अक्षमता है। कोई सेरेब्रल पालसी, तो कोई डाउन सिंड्रोम, आटिज्म जैसी किसी बीमारी से ग्रसित है। यह सभी असल जिंदगी में इस बीमारी से ग्रसित हैं।

फिल्म सितारे जमीं पर की शूटिंग कर रहे हैं आमिर ● मिडडे आर्काइव

****